हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 2.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

28.3.2016/1400/av/as/1

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

डॉ0 राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय।

Speaker: Let's finish the Question Hour then I listen to you. क्या कहना चाहते हैं आप?

डॉ0 राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी और विपक्ष के सभी विधायकों ने नियम 67 के अंतर्गत समय रहते काम रोको प्रस्ताव की सूचना आपके कार्यालय में उपलब्ध करवा दी है। प्रदेश में एक गम्भीर मामला शुरू हुआ है जो लगातार चल रहा है और उसमें स्थिति निरंतर आगे बढ़ रही है।

Speaker: You can't make a statement like this. आपने अपने नोटिस में कुछ बातें रखी हैं और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। I have to speak. (---व्यवधान---) आपका जो नोटिस आया है, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं। (---व्यवधान---) आपने उसमें लिखा तो है और जो आपने उसमें लिखा है मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। You can't explain the things. -ऐसा है, जो नोटिस दिया है आप उसके बारे में ऐक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? आपने जो नोटिस दिया है उसका जवाब मुझे देना है। (---व्यवधान---) अब आपने यहां पर अपना विषय नहीं रखना है। आपने अपने नोटिस में विषय लिख तो दिया है। आप बैठ जाइए।

आज माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल जी और श्री महेन्द्र सिंह जी की ओर से नियम 67 के अंतर्गत कार्य स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ ई0डी0 द्वारा की गई कार्रवाई से सम्बंधित है। यह मामला मान्य न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन

नियम 69 और 70 के तहत इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। अतः मैं इस विषय को

28.3.2016/1400/av/as/2

अस्वीकार करता हूं। (---व्यवधान---) Your Notice has been rejected by me under Rule 69 and 70. यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि यह मामला मान्य न्यायालय में विचाराधीन है। अगर यह मामला न्यायालय में लम्बित है तो इसके बारे में सारी अखबारों में क्यों छप रहा है? हर रोज अखबारों में आ रहा है कि ई0डी0 द्वारा 7.8 करोड़ रुपये की (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट बैठ जाइए। यह मान्य न्यायालय की बात नहीं है। under Rule-70- No adjournment motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi judicial functions or any commission or Court of Enquiry appointed to enquire into or investigated any matter, shall ordinarily be permitted to be moved.

डॉ0 राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, जो मामला पब्लिक डिबेट का बन रहा है और उस पर हम डिबेट चाहते हैं, मुख्य मंत्री स्टेज से बोल रहे हैं तथा अखबार इस मामले को खबरों के रूप में कैरी कर रहे हैं।

टीसीद्वारा जारी

28.03.2016/1405/TCV/AS/1

डा0 राजीव बिंदल--- जारी।

सर, जो पब्लिक ग्रीवेंस का मामला है वह विधान सभा में क्यों डिस्कस नहीं हो सकता है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी यह मैटर कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में चला हुआ है। This matter is being inquired into by a statutory body.

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, यह मामला न्यायालय के अधीन नहीं है, अभी मामला न्यायालय के पास नहीं गया है।

Speaker: This is under purview of the statutory body and this is not a public matter. ये रूल्ज मेरे नहीं है यह रूल्ज तो विधान सभा के हैं और मैंने रूल्ज आपको पढ़कर बता दिए हैं It is a statutory body which is inquiring into the matter. This matter cannot be discussed when the law is taking its course. Why should we interfere. Let's the law take its own course.

Dr. Rajeev Bindal: Then why the discussion is going on all over the State. It is in the public domain, Sir.

Speaker: Now the question hour begins. Shri Yadvinder Goma.

प्रो प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, आपने नियम-70 का रैफरेंस दिया है और उसमें आपने स्वयं पढ़ा "ordinary discussion will not be allowed". Do you think it is ordinary condition now? It is extra ordinary situation now. ई0डी0 वालों ने सीटिंग मुख्य मंत्री की सम्पत्ति जब्त कर दी है। आपका जो नियम है और आपने पढ़ा है आपने कहा है Ordinarily Situation is extra ordinary, therefore, discussion should be allowed. मंच से भाषण हो रहे हैं, दूसरों पर आरोप लग रहे हैं कि वह इसकी साजिश रच रहे हैं तो चर्चा हाउस में क्यों नहीं ? जब इसके बारे में प्रैस लिख सकता है और मुख्य मंत्री पब्लिक प्लेस में बोल रहे थे इसलिए इस मान्य सदन में चर्चा होनी चाहिए ताकि सारे तथ्य सामने आएं। हमारे ऊपर आरोप लगाये जा रहे हैं कि ये इन्होंने (बी0जे0पी0) करवा दिया लेकिन

28.03.2016/1405/TCV/AS/2

यह मामला तब का है जब माननीय मुख्य मंत्री जी 2009 से 2012 में केन्द्र में मंत्री थे। यह केस यू0पी0ए0 सरकार के टाईम में दायर हुआ और उसका फॉलोअप ऐक्शन चल रहा है। आज इसमें साजिश कहां से आ गई, अगर एन0डी0ए0 सरकार ने करना होता तो सत्ता परिर्वतन के तुरन्त बाद ऐक्शन हुआ होता। एक नेचुरल कोर्स में यह चीज़ हो रही है और उसमें इस तरह का एस्केप रूट ढूढ़ना कि यह किसी और ने साजिश रची है। क्या यह संभव है कि हमने साजिश रची और प्रॉपर्टी इनकी बढ़ गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसमें चर्चा अलाऊ करिए और यह चर्चा आप एक्सट्राआर्डिनरी कंडीशन में आप अलॉऊ कर सकते हैं। उसी रूल्ज को कोट करके मैं कह रहा हूं under Rule-70, you please allow the discussion.

अध्यक्षः मेरा यह कहना है कि यह चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि यह विषय कोर्ट में पहले से ही चला हुआ है। Let the law take its own course हमारा इसमें कोई मतलब नहीं हैं। उसमें जब कोई फैसला आएगा उसके बाद देखेंगे। अभी तो यह चर्चा का विषय नहीं हैं। I can't take up the issue which is going in the court.

डा0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला पब्लिक डोमेन में हैं अगर इस सदन में इस बारे में चर्चा नहीं होगी तो यह चर्चा कहां पर होगी? आज यह चर्चा नितांत आवश्यक है। उसके बाद सरकार स्पष्टीकरण देगी। अध्यक्ष महोदय हमें आपका संरक्षण चाहिए। (-----व्यवधान----)

अध्यक्ष : मैं आपको एक बात बता दूं जो मामला कोर्ट में चला हुआ है उसका फैसला कोर्ट ने ही करना है उसका फैसला इस विधान सभा ने नहीं करना है। I will not allow. I won't allow this. I rejected this motion.

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister: The House is run by the

Rule and Procedure and conduct business of the House. It cannot be run at

28.03.2016/1405/TCV/AS/3

the mercy of someone from this side or that side. अब आपने रूलिंग दे दी है और उसके बाद माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन्ज में अलाऊ कर दे जबकि मैटर ऑलरेडी सब ज्यूडिस है।

श्री आर0के0एस0 --- द्वारा जारी ।

28.03.2016/1410/RKS/DC/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री....जारी

अगर यह मामला ई.डी. या किसी और एजेंसी के पास है तब भी इस मामले को डिस्कस नहीं किया जा सकता।

Sh. Suresh Bhardwaj: Enforcement Directorate is an investing agency, not a statutory agency.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अगर मामला डिस्कस नहीं हो सकता और अखबारों वाले लिख रहे हैं, बाहर डिबेट हो रही है तो यहां पर इस मामले को डिस्कस करके आप आगे क्या करना चाहते हैं? अगर आपके पास कोई तथ्य हैं तो आप उन तथ्यों को अखबार में छापने के लिए ले जा सकते हैं। जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी का सवाल है अभी तक सारे चैनल खुले हैं। इसके बाद अपील में जाएंगे, ई.डी. की अपील में जाएंगे। मारंग साहिब की कितनी प्रोपर्टी जब्त की है। ज्यूडिशियल प्रोसिजर है। प्रोसिजर को कट-शोर्ट नहीं किया जा सकता। माननीय अध्यक्ष जी इस हाऊस को नियमों के अनुसार चलाया जाए। प्रश्नकाल को चलाएं। उसके बाद चर्चा कर

सकते हैं।

अध्यक्षः एक मिनट बैठिए, जस्ट एक मिनट बैठिए, महेन्द्र सिंह जी एक सैकिंड बैठिए। जस्ट एक मिनट बैठिए। ऐसा है कि, I have rejected this Motion on the ground क्योंकि जो डिस्क्शन आप यहां करना चाहते हैं this will prejudice the proceedings which is going in the court of law. अब कोर्ट ऑफ लॉ की प्रोसिंडिंग को हम इफैक्ट नहीं करेंगे through the discussion of the Assembly. हम नहीं चाहेंगे कि जो डिस्कशन हम यहां पर करें वह प्रेज्यूडिश हो। Let the law takes its own course. यह मोशन रिजैक्ट हो गया है और इसके लिए हम कोई डिस्कशन अलौ नहीं करेंगे।

श्री राजीव बिंदलः सर, ई.डी. का मामला है।

Speaker: ED is a statutory body.आप बैठिए, आप बोलने दीजिए। आप बैठिए प्लीज। I can't not allow it if you all will speak at the same time. आप चुप रहिए। आप बैठिए

28.03.2016/1410/RKS/DC/2

प्लीज। Let him speak. He is not a child. पूछ रहे हैं। आप इशारा क्यों कर रहे हैं। आप बैठिए। . He knows it how to speak. सुरेश भारद्वाज जी आप बोलिए।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता और अन्य सदस्यों ने नियम-67 के अंतर्गत जो नोटिस दिया है, वह स्पेस्फिकली ई.डी. के बारे में है। Enforcement Directorate is not a statutory authority; it is not a Commission; it is not a quasi -judicial authority; and it is not a court. It is an investigating agency only which is investigating the matter. They have attached the property.

Speaker: ED is a statutory authority. Tribunal and ED are statutory bodies.

श्री एस.एल.एस द्वारा ....जारी

28.03.2016/1415/SLS-DC-1

Sh. Suresh Bhardwaj: Why it cannot be discussed in the House when it is being discussed throughout the country? It will be in the benefit of the Ruling Party also if they clear themselves from all the allegations and discuss it in the House .

Speaker: Let me Know who is discussing outside? Nobody is discussing it outside.

Sh. Suresh Bhardwaj: The Rule quoted by you is not relevant in this case because it is not a judicial authority; it is not a Commission; it is not a court but it is just an investigating agency only. And matter before any investigation agency, before any police station and before CBI it can be discussed in the House. Why it cannot be discussed in the House? We can even discuss the judicial matter also if it is in public interest. Why it cannot be discussed?

Speaker: Hon'ble Member I have not seen this matter being discussed outside the court. Who is discussing it outside? Only there is a coverage in the newspaper.

Sh. Suresh Bhardwaj: Sir, all the papers have published that the Enforcement Directorate has confiscated/attached the property belonging to Himachal Pradesh Chief Minister and his Family. It is all in papers.

Speaker: That is the procedure which has been taken by the ED and it is

still going on. Don't take law into your own hands? Let the court workout. This is not our concern. The ED is taking its own legal procedure and that's why they are doing it. It is not our question. There is no point of discussing it here. I have rejected this Motion and there will be no discussion on it. Please. No, not at all. I have rejected this Motion.

28.03.2016/1415/SLS-DC-2

प्रश्न काल आरंभ

प्रश्न संख्या : 2992

श्री यादविन्द्र गोमा : अध्यक्ष जी, जो 75 लाख रुपये की राशि इन्होंने स्वीकृत की है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि बस अड्डा निर्माण के लिए भूमि चयनित कर ली है। क्या यह वही भूमि है जो पिछली बार चयनित की गई थी या बस अड्डे के निर्माण के लिए यह भूमि नए सिरे से चिन्हित की गई है? अगर पिछली भूमि को ही इन्होंने स्थानांतरित किया है तो उसको स्थानांतरित करने के क्या कारण हैं?

(विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे।)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बस अड्डे की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैंने ही वर्ष 2007 में उसका फाऊंडेशन स्टोन रखा था। मैंने इनको कहा है कि मैं आपके साथ चलकर उस भूमि को देखूंगा। जो भी भूमि उपयुक्त होगी, वहीं पर बस स्टैंड बनाएंगे।

श्री यादविन्द्र सिंह गोमा: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि आप कब तक इसके लिए एक औपचारिक दौरा रखेंगे? मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस बस अड्डे के निर्माण हेतु जल्दी-से-जल्दी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद यह बस

अड्डा एक साल के भीतर बने क्योंकि सरकार को सत्तासीन हुए 3 साल हो चुके हैं और जयसिंहपुर उप-मंडल की यह बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहूंगा।?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : मानननीय अध्यक्ष जी, मैं दो महीने के भीतर-भीतर एम.एल.ए. साहब के साथ वहां जाऊंगा और हम स्पौट पर ही इसका निर्णय लेंगे। ...(व्यवधान)...

28.03.2016/1415/SLS-DC-3

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण ...(व्यवधान)... माननीय सदस्यगण ...(व्यवधान)... माननीय सदस्यगण ...(व्यवधान)... माननीय सदस्यगण, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। जो कानून कर रहा है, let the law takes its own course. जो कार्रवाई कानून के अंतर्गत चल रही है, उसको चलने दीजिए, उसको यहां चर्चा में मत लाइए।...(व्यवधान)...मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि जो कार्रवाई कानून के अंतर्गत चली है, उसमें सब-कुछ प्रोसीजर के अनुसार हो रहा है। नियम के अनुसार हम यहां उस पर चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए आप चर्चा के लिए इनसिस्ट न कीजिए। ...(व्यवधान)...

(विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे।)

28.03.2016/1415/SLS-DC-4

अध्यक्ष : अगला प्रश्न -2993 श्री विजय अग्निहोत्री जी। (Not interested)

28.03.2016/1415/SLS-DC-5

अगला प्रश्न-2994 श्री बम्बर ठाकुर (Not present)

28.03.2016/1415/SLS-DC-6

Question No-2995

Sh. Ravi Thakur: Hon'ble Speaker Sir, is Rohtang Tunnel land diversion case at North Portal towards Lahaul for quarry, mining and raw material being delayed and by when

Contd. By AG/RG.....

28032016/1420/RG-AG/1

Question No. 2995 Continues . . .

Shri Ravi Thakur Continues . .

the quarry diversion of land will be cleared ? How the construction of National Project of Defence and connectivity to tribal areas be completed without clearance of land diversion? Is the case pending with Principal CCF? Has Government of Himachal Pradesh approved and decided in Cabinet for approval of FCA for tribal areas of Lahaul & Spiti, Kinnaur and Bharmour and file is pending with His Excellency the Governor of Himachal Pradesh and has been sent to GOI vide letter dated 25.02.2016 from Secretary to His Excellency the Governor of Himachal Pradesh to Ministry of Home Affairs, Government of India?

Speaker: Hon'ble Member, are you asking a question or you are reading a statement? You can ask question only.

Chief Minister: Sir, the latest status of different tunnels is as under:
The work on Rohtang Tunnel is in progress and being executed by BRO. Till now, 8730 meters tunnel has been bored and work is likely to be completed by August, 2019.
Holi to Utrala:- M/s Benard Inginieure ZT GmbH, Austria has been appointed as Consultant for feasibility study and preparation of DPR on three tunnels, namely, Holi to Utrala, Bhubu Jot and Bangana to Dhaneta for Rs. 6.98 crores. The length of the proposed tunnel is 6 kms 905 meters and cost Rs. 1572/- crores (on year 2012 prices). This tunnel has not been found to be economically viable, hence DPR is not being prepared.
28032016/1420/RG-AG/2

Bhubu Jot Tunnel:- The Consultant has submitted final feasibility on 7th February, 2014. The draft DPR has been submitted on 13th November, 2015. The final DPR is awaited. The length of proposed tunnel is 3.16 kms and cost shall be Rs. 529/- crores (on year 2012 prices).
Bangana to Dhanetta:- The Consultant has submitted final feasibility report on 7th February, 2014. The draft DPR has been submitted on 8th July, 2015. The final DPR is awaited. The length of the tunnel shall be 1.265 kms and cost shall be Rs. 184/- crores (on year 2012 prices).
Jalori Jot Tunnel:- M/s Dhruv Services Private Limited, Mumbai has been appointed as Consultant by National Highway Wing for preparation of feasibility report and DPR of tunnel including 97 kms long National Highway from Sainj-Ani-Jalori-Banjar-Aut road. The DPR for total cost of Rs. 990/-

crores including cost of tunnel of Rs. 283 crores has been submitted to Ministry of Road Transport, Government of India during November, 2015. Approval is awaited.

So far the question of FRA is concerned, the matter does not arise at present. Once the tunnel project is approved then the necessary approval of FRA and other agencies will be taken.

Contd. By AG in English . . .

28/03/2016/1425/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः2995 क्रमागत ----

Shri Ravi Thakur: Speaker, Sir, I wanted to ask till when the approval of His Excellency the Governor of Himachal Pradesh be given for FCA clearances as it is being delayed for the quarry and mining and general development of tribal areas as Governor is custodian of tribal areas? Isn't the delay harming the development of tribal areas and denying their rights?

Chief Minister: Sir, this supplementary doesn't arise out this question. This question is about construction of tunnels. So far Forest Rights of Tribal are concerned, it is a separate issue. But I would like to tell the Hon'ble Member that this matter was approved by the Governor of Himachal Pradesh earlier. Some clarifications are required. I hope that the Hon'ble Governor will clear the file at the earliest.

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अंतर्गत रोहतांग में 8.8 किलोमीटर का टनल प्रस्तावित है और 7.30 किलोमीटर बन चुका है अर्थात एक किलोमीटर टनल का निर्माण शेष है। वह भी वर्ष 2019 में पूरा हो जाएगा,

ऐसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात इनके ध्यान में है कि जितना भी लाखों टन के हिसाब से मक वहां से निकल रहा है, उसको फेंकने की जो जगह बनाई गई है, उसको डम्पिंग यार्ड में डाला गया है। उससे यह खतरा उत्पन्न हो गया है कि जब ज्यादा वर्षा होगी तो सोलंगनाले में सब-का-सब बह जाएगा। इसलिए जब माननीय प्राक्कलन समिति वहां प्रवास पर गई थी तो हमने अधिकारियों को एक सुझाव दिया था कि इसको लैवलिंग कर दीजिए और जितना सरप्लस मक है, उसको दोनों नदियों के तटों पर फैंका जाए तथा वहां पर फ्लड प्रौटेक्शन वर्क लगाया जाए। इससे नदी का स्पेन भी कम हो जाएगा और जगह भी अच्छी बन जाएगी। क्या इस पर काम करने के लिए सरकार उनको निर्देश देगी? क्योंकि प्राक्कलन समिति के सुझाव को उन्होंने माना था। अन्यथा उस नाले को पागल

28/03/2016/1425/MS/AG/2

नाला कहते हैं। यदि किसी दिन ज्यादा पानी आया तो सारे-का-सारा मनाली बह सकता है। इसलिए समय रहते इस प्रकार का सुझाव क्या सरकार ग्रेफ वालों को देगी?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यह बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है और सरकार इस पर विचार करेगी।

अध्यक्षः माननीय धूमल जी कुछ बोलना चाहते हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, आप इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा अलाऊ कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर हम सदन में बैठना उचित नहीं समझते, हम सदन से वॉक आउट करेंगे।

अध्यक्षः मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि यह विधान सभा में चर्चा का विषय नहीं है। क्योंकि यह मामला पहले ही सब-ज्यूडिस है। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त जांच

चल रही है and our discussion will prejudicially affect the case which is going on. और जो केस चला है उसका परिणाम तो आना ही है then why should we discuss here? और जो यहां कह रहे थे कि कोई बाहर डिस्कशन हो रही है। अखबारों में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। (व्यवधान)--कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप लोग केस के बारे में, (व्यवधान)--मेरा आपसे निवेदन है कि we should adhere to the implications of the rules जो हमारे पास हैं और जो आप निष्कर्ष निकालना चाहते हैं वह निष्कर्ष तो कोर्ट में निकलेगा where the case is going on already. Why should we take the law in our own hands? ऐसा मेरा निवेदन है। बाकी आज आपके कटमोशन्ज भी हैं और बजट भी पास होना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी कार्यवाही चल रही है उसको चलने दीजिए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। बाकी मैं आपको कोई गलत थोड़े ही कह रहा हूं या बोलने के लिए मना कर रहा हूं। लेकिन यदि कोई चीज लॉ में परमिटिड नहीं है

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

28.03.2016/1430/जेएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः 2995ः--------जारी------

अध्यक्षः -----जारी--------

तो How can I permit. मैं परमिट नहीं कर सकता हूं। मैंने आपका 67 रिजैक्ट कर दिया है। let's now come to the Question Hour which is going on. एक बात और है, प्लीज़ सुनिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि When some of the Member is speaking please don't speak You don't want to hear your Member. Please let him speak. श्री सुरेश भारद्वाज जी आप बोलिए।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हमने नोटिस दिया है और विपक्ष इस पर चर्चा करना चाहता है। सारे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे

देश में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। अगर यह किसी रूल्ज़ के कारण, मैं समझता हूं कि जो यहां पर रूल्ज़ कोट किए गए हैं वे उचित नहीं हैं। इन्फोर्समैंट डॉयरैक्टरेट ने जो कार्रवाई की है वह किसी कमिशन, ज्युडिशियल अथोरिटी की कार्रवाई नहीं है। उस पर यहां डिस्कशन हो सकती है। अगर डिस्क्शन एलाऊ नहीं करते हैं तो हम सदन में बैठना उचित नहीं समझते इसलिए हम यहां से वॉकआऊट कर रहे हैं। __(व्यवधान)__

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से बर्हिगमन किया।)

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister (authorized): They don't want to face the Assembly. That is very unfortunate. The Leader of the Opposition is saying that we are going. The House is run by your directions and rulings and not by their rulings. अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने पहले इस केस के बारे में कहा है उसको भी एक्सपंज करिए, क्योंकि यहां पर बोल कर ये लोग अखबार को मसाला देते हैं।

Speaker: This matter is not to be discussed in this House.

28.03.2016/1430/जेएस/एएस/2

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister (authorized): Thank you very much, Sir.

Speaker: Then I have said that this is a quasi judicial body which is a statutory body established by the Central Government and proceeding of which cannot be discussed here. Let's go ahead with the question.

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि कुल्लू की तरफ से 15 किलोमीटर सड़क का निर्माण ठेके पर वर्ष 2012

दिया गया था और युद्धस्तर पर उसका काम हो रहा था। उसमें 9 करोड़ 65 लाख 80 हजार का काम हो चुका था। उसके बाद काम ढीला चल रहा था और मुख्य मंत्री जी के प्रवास के दौरान इसकी शिकायत हुई और यह ठेका रद्द हो गया। फलस्वरूप जो 3 किलोमीटर सड़क बाकी बननी है वह आज भी नहीं बन पाई है। विभाग ने उसमें इतना विलम्ब कर दिया कि उसकी रि-टेंडरिंग होनी थी और आज वर्ष होने को आ गया लेकिन अभी तक रि-टेंडिरिंग फाईनल नहीं हुई है। सारी सड़क जो बनी हुई है उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो छुटा हुआ काम है अगर उसी ठेकेदार को करने दिया जाता और पैनल्टी लगा कर आज तक पूरा भी हो जाता, लेकिन क्योंकि ठेका केंसिल हुआ है या तो जल्दी से जल्दी किसी नए ठेकेदार को काम दिया जाए ताकि सड़क का निर्माण टनल के मुंह तक पहुंच जाए, फिर वह सम्भव हो पाएगा जैसा कि आपने कहा कि टनल के लिए डी0पी0आर0 तैयार है और अब उसकी सारी डिटेल बना रहे हैं, उसकी डी0पी0आर0 बन रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि विभाग को निर्देश दिए जाएं कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को टेण्डर के आधार पर ठेके पर दिया जाए।

Chief Minister: This is a suggestion for action. Government will consider it.

28.03.2016/1430/जेएस/एएस/3

प्रश्न संख्याः 2996

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो गौ सदन है इसकी केपेसिटी 500 गाय की है। but at any given time लेकिन इसमें 100 से ज्यादा पशु नहीं होते हैं। उसकी वज़ह यह है कि there is lack of staff यहां पर total staff is about 6 people और 25 पशुओं के लिए एक आदमी उनको देख सकता है। दूसरे, इसमें ग्रीन चारे का प्रोविज़न नहीं है। यहां पर चारा नहीं आता। 53 केनाल में यह गौ सदन बना है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

28.03.2016/1435/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 2996 क्रमागत

श्री अजय महाजन क्रमागतः

It is probably the oldest Gau-sadan in the State. 1967 में इसके साथ 684 एकड़ ऑफ लैंड अटैच थे। In 1982 that land went back to the respective department. आज की डेट में 53 एकड़ में गौसदन तो बना हुआ है लेकिन वहां पर ग्रीन चारे के लिए साथ में जमीन नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो इसके लिए स्टाफ बढ़ाया जाए क्योंकि जब माननीय मुख्य मंत्री जी टूअर पर गये थे तो इन्होंने कहा था कि हम इसको स्टेट का एक आइडियल गौसदन बनायेंगे। Ideal ratio should be 25 animals under one staff member. 500 एनीमल के लिए यह अंडर स्टाफ्ड है। इसलिए इसका स्टाफ बढ़ाया जाए और जो जमीन 684 एकड़ 1982 में चली गई थी, वह वापिस आए। This should be ideal Gau-sadan और फिर इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें सिर्फ स्टाफ की ज़रूरत है और जमीन वापिस चाहिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने कहा, यह ठीक है कि विभाग के पास 52 कैनाल 8 मरले की जमीन है अैर 2007-2008 में हमने इसको अपग्रेड करने के लिए फंडस 1.700 करोड़ हिमुडा के माध्यम से उपलब्ध करवाये थे। इससे शैडस और स्टोर वगैरह बनाये गये थे। यह ठीक कहा कि हम किसी एनीमल को यहां लाने से इंकार नहीं करते। कोई एनीमल यहां लाया जाए तो उसके लिए हम पूरा प्रावधान करने का प्रयास करते हैं। आपने ठीक कहा कि अगर हमने 500 एनीमल्ज़ को रखना है तो उसके लिए हमें लगभग 25 अटैंडैंट चाहिएं। हम प्रयास करते हैं कि जितने एनीमल यहां आएं, उसके लिए वैटरिनरी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और अटैंडैंट सब उपलब्ध हों। आप फोडर के बारे में कह रहे हैं, फोडर में भी हम एनीमल वैल्फेयर बोर्ड से खर्चा करते रहते हैं। अभी पिछले साल लगभग 28 लाख रुपये का खर्चा

गौसदन में आया है। यदि हम इसमें 500 एनीमल्ज़ की कैपेसिटी की बात करते हैं तो एक करोड़ दस लाख रुपया साल का चाहिए और लगभग 25 क्लास-फोर की इसमें रिक्वायरमैंट है। हम प्रयास करते हैं कि जितने एनीमल यहां आएं, उसके लिए हम पूरा प्रावधान करते हैं। उसमें हम फोडर का भी पूरा प्रावधान करते हैं।

28.03.2016/1435/SS-AS/2

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह मान रहे हैं कि कम-से-कम 25 क्लास-फोर चाहिएं और साथ में यह भी कह रहे हैं कि हम किसी एनीमल को यहां लाने के लिए इंकार नहीं करते हैं। परन्तु जब यहां स्टाफ ही नहीं होगा तो वहां 90 से ज्यादा एनीमल आ ही नहीं सकते हैं। तो ज्यादा एनीमल का प्रावधान कैसे होगा? मैं इनसे आश्वासन चाहता हूं कि उसका स्टाफ बढ़ाया जाए। वह 500 एनीमल्ज़ के लिए 53 कैनाल में बनी हुई बिल्डिंग है, जब वहां स्टाफ ही पूरा नहीं होगा और ग्रीन चारा नहीं आयेगा तो यह एक सैल्फ-कंट्राडिक्टरी स्टेटमैंट लगती है। इसलिए या तो यहां स्टाफ बढ़ाएं तभी ज्यादा एनीमल वहां जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हम न नहीं करते जबकि दूसरी तरफ 90 के बाद एनीमल लेते ही नहीं हैं। At any given time it has not gone above the 100. थ्योरेटिकली तो स्ट्रैंथ है लेकिन वास्तव में 500 की स्ट्रैंथ नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसके लिए स्टाफ बढ़ाया जाए। साथ में ग्रीन चारा इनको नहीं मिलता है, एनीमल वहां पर भूखे मरते हैं। तूड़ी तो मिल जाती है लेकिन ग्रीन चारे का भी प्रावधान किया जाए। साथ में जो 637 एकड़ जगह थी जोकि 1982 तक इसके साथ थी, वह भी इनको ग्रेजिंग और चारे का उत्पादन करने के लिए वापिस मिल जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, सैल्फ-कंट्राडिक्टरी की कोई बात नहीं है। हमने कहा कि यदि 500 एनीमल हों तो हमें 25 अटैंडैंट का प्रावधान करना पड़ता है और हम लगातार 5 अटैंडैंट दूसरी जगह से ट्रांसफर करते रहे। जैसे ही एनीमल बढ़ जाते हैं तो हम 5 अटैंडैंट का प्रावधान दूसरी जगह से करते रहते हैं। जो आपने कहा, हमने लगभग 2012 में 300 मैनडेज़ घास की उपलब्धता के लिए किये थे जबकि हमारे पास उस समय 230 कैटल्ज़ थे। उसके बाद 350 मैनडेज़ जनरेट किये थे। यह लगातार प्रोसैस होता है जैसे-जैसे हमारे एनीमल

बढ़ते हैं हम आदमी रखने की कैपेसिटी को बढ़ाते जाते हैं। इसलिए वहां पर क्लास-फोर का इंतजाम साथ-साथ होता है। वैटरिनरी डॉक्टर्ज़ और फार्मासिस्ट साथ में रखे गये हैं और हमारी तरफ से यह प्रयास होता है कि जितने एनीमल्ज़ आएं उसके लिए उसी वक्त अटैंडैंट का प्रावधान करते हैं और फोडर के लिए एनीमल वैल्फेयर बोर्ड से पैसा देते रहते हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

28.03.2016/1440/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 2996 जारी---

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज तक 100 से ऊपर कितनी बार वहां पर एनिमल्ज़ आए हैं? वहां पर आज तक 6 का स्टाफ है जिनमें से एक डॉक्टर है, दो वैटरिनरी फार्मासिस्ट है, दो अटैंडैंट्स हैं और एक नाईट चौकीदार है। जैसे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि दूसरी जगह से ले कर आते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कितनी बार वहां पर आए हैं?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि वर्ष 2012 में हमारे पास 230 कैटल्ज़ आए थे। तो जैसे-जैसे एनिमल्ज़ आते हैं, उस हिसाब से हम स्टाफ बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे विभाग का काम यह नहीं है कि हम सड़क से पकड़ कर गौ सदन में मवेशी लाएं। जो गौ सदन में आएगा , उसको वहां रखने से हम इन्कार नहीं करते , हम यह कह रहे हैं। केपेसिटी के हिसाब से यदि वहां पशु आते हैं तो हम उनको लेने से कभी इन्कार नहीं करते और उस हिसाब से एनिमल वैल्फेयर बोर्ड से हम उनके चारे का प्रावधान भी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, कांगड़ा के अंदर आवारा पशु तो बहुत ज्यादा है । उन सब को पकड़ कर विभाग गौ सदन में नहीं लाएगा। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस गौ-सदन को चलाने का हमने भरसक प्रयास किया है और हमने इसमें और भी प्रावधान करने का प्रयास किया जब हाई कोर्ट की हमें इंस्ट्रक्शन्ज़

आई उसके बाद हमने पंचायत से भी बात की। पंचायत बॉडी उसको लेने को तैयार हो और पंचायत कम से कम उसको चलाए तो विभाग अपने स्तर पर उतना ही कर पाता है जितने एनिमल्ज़ उसके पास आएं। हमने एन.जी.ओ. को भी कहा। कुछ एन.जी.ओज़. आगे आए, उन्होंने उसको कुछ महीने चलाया उसके बाद छोड़कर चले गए। अभी हमारे पास जितने कैटल्ज़ आते हैं उनके लिए हम पूरा प्रावधान भी करते हैं और जितने चारे की जरूरत होती है, वह भी उपलब्ध करवाते हैं। आपने आदमियों की उपलब्धता की बात की, जैसे जरूरत पड़ती है, जब एनिमल्ज़ बढ़ जाते हैं, हम बाहर से उसके लिए भी प्रावधान करते हैं।

28.03.2016/1440/केएस/डीसी/2

Speaker: How can the Panchayat meet out the expenditure of the Gau-sadan?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जैसे हाई कोर्ट ने आदेश किए हैं कि हर पंचायत के अंदर गौ-सदन होने चाहिए और फिर माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि इस बात को भी देखा जा सकता है कि दो-चार पंचायतों को मिलाकर कहीं एक गौ सदन बनाया जाए।

Speaker: Who is meeting out the expenditure?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: एक्सपैंडिचर जो है, पंचायत में जैसे पिछली बार हाई कोर्ट का आदेश था, उन्होंने 13वें वित्तायोग को इस बात को कहा था कि आप इसमें फंड उपलब्ध करवाएं। अब 14वें वित्तायोग का जो है, उसमें गाईड लाईन में आ गया है कि सीधे तौर पर पंचायत अपने स्तर पर खर्चा कर सकती है। तो केवल हम पंचायतों को बाध्य नहीं कर सकते हैं और जैसे हाई कोर्ट की डायरैक्शन है उसमें हमने केवल पंचायतों को कहा कि इसके खर्च के लिए लोग उसमें पैसा दें या हमने जो स्ट्रे कैटल पॉलिसी बनाई है उसके माध्यम से भी और मंदिर ट्रस्ट से भी हम कुछ फंडज़

ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक साधारण सा आश्वासन चाहता हूं। इन्होंने इतना लम्बा चौड़ा जवाब दे दिया । मैं इतना आश्वासन चाहता हूं कि गौ सदन का 500 का प्रोविज़न है और उसके लिए 6 मैम्बर्ज़ रखे हुए हैं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि स्टाफ बढ़ा दिया जाए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं । मुझे सब कुछ समझा दिया गया परन्तु जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दिया गया।

28.03.2016/1440/केएस/डीसी/3

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को ठीक जवाब दिया कि जैसे-जैसे जानवर बढ़ते जाएंगें, स्टाफ बढ़ा दिया जाएगा। इससे ज्यादा क्या आश्वासन दूं। जब 500 की केपेसिटी है, 500 केपेसिटी पर हमें 25 अटैंडेंट रखने पड़ेंगें और जब ज्यादा ऐनिमल्ज़ आएंगें तो अटैंडेंट्स भी रखे जाएंगें। हमने कहा कि चारे का भी हम प्रावधान करेंगें। तो निर्भर करता है कि जितने स्ट्रे कैटल होंगें उसके हिसाब से हम आदमी रखेंगें।

अध्यक्षः माननीय सदस्य न आपकी बात मंत्री जी को समझ आ रही है और न मंत्री जी की बात आपको समझ आ रही है। अब आप क्या पूछना चाहते है?

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि 637 एकड़ जगह इसके साथ लग रही है, क्या उसको वापिस लेने का प्रयास किया जाएगा? दूसरा मैंने कहा कि 53 कनाल के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और आज की तारीख में वहां पर 98 एनिमल्ज़ हैं, मैं सिर्फ एक आश्वासन चाहता हूं कि जब वहां बिल्डिंग बनी हुई है और जिला कांगड़ा में वह सबसे बड़ा गौ सदन है, वहां पर 6 का स्टाफ है अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो वह प्रैक्टिकली युटिलाईज़ हो जाएगा।

अध्यक्षः मंत्री जी तो कह रहे हैं कि जैसे-जैसे एनिमल्ज़ की संख्या बढ़ती रहेगी हम

स्टाफ बढ़ाते रहेंगें।

श्री अजय महाजनः सर, यह तो वही बात हो गई कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। जब स्टाफ ही नहीं है तो एनिमल्ज़ कैसे आएंगें?

मंत्री जी अ0व0 द्वारा

28.3.2016/1445/av/डीसी/1

प्रश्न संख्या : 2996 -------------- क्रमागत

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि जैसे-जैसे जानवरों की संख्या बढ़ती जायेगी विभाग उस केपेसिटी के हिसाब से स्टाफ रखता जायेगा। अभी वहां पर सौ जानवर हैं और जैसे-जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी हम वहां पर अटेडैंट की संख्या बढ़ाते जायेंगे।

28.3.2016/1445/av/डीसी/2

प्रश्न संख्या : 2997

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखी गई सूचना से मैं संतुष्ट हूं। लेकिन मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बसों की अभी शॉर्टेज पड़ रही है उसको जल्दी-से-जल्दी पूरा किया जाये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने वहां पर जो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसें भेजी हैं वह खासकर रोहड़ू निर्वाचन क्षेत्र में सफल नहीं है, इसकी जगह आप भले ही छोटी बसें भेज दें। इसके अतिरिक्त वहां पर स्टाफ की कमी को भी शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की कृपा करें। मैं इन सबके बारे में आश्वासन चाहता हूं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वहां पर केवल एक बस की कमी है। वहां बेड़े के हिसाब से 115 बसें होनी चाहिए और वर्तमान में वहां

पर 114 बसें हैं। नई बसों के लिए टैंडर का प्रोसिजर चला हुआ है। उस टैंडर में पिछली बार एक ही पार्टी आई थी। अब हमने विभाग को फिर से टैंडर करने के आदेश दिए हैं। जैसे ही टैंडर हो जायेगा और उसके तहत नई बसें आना शुरू हो जायेगी क्योंकि अभी हमारी बातचीत चल रही है तथा बस कम्पनियों के पास कई जगह से ऑर्डर पड़े हुए हैं। प्रोटोटाइप बस के लिए ही वह दो महीने से ऊपर का समय मांग रहे हैं। जहां पर माननीय सदस्य को लगता है कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसें नहीं चल सकती तो जैसे-जैसे नई बसें आयेंगी वहां हम इनको छोटी बसों से चेंज करेंगे और कहीं पर भी बसों की कमी नहीं आने देंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है उसके अनुसार इन्होंने प्रदेश के सभी डिपोज में नई बसें दी हैं। लेकिन इसमें इन्होंने बस डिपो, नेरवा के लिए एक भी बस नहीं दर्शाई है। नेरवा डिपो माननीय मुख्य मंत्री जी और आपके सहयोग से खुला है उसके लिए आपने सभा पटल पर रखी गई सूचना के अनुसार एक भी नई बस नहीं दी है।

28.3.2016/1445/av/डीसी/3

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेरवा में भी सेम प्रोब्लम है। आपको अगर नीली बसें चाहिए तो मैं भिजवाता हूं। हमने डेढ़ सौ के करीब छोटी बसें लेने के लिए टैंडर प्रक्रिया शुरू की है। जैसे ही बसें आती हैं उनको हम ओल्ड हिमाचल के एरिया में जहां पर केवल छोटी बसें चल सकती हैं वहां के लिए प्राथमिकता के आधार पर बसें देंगे। आपको उसमें से कम-से-कम दस बसें देंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। अभी मंत्री जी तो यह कह कर टाल रहे थे कि केवल रोहड़ू तक सीमित है जबकि इसमें पूरे प्रदेश की सूचना दी गई है। जो सूचना दी गई है इसमें भी बहुत कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें लिखा है कि कुल्लू डिपो को आपने पिछले तीन वर्षों में 62 बसें दी। इसके अगले कॉलम में लिखा है कि 23

बसों की बुक वैल्यु जीरो है तथा 9 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली बसों की संख्या 8 हैं। इससे यह समझ नहीं आ रहा है कि कुल कितनी बसें दी हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि कुछ दिन पूर्व आपकी एक स्टेटमैंट आई कि जितनी भी बसें अपनी आयु सीमा पूर्ण कर चुकी हैं उनको धीरे-धीरे निकाल दिया जायेगा तथा बदले में दूसरी बसें देंगे। आपने गणतंत्र दिवस पर घोषणा की थी कि हम मलाना के लिए बस चला देंगे। नई बसें आई-गई, घटती गई मगर वह बस आज भी बंद पड़ी है। आपने कहा कि बंजार होकर जलोड़ीजोत-शिमला बस चलायेंगे। मगर वह आज दिन तक नहीं चली। बंजार की हालत यह है कि वहां पर बस का सब-डिपो भी नहीं है केवल कुल्लू बस डिपो है। वह ओवर लोडिड है और वहां से बाकी बसों के जो डिपोज हैं उस ज्युरिसडिक्शन को बसें जाती है। आपने यह आश्वासन दिया कि यह समस्या है इसके हल के लिए जो बाकी सम्बंधित डिपोज हैं जिनकी ज्युरिसडिक्शन में वह बसें चलाई जायेंगी। कुल्लू को और बसें दे दी जायेंगी आपका काम चल पड़ेगा।

टीसीद्वारा जारी

28.03.2016/1450/TCV/AG/1

प्रश्न संख्याः 2997---- क्रमागत

श्री महेश्वर सिंह ---- जारी

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इसकी फैक्चुअर पॉजिशन क्या है? कुल्लू में कितनी बसें हैं, कितनी शॉर्टेज़ हैं और कितनी आपने लॉ फ्लोरिंग वाली बसें दी है? कितनी बसें ऐसी हैं जो छोटी सड़कों में जाने वाली हैं?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां कुल 148 बसों की सट्रैंथ हैं जिसमें से हमने 3 वर्षों में 62 बसें दे दी है और सारी बसें संतुष्टी से चल रही है। जहां तक इन्होंने शुन्य वैल्यू बसों की बात की है वह छोटे वाली बसें हैं। मैं यह बात बार-बार कह रहा हूं कि हमने टैण्डर कर दिया है। हम 1300 +300

नई बसें डाल चुकें हैं और भी नई बसें ले रहे हैं। अगर पिछले पांच वर्षों में कुछ नहीं हुआ है तो उसका जिम्मा इस सरकार पर मत डालिए, वे आपके पुराने सहयोगी थे जो चले गये है। लेकिन जैसी व्यवस्था बंजार, रोहडू और चौपाल में हैं जैसे ही बसें आएगीं कुल्लू को भी दे दी जाएगी । जो पुरानी बसें हैं उनको हम फेस्ड मैनर्ज में चैंज कर रहे हैं।

28.03.2016/1450/TCV/AG/2

प्रश्न संख्याः 2998

श्री सुरेश कुमारः (अनुपस्थित)

28.03.2016/1450/TCV/AG/3

प्रश्न संख्याः 2999

श्री ईश्वर दास धीमानः (अनुपस्थित)

28.03.2016/1450/TCV/AG/4

प्रश्न संख्याः 3000

श्री मनोहर धीमानः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है मैं इससे सहमत हूं । इसमें बताया गया है कि वहां कोई कोर्ट केस चला हुआ है। मैंने पिछले सत्र में भी यह प्रश्न यहां पर उठाया था तो आपने आश्वासन दिया था कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता तब तक इंदौरा में कोई सब काऊंटर विभाग की तरफ से खोला दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि क्या इंदौरा में सब काऊंटर खोला जाएगा? क्योंकि लोगों को गैस लेने के लिए 40-40 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है क्योंकि जो गैस ऐजैंसी डमटाल में है वह एक

कॉर्नर में है। मैं चाहता हूं कि इन्दौरा जो तहसील हैड क्वार्टर है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है, वहां पर विभाग द्वारा तब तक कोई सब काऊंटर खोला जाए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय काऊंटर की बात तो नहीं कह सकता हूं पर उनको फैस्लिीटेट जरूर करेंगे। उनके लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। आप अभी थोड़ी देर में मेरे चैम्बर में आना, बातचीत करके उनके लिए कोई न कोई समाधान निकालेंगे।

28.03.2016/1450/TCV/AG/5

प्रश्न संख्याः 3001

श्री जय राम ठाकुरः (अनुपस्थित)

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो मेरा चुनाव क्षेत्र चौपाल है उसमें लोक निर्माण विभाग के पास मशीनरी की कमी है। मेरा क्षेत्र बहुत ही हार्ड एरिया है और वहां एयर कंप्रैशर एक ही है और बल्डोजर/जे0सी0बी0/रोलर/टिपर भी कम है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में हाल ही में बहुत सारी सड़कें पी0एम0जी0एस0वाई0/नाबार्ड से बनी है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्वयं एक साल पहले ही उसकी इनोग्रेशन की थी। मेरे क्षेत्र में 3 साल के अन्दर 200 किलोमीटर से ऊपर नई सड़कें बनी है और जनता को समर्पित हुई है। हमारे क्षेत्र में जैसे ही बरसात होती है उस समय स्लिप रिमूवर और वर्फ को हटाने के लिए मशीनें बहुत कम है मैं माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि मुझे जे0सी0बी0,बुलडोज़र

श्री आर0के0एस0 ---- द्वारा जारी ।

28.03.2016/1455/RKS/AG/1

प्रश्न संख्याः 3001..जारी

श्री बलबीर सिंह वर्मा ...जारी

और कंप्रेशर ये 2-3 मशीनरियां जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएंगे तो चौपाल की सड़कें जो बरसात और बर्फ में बंद रहती हैं, कभी भी बंद नहीं रहेगी।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में किस डिविजन में कितनी मशीनरी है उसका विस्तृत ब्योरा दिया है। जो पिछड़े क्षेत्र हैं, मुश्किल इलाके हैं वहां की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो मशीनरी वहां चाहिए उसे दिया जाए। सरकार आगे नई मशीनरी एक्वायर करेगी और उसमें से जो-जो मशीनरी चाहे बूलडोजर हो, चाहे कोई और चीज, पीक अप या वैन हो हम उन क्षेत्रों में भेजेंगे, जहां उनकी आवश्यकता होगी।

28.03.2016/1455/RKS/AG/2

प्रश्न संख्याः 3002

श्री किरनेश जंगः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है कि बस अड्डा पांवटा साहिब का निर्माण कार्य पी.पी.पी. आधार पर किया जाएगा मैं उससे सहमत हूं। पांवटा क्षेत्र एक धार्मिक स्थल है। जहां प्रदेश या देश से ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग गुरु के दर माथा टेकने के लिए आते हैं। यहां के बस स्टैंड की हालत बहुत बुरी है। जहां लोगों को खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस बस स्टैंड का निर्माण कार्य 2-3 महीनों में शुरू हो जाएगा या नहीं?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी को पता है कि मैं इस कार्य का जायजा लेने के लिए स्वयं वहां गया था। वहां पर

एनक्रोचमेंट हुई है और उसी समय एनक्रोचमेंट को खाली करने के लिए मैंने आदेश दिए थे। पी.पी.पी. आधार पर तभी कार्य होगा जब हम उन लोगों को जगह क्लीयर देंगे। अगर हम पी.पी.पी. वालों को यह जगह दे दें और आगे कोई स्टे लेकर आ जाए तो बस अड्डे का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। हम इस कार्य को प्रायोरटी में कर रहे हैं। मैंने पिछली वर्ष के बजाय इस बर्ष 2015-16 में भी इस कार्य के लिए 70 लाख रुपए अलग से दिए हैं। पी.पी.पी. में पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार में नीति और नियत में कोई अंतर नहीं है। **आपके बस अड्डे को बनाने की हमारी पूरी प्रायोरटी है और इस बस अड्डे का निर्माण हम प्रायोरटी में करेंगे।**

अध्यक्षः किरनेश जंगी जी आप क्या बोलना चाहते हैं, आप बोलिए।

श्री किरनेश जंगः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने वहां पर एनक्रोचमेंट की है हमने उनसे बात कर ली है। वे लोग जगह खाली कर देंगे। हमने उन लोगों से यह भी वायदा किया है कि जो पहली मंजिल बनेगी उनको वहां पर दुकान दे दी जाएगी। मैं आपसे आग्रह करुंगा कि आप इस बस अड्डे को जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करें, उस जगह को खाली कर दिया जाएगा।

28.03.2016/1455/RKS/AG/3

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, इस कार्य को न तो विधायक जी तय करेंगे और न मैं तय करुंगा। यह कार्य जिस पी.पी.पी. वाले को मिलेगा वह ही तय करेगा। अगर मैं उन लोगों को बोल दूं कि पहली मंजिल आपको दी जाएगी तो पी.पी.पी. वाला वहां कोई नहीं आएगा। इसका फैसला तो जो कांट्रैक्टर पैसे लगाएगा वह करेगा।

28.03.2016/1455/RKS/AG/4

प्रश्न संख्या : 3003

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है यह तथ्यों से परे है।

श्री एस.एल.एस द्वारा ....जारी

28.03.2016/1500/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 3003 ...जारी

श्रीमती आशा कुमारी ...जारी

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह प्रश्न लगाया था। उसमें वन विभाग की ओर से सैटिस्फैक्टरी उत्तर न आने के कारण ही मैंने इस बार यह प्रश्न लोक निर्माण विभाग के लिए लगाया है। यह सड़क 1960 के दसक में बनी है। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि डी.एफ.ओ. की स्टेटमैंट मायने रखती है या रैवन्यु रिकॉर्ड मायने रखता है? रैवन्यु रिकॉर्ड में 1960 के दसक से ही इसमें 9 करम का रास्ता है। किस विभाग ने बनाया, किस विभाग ने नहीं बनाया, इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन सलूणी का फोरैस्ट डिविजन 1985 के बाद स्थापित हुआ है। इनके पास 1980 के पहले का रिकॉर्ड ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या रैवन्यु रिकॉर्ड सही होता है या डी.एफ.ओ. की स्टेटमैंट सही रिकॉर्ड है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि **सलूणी में डी.एफ.ओ. का दफतर हाल ही में बना है; कुछ वर्ष पहले ही बना है। क्योंकि सलूणी में डी.एफ.ओ. ऑफिस बाद में बना है इसलिए अगर रैवन्यु रिकॉर्ड में वह बात दर्ज़ है तो रैवन्यु रिकॉर्ड को ही प्राथमिकता दी जाएगी।**

प्रश्न काल समाप्त

28.03.2016/1500/SLS-AS-2

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत कराएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार से है :-

सोमवार 28 मार्च, 2016 1-शासकीय एवं विधायी कार्य।
2-बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2016-17 - मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

मंगलवार 29 मार्च, 2016 1-शासकीय एवं विधायी कार्य।
2-बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2016-17 - मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

बुद्धवार 30 मार्च, 2016 1-शासकीय एवं विधायी कार्य।
2-बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2016-17 - मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

वीरवार 31 मार्च, 2016 1-शासकीय/विधायी कार्य एवं बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2016-17
2-मांगों पर चर्चा एवं मतदान और विनियोग विधेयक पुरःस्थापना, विचार-विमर्श एवं पारण।

शुक्रवार 01 अप्रैल, 2016 1-शासकीय एवं विधायी कार्य।

28.03.2016/1500/SLS-AS-3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब कागज़ात सभापटल पर रखे जाएंगे।
अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास निगम सीमित का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मंत्री की ओर से माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

आबकारी एवं कराधान मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अनुसूची-1 में, मद संख्या 22 में संशोधन बारे अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ0(18)-2/2001 दिनांक 22.06.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.06.2015 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

28.03.2016/1500/SLS-AS-4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत होंगे।

अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं :-

i. समिति का 137वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा श्रम एवं रोजगार विभाग से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का 138वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा मत्स्य पालन विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री खूब राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति कल्याण समिति (वर्ष 2015-16), समिति का 25वां प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः19 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत महिला विकास एवं बाल विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं।

अगली मद ...गर्ग जी

28/03/2016/1505/RG/AS/1

अध्यक्ष : अब श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन-प्रशासन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का **23वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:21 के अन्तर्गत **सहकारिता विभाग** की वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और
ii. समिति का **24वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:22 के अन्तर्गत **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग** की वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है ।

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक सभा प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति का **19वां प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:27 श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण के अन्तर्गत **तकनीकी शिक्षा विभाग** की वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति के प्रतिवेदनों की की एक-एक सभा प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति का **17वां प्रतिवेदन** (बारहवीं

28/03/2016/1505/RG/AS/2

विधान सभा) जोकि मांग संख्याः26 के अन्तर्गत **पर्यटन एवं नागर विमानन विभाग** की वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा तथा सदन के पटल पर रखती हूं :-

(i) समिति का **21वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः11 के अन्तर्गत **कृषि विभाग** की वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का **22वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः12 के अन्तर्गत **उद्यान विभाग** की वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है ।

28/03/2016/1505/RG/AS/3

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का

प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान होगा। अब वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान होगा। सभा का समय बचाने के लिए, मैं माननीय मुख्य मंत्री जिनके पास वित्त विभाग भी है, की ओर से सभी मांगों को सभा में प्रस्तुत हुआ समझता हूं जो इस प्रकार है :-

मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा दत्तमत
1	**2**		**3**
1	विधान सभा	(राजस्व)	26,43,32,000
		(पूंजी)	3,10,00,000
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद्	(राजस्व)	11,06,39,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	1,37,41,51,000
		(पूंजी)	7,95,01,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	1,67,97,12,000
		(पूंजी)	5,00,00,000
5	भू-राजस्व व जिला प्रशासन	(राजस्व)	6,32,46,71,000
		(पूंजी)	10,00,00,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	59,86,29,000
		(पूंजी)	1,50,00,000
7	पुलिस और सम्बध्द संगठन	(राजस्व)	9,17,88,64,000
		(पूंजी)	54,87,00,000

28/03/2016/1505/RG/AS/4

8	शिक्षा	(राजस्व)	52,62,90,86,000
		(पूंजी)	82,18,63,000
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	(राजस्व)	16,18,39,36,000
		(पूंजी)	53,26,50,000
10	लोक निर्माण- सड़क, पुल एवं भवन	(राजस्व)	27,94,29,62,000
		(पूंजी)	8,75,86,56,000
11	कृषि	(राजस्व)	3,51,38,26,000
		(पूंजी)	56,82,36,000
12	उद्यान	(राजस्व)	2,09,83,29,000
		(पूंजी)	14,21,55,000
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	(राजस्व)	22,61,32,75,000
		(पूंजी)	5,39,30,83,000
14	पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	(राजस्व)	3,13,76,91,000
		(पूंजी)	3,84,09,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	(राजस्व)	83,14,55,000
		(पूंजी)	2,04,11,00,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	4,54,47,74,000
		(पूंजी)	8,40,00,000
17	निर्वाचन	(राजस्व)	18,85,51,000
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	(राजस्व)	1,08,22,08,000
		(पूंजी)	48,35,01,000
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	(राजस्व)	6,65,47,80,000
		(पूंजी)	13,70,01,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	12,18,40,58,000
		(पूंजी)	1,84,00,000
21	सहकारिता	(राजस्व)	34,31,27,000

22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	(राजस्व)	2,36,42,98,000
		(पूंजी)	1,96,03,000
28/03/2016/1505/RG/AS/5			
23	विद्युत विकास	(राजस्व)	4,75,86,73,000
		(पूंजी)	4,07,08,01,000
24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	(राजस्व)	29,45,13,000
25	सड़क और जल परिवहन	(राजस्व)	2,19,22,85,000
		(पूंजी)	45,95,00,000
26	पर्यटन और नागर विमानन	(राजस्व)	48,64,76,000
		(पूंजी)	3,60,00,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	(राजस्व)	2,41,22,77,000
		(पूंजी)	58,72,01,000
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्रामयोजना तथा	(राजस्व)	2,61,42,31,000
	आवास	(पूंजी)	23,83,00,000
29	वित्त	(राजस्व)	42,81,54,78,000
		(पूंजी)	12,07,50,000
30	विविध सामान्य सेवाएं	(राजस्व)	84,57,34,000
		(पूंजी)	34,59,00,000
31	जनजातीय विकास	(राजस्व)	10,33,36,85,000
		(पूंजी)	2,73,82,10,000
32	अनुसूचित जाति उप-योजना	(राजस्व)	11,26,06,01,000
		(पूंजी)	8,23,08,50,000
	जोड़	**(राजस्व)**	**2,53,85,73,07,000**
		(पूंजी)	**36,69,03,70,000**
		कुल जोड़	**2,90,54,76,77,000**

28/03/2016/1505/RG/AS/6

विपक्ष की ओर से अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु प्रार्थनाओं का जो क्रम प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप मैं उनको सभा में चर्चा एवं मतदान हेतु रखूंगा। इससे पूर्व कि अनुदान मांगों पर चर्चा आरम्भ हो, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अपनी-अपनी बात संक्षेप में रखें और उसी विषय पर वे बोलें ताकि ज्यादा-से-ज्यादा अनुदान मांगों पर विचार हो सके। अब सर्वप्रथम मैं मांग संख्या-10 'लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन' को चर्चा एवं मतदान के लिए लेता हूं। तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-10, 'लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन' के अन्तर्गत राजस्व एवं पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम-3 में दर्शाई गई धनराशियां क्रमशः 27,94,29,62,000/-रुपये(राजस्व) एवं 8,75,86,56,000/रुपये(पूंजी) संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

इस मांग पर **सर्वश्री महेन्द्र सिंह, श्री रिखी राम कौंडल, श्री इन्द्र सिंह, श्री विजय अग्निहोत्री, श्री बिक्रम सिंह, श्री जय राम ठाकुर, श्री महेश्वर सिंह, श्री सुरेश भारद्वाज, श्री रविन्द्र सिंह, डॉ0 राजीव बिन्दल, डॉ0 राजीव सैज़ल, श्री कृष्ण लाल ठाकुर** की ओर से तीन कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या वे इन्हें प्रस्तुत करना चाहेंगे या उनकी ओर से मैं प्रस्तुत हुआ समझूं?

सदस्यगण : प्रस्तुत हुए समझे जाएं।

अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए जो इस प्रकार से हैं :-

28/03/2016/1505/RG/AS/7

<u>मांग संख्याः 10 -लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन</u>

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या

<u>**नीति का अननुमोदन**</u> **10**

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

"लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन"

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,

श्री ईश्वर दास धीमान,

श्री रिखी राम कौंडल,

श्री इन्द्र सिंह,

श्री विजय अग्निहोत्री,

श्री बिक्रम सिंह,

श्री जय राम ठाकुर,

श्री महेश्वर सिंह,

28/03/2016/1505/RG/AS/8

श्री सुरेश भारद्वाज,

श्री रविन्द्र सिंह,

डॉ0 राजीव बिन्दल,

डॉ0 राजीव सैज़ल,

श्री कृष्ण लाल ठाकुर ।

1. **सरकार की सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।**
2. **सरकार की मशीनरी तथा उपकरण क्रय एवं आबंटन की नीति का अननुमोदन ।**
3. **सरकार की जिला तथा अन्य सड़कों से जोड़ने की नीति का अननुमोदन ।**

मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध हैं।
अब श्री महेन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-10-'लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन' पर जो कटौती प्रस्ताव हमने दिए हैं, इसी सदन में दिनांक 8 मार्च, 2016 को प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2016-17 का बजट प्रस्तुत किया था।

एम.एस. द्वारा जारी

28/03/2016/1510/MS/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी-------

उस पर चर्चा होने के साथ-साथ हमने जो कमियां/त्रुटियां/विसंगतियां इसमें पाई हैं, उसी पर मैं आपके आदेशों के मुताबिक बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, इस वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट की जब हमने वर्ष 2015-16 के बजट के साथ तुलना की तो लोक निर्माण विभाग के अंदर जो बजट पिछले वर्ष 2015-16 के लिए केन्द्रीय जोन मण्डी और हमीरपुर को दिया गया था,

क्योंकि मैंने जब उन आंकड़ों को देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्या कारण है कि मण्डी जोन के अंतर्गत जो पिछले वर्ष 66 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया था इस बार उस बजट के प्रावधान को कम करके 46 करोड़ रुपये कर दिया गया है? मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारी योजना का आकार पिछले वर्ष 4 हजार 800 करोड़ रुपये था और इस बार वह बढ़कर 5 हजार 200 करोड़ रुपये हो गया। हम सोच रहे थे कि 66 करोड़ रुपये से बढ़कर बजट आगे जाएगा लेकिन क्या वजह और कारण है, क्योंकि वित्त विभाग मुख्य मंत्री जी के पास है कि मण्डी और हमीरपुर जोन का बजट आपने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वित्त वर्ष में कम किया है और एक मण्डी जोन में ही 20 करोड़ रुपये कम किया है। क्या मुख्य मंत्री जी बतलाएंगे कि मण्डी और हमीरपुर जोन के अंदर जितनी सड़कें बननी थी, जितने पुल बनने थे, जितनी खस्ता हालत सड़कों की मण्डी केन्द्रीय क्षेत्र के अंदर है क्या वहां पर सारी व्यवस्था लोक निर्माण विभाग ने पूर्ण कर दी है यानी वहां पर अब और काम करने की आवश्यकता नहीं है? अध्यक्ष जी, हम मुख्य मंत्री जी से एक बात और जानना चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी यह 21वीं शताब्दी का दौर है। हम 19वीं शताब्दी की तरफ पीछे नहीं हट रहे हैं। जब 21वीं शताब्दी का दौर है तो इस शताब्दी में तो सारी जानकारी हमारी जेब में है। हमारे छोटे-छोटे बच्चे जो पहली और दूसरी कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वे भी अपने मोबाइल पर सारे विश्व की जानकारी रखते हैं। लेकिन मुख्य मंत्री जी एक बात की हैरानी होती है। वर्ष 2012 में जब

28/03/2016/1510/MS/DC/2

छठी बार मुख्य मंत्री के तौर पर आपने शपथ ली थी तो आपने कहा था कि हम पारदर्शिता पूरे प्रदेश के अंदर सभी विभागों के अंदर लाएंगे। उस पारदर्शिता में आपकी पारदर्शिता के ऊपर बहुत बड़ी शक की सूई जा रही है। वह शक की सूई इसलिए नहीं जा रही है कि हम अपनी तरफ से कोई ऐसे आरोप-प्रत्यारोप आपके ऊपर लगा रहे हैं बल्कि इसलिए शक की सूई जा रही है कि आपने एक नया फार्मूला निकाल दिया है। अब पता नहीं वह कौन सा फार्मूला निकाल दिया, वह हमें समझ नहीं आ रहा है। आपने एकमुश्त का नया फार्मूला निकाल दिया है कि जो भी राशि है या बजट की राशि है उसमें आप लिख रहे हैं कि यह एकमुश्त राशि सी0आर0एफ0 वर्क के लिए हिमाचल

प्रदेश के अंदर है। अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सी0आर0एफ0 का पैसा है वह पैसा कोई एकमुश्त में हिमाचल प्रदेश सरकार को नहीं मिलता है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

28.03.2016/1515/जेएस/डीसी/1

श्री महेन्द्र सिंहः-----जारी-------

वह पैसा भारत सरकार से डी0पी0आर0 के मुताबिक मिलता है और एक-एक काम के मुताबिक मिलता है। जब आपकी डी0पी0आर0 मिनिस्टरी ऑफ सरफेस ऑफ ट्रांसपोर्ट के वहां से सेंक्शन हो कर के आई हुई है आप उस पैसे को एकमुश्त राशि में क्यों रखना चाहते हैं? इससे हमें एक शंका पैदा हो रही है कि आप यह चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे क्षेत्रों का पैसा जो सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों के लिए आया हुआ है, पुलों के निर्माण कार्यों के लिए आया हुआ है और इन्टर स्टेट कनैक्टिविटी के लिए आया हुआ है। आप उस पैसे को अपने पास रखना चाहते हैं और जहां आपकी इच्छा हुई उस पैसे को दे दिया और जहां पर इच्छा नहीं हुई वहां पर रहने दिया। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र के अन्दर एक सड़क है उसके लिए 46 करोड़ 24 लाख की डी0पी0आर0 भारत सरकार से स्वीकृत हुई है। फर्स्ट फेज़ के लिए 12 करोड़ 27 लाख रूपया आया हुआ है, लेकिन आपने उस बजट बुक में अंकित किया कि अवाहदेवी-टिहरा-सन्धोल सड़क के लिए 10 लाख का प्रावधान है। मुख्य मंत्री महोदय इससे क्या हो रहा है कि जो ग्रास रूट पर जो वर्किंग हो रही है और जो ग्रांस रूट में हमारा जो जे0ई0 है, एस0डी0ओ0 है और एक्सियन है वह कह रहा है कि इसमें केवल इतना कर काम करना है क्योंकि इसके लिए केवल 10 लाख रूपए का प्रावधान है, जबकि उसके लिए भारत सरकार ने आपको एकमुश्त राशि प्रदान कर दी है? हमारा आरोप इस बात के ऊपर है और हमारा आपसे निवेदन नहीं है, हमारा आरोप वर्तमान सरकार के ऊपर है कि एकमुश्त राशि चाहे वह सी0आर0एफ0 है, चाहे वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और हमें तो हैरानी इस बात की होती है कि माननीय अध्यक्ष जी आप भी अपने विधान सभा क्षेत्र से एक विधायक के रूप में चुन कर आए हैं। जब हम अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं वहां पर

जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उस योजना का एक कोर नेट वर्क बना हुआ है। वह कोर नेट वर्क जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री थे उन्होंने हर गांव तक सड़क को पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया था। जो कोर नेट वर्क बना हुआ है और उस कोर नेट वर्क के मुताबिक डी0पी0आर0 बन करके भारत

28.03.2016/1515/जेएस/डीसी/2

सरकार को भेजी जाती है। जब भारत सरकार से पैसा स्वीकृत हो कर आता है वह पैसा कोई लमसम में नहीं आता है कि हिमाचल प्रदेश को इतना पैसा लमसम में दे दिया। वह पैसा भी वर्क वाईज़, डी0पी0आर0 वाईज़ वहां से स्वीकृत करके प्रदेश सरकार को भेजा जाता है। आपने क्या कर दिया कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 50 करोड़ 38 लाख रूपया बजट बुक में लिख दिया कि एकमुश्त राशि 50 करोड़ 38 लाख रूपया प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्दर जितनी भी सड़कें इस प्रदेश के अन्दर बन रही हैं और पुल इस प्रदेश के अन्दर बन रहे हैं उनके लिए एकमुश्त राशि रख दी। वह भी आपके ऊपर निर्भर करेगा कि जहां पर आपकी इच्छा करेगी तो वहां पर आप पैसा भेज देंगे और जहां आपकी इच्छा नहीं करेगी वहां पर आपके जो इंजीनियर बैठे हैं, आपके जो सेक्रेटरीज़ बैठे हैं वे कहेंगे कि आपकी सड़कों के लिए तो अभी तक पैसा नहीं आया हुआ है। आप विशेष करके जो हम यहां पर विपक्ष के बैंचों में 27 लोग हैं और महेश्वर सिंह जी का पता नहीं कि वह इस तरफ है या उस तरफ है। हम जो 27 लोग हैं आप हमारे विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के अन्दर विकास की गति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के ऊपर भी हमारा आपके ऊपर आरोप है। विश्व बैंक परियोजनाएं यहां से जाती हैं उसके लिए प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनती है और उसका पूरा प्रोजैक्ट बन कर जाता है और उस प्रोजैक्ट के रूप में ही वह सेंक्शन हो करके आता है। जो प्रोजैक्ट के रूप में सेंक्शन हो करके आता है तो क्या कारण है कि आपने वहां पर भी एकमुश्त कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि और मुख्य मंत्री जी आपने सी0आर0एफ0 का हवाला दे दिया, पी0एम0जी0एस0वाई0 का हवाला दे दिया और विश्व बैंक का हवाला दे दिया।

अच्छा होता कि हिमाचल प्रदेश के जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं उन के लिए जो भूतल परिवहन मंत्रालय से आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जो पैसा हिमाचल प्रदेश की उन नेशनल हाई वे बनाने के लिए दिया है अगर उसका भी आपने यहां पर कोई जिक्र कर दिया होता तो अच्छा होता और पता चलता कि

28.03.2016/1515/जेएस/डीसी/3

हिमाचल प्रदेश की नेशनल हाई वे रोड़ज को बनाने के लिए कितना पैसा भारत सरकार से हमें मिला हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि अभी आपकी जो देनदारियां हैं, जो पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग की देनदारियां हैं वे आंकड़ें मेरे पास वर्ष 2015 तक के हैं और 31 मार्च, 2016 के आंकड़ें 31 मार्च के बाद हासिल होंगे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

28.03.2016/1520/SS-AG/1

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागतः

मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आपके लोक निर्माण विभाग के अंदर जो देनदारियां हैं उसमें बहुत सारी देनदारियां ठेकेदारों को देनी हैं। दूसरे जो हमारे अन्य कंट्रेक्टर्ज़ हैं उनकी बहुत बड़ी लाइबिलिटी अभी तक देनी बाकी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि 6 करोड़ 15 लाख रुपये की लाइबिलिटी मार्च, 2015 तक मैटीरियल कम्पोनैंट की है और इस वर्ष की लाइबिलिटी वह इससे कम नहीं होगी। वह लाइबिलिटी इससे ज्यादा बढ़ेगी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने उसका क्यों ज़िक्र नहीं किया है। मैं दूसरा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि ठेकेदारों की जो लाइबिलिटी मार्च, 2015 तक की है वह 121 करोड़ 23 लाख रुपये की है। 121 करोड़ 23 लाख रुपया आपको 2015 तक प्रदेश के अंदर जो रीढ़ की हड्डी कंट्रैक्टर्ज़ हैं उनका देना है। उन कंट्रैक्टर्ज़ ने लोक निर्माण विभाग से विभिन्न सड़कों, पुलों या अन्य लाइबिलिटीज़ के रूप में वह पैसा लेना है लेकिन आपने उस राशि का

कोई भी ज़िक्र यहां पर नहीं किया है। मैं मुख्य मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो 31 मार्च लग रहा है, इस 31 मार्च में क्या होता है कि इससे पहले-पहले लोक निर्माण विभाग में सारी बुकिंग की जाती है। सरिया, सीमेंट, बिचुमैन बुक किया जाता है। मेरा निवेदन है और आरोप है कि जिस प्रकार का बिचुमैन लोक निर्माण विभाग के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है वह सही नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें चिन्ता इस बात की है कि ऐसा बिचुमैन या तारकोल सड़कों को पक्का करने के लिए प्रदेश के अंदर लगाया जा रहा है कि पहली ही बरसात में बह जाता है। आज उस सड़क पर टारिंग करके जाते हैं और जब पहली बारशि होती है जैसे तवे की स्याही पर पानी पड़ता है तो वह धुल जाती है उसी प्रकार से गुणवत्ता की दृष्टि से अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई है। आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लैबोटरीज़ हैं वह गुणवत्ता देखती हैं। आपने एक विभाग लोक निर्माण विभाग के अंदर खड़ा किया हुआ है जोकि पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी सड़कें, बिल्डिंगें बन रही हैं या दूसरे टैक्निकल कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता जांचता है। हर जोन में चाहे वह मंडी का जोन है, शिमला का जोन है या धर्मशाला/हमीरपुर का जोन है वहां पर आपकी लैबोटरीज़ बनी हुई हैं। उन लैबोटरीज़ की स्थिति मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। उनकी हालत ऐसी है कि

28.03.2016/1520/SS-AG/2

अगर कहीं पी0सी0सी0 का डंगा लग रहा है तो पी0सी0सी0 के डंगे में वैसे आपकी टैक्निकल साइड कहती है कि उसमें 85 प्रतिशत कंकरीट पड़नी चाहिए और 15 परसैंट आपके प्लम पड़ने चाहिएं लेकिन अध्यक्ष जी उलटा हो रहा है। 85 प्रतिशत कंकरीट की जगह 65 और 70 प्रतिशत वोल्डर प्लम पड़ रहे हैं और 30 से 25 परसैंट कंकरीट पड़ रही है। आज यही वजह है, सबसे बड़ा कारण है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने कंकरीट के डंगे लग रहे हैं एक तो उसमें पत्थर ज्यादा डाले जा रहे हैं। दूसरा उसमें जिस अनुपात में सीमेंट डलना चाहिए वह उस रेशो में नहीं डल रहा है। उस रेशो में सीमेंट न डलने की वजह से जिस प्रकार से उसकी क्योरिंग होनी चाहिए वह क्योरिंग नहीं हो रही है। जिसकी वजह से आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आप आगे-आगे

डंगे लगा रहे हैं और दूसरी-तीसरी बरसात के बाद सारे-के-सारे डंगे धराशायी हो रहे हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप इस तरफ विशेष ध्यान दें। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि आज पूरे विश्व स्तर पर तेल की कीमतें कम हुई हैं। थोड़ी कम नहीं हुई बल्कि बहुत ज्यादा कम हुई हैं। जब तेल की कीमतें कम हुई हैं तो बिचुमैन की दरें भी कम हुई हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप बताएं कि जिस बिचुमैन की लोक निर्माण विभाग ने बुकिंग की हुई है, मेरा ख्याल है कि जैसे ही बजट पास होता है उसके बाद जो मैटीरियल कम्पोनैंट है उसके लिए जो एक्सियन हैं या एस0सी0 हैं या चीफ इंजीनियर हैं या इंजीनियर-इन-चीफ हैं वे उस मैटीरियल कम्पोनैंट को पहले ही बुक कर लेते हैं। जो पहले बुक किया हुआ मैटीरियल है उस वक्त के बिचुमैन के रेट्स बहुत ज्यादा थे, आज बिचुमैन के रेट कम होने चाहिए थे।

जारी श्रीमती के0एस0

28.03.2016/1525/केएस/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी----

आप इस बात को सुनिश्चित करें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर विभिन्न मण्डलों के माध्यम से जितना बिचुमैन खरीदा जा रहा है, क्या उसकी वही कीमतें हैं जो वर्तमान में कीमतें हैं या कहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे मालूम है कि पी.डब्ल्यू.डी. में जब बिचुमैन के लिए पैसा जमा करवाया जाता है अगर बिचुमैन के रेट बढ़ते हैं तो जो रिफाईनरीज़ हैं, वह उस रेट को बढ़े हुए रेट के मुताबिक देती हैं। लोक निर्माण विभाग इस बात को सुनिश्चित करें कि जब बिचुमैन के रेट घटे हैं तो उसके साथ-साथ अगर पहले ज्यादा रेट्स पर पैसा दिया होगा तो जो आज घटे हुए रेट हैं, आज जब आप माल हासिल कर रहे हैं तो उस रेट से सारा का सारा बिचुमैन खरीदना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर सरिया का रेट बहुत ज्यादा कम हुआ है। जो सरिया पहले 4500-4600 रु0 मिलता था, टाटा का स्टील जो 5500 में मिलता था आज वह सरिया 3200-3300 और 3000 और 3500 रु0 के बीच में हैं। इस बात को लोक निर्माण विभाग सुनिश्चित करें। मेरा आरोप है कि जो सरिया की इस प्रदेश के अंदर लोक निर्माण विभाग ने पहले की बुकिंग की है, वह पहले के रेट से बुकिंग की है । आप इस

बात को भी देखें कि इस प्रदेश के धन का दुरुपयोग न हो।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये चार दिन हमारे हैं। प्राईवेट मैम्बर डे और ये जो हमारे कटौती प्रस्ताव हैं, ये विपक्ष का ही काम है, विपक्ष का ही समय है। निश्चित समय के बीच में ही इसमें हमें बोलना होता है और इस समय में हमने जो अपनी प्राथमिकताएं दी हैं, हम सभी ने इस पर अपनी-अपनी बात रखनी है। इसलिए मेरी आपसे विनती है।

अध्यक्षः अपोजीशन में केवल आप ही बोलने वाले नहीं है बाकी मैम्बर्ज़ भी हैं।

28.03.2016/1525/केएस/एजी/2

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, बहुत समय है। चार दिन है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो बेलदार हैं, उनका बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। उनको राजनीतिक आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है और एक मण्डल से दूसरे मण्डल में नहीं बल्कि लोक निर्माण विभाग से दूसरे विभागों में भेजा जा रहा है। आपने धर्मपुर मण्डल से लोक निर्माण विभाग के ऐसे बेलदारों को जिन्होंने लिखित रूप में नहीं दिया था कि हम लोक निर्माण विभाग से मच्छली पालन विभाग में जाना चाहते हैं, एक्साईज़ एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमैंट में जाना चाहते हैं या हम किसी दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं लेकिन प्रदेश सरकार, लोक निर्माण विभाग अपने आप ही उनके आदेश कर रही है कि आपको मच्छली पालन विभाग में फ्लां जगह भेज दिया, आपको किन्नौर भेज दिया, आपको कल्पा भेज दिया। हमारा वर्तमान प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप है और निवेदन भी है कि लोक निर्माण विभाग के अंदर जो बेलदारों और मजदूरों का शोषण किया जा रहा है उसको जितनी जल्दी हो सके बन्द करें। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर यह स्थिति पैदा हो चुकी है कि टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन आज लोक निर्माण के अंदर है। कोई चीफ इंजीनियर की पोस्ट खाली नहीं है, इंजीनियर इन चीफ एक या दो नहीं बल्कि तीन-तीन लोक निर्माण के अंदर बिठाए गए हैं। आज एस.ई. या एक्सिअन की कोई पोस्ट खाली नहीं है। जहां

से ग्राऊंड वर्क होना है, जहां से सर्वे इन्वैस्टिगेशन होनी है, जहां सड़कों की डी.पी.आर. बननी है, वहां सर्वेयर की पोस्टें खाली है। ड्राफ्ट्समैन की पोस्टें खाली पड़ी है। ड्राईंग ब्रांच में देखें तो वह चाहे डिविज़न की ड्रॉईंग ब्रांच हो या सर्कल या जोनल स्तर की ड्राईंग ब्रांच हो, उनमें तो ऐसा हो रहा है कि जो कोई रिटायर हो रहा है उसके साथ ही उस पद को भी खत्म किया जा रहा है। हमारा आरोप भी है और मुख्य मंत्री जी से निवेदन भी है कि जो टैक्निकल विंग है, जो ग्रास रूट से काम करने वाले छोटे कर्मचारी है, उनकी पोस्टों को आप हर हाल में भरें भले ही ऊपर की पोस्टें खाली रह जाएं। हमारी एम.एल.ए. प्रायोरिटी की जो स्कीमें हैं, हम सभी सदस्य बड़ी उम्मीदों के साथ एम.एल.ए.

28.03.2016/1525/केएस/एजी/3

प्रायोरिटीज़ देते हैं लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एम.एल.ए. प्रायोरिटीज़ में हमने इन तीन-चार वर्षों में जितनी प्रायोरिटीज़ दी हैं, उनमें लगभग 10 प्रतिशत प्रायोरिटीज़ भी अभी पूरी नहीं हुई है। हम जब डिविज़न में पूछते हैं, एस.डी.ओ. और जे.ई. को पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि एम.एल.ए. प्रायोरिटी चीज़ क्या होती है। इस लोक निर्माण विभाग को क्या हो गया है कि जिसमें जे.ई. को पता नहीं है, एस.डी.ओ. को पता नहीं है, एक्सिअन को पता नहीं है कि विधायकों की प्राथमिकताएं क्या है और उनकी डी.पी.आर. किस प्रकार बननी चाहिए? हमारा आरोप है कि हम जो विपक्ष के लोग हैं, हमारे चुनाव क्षेत्र के अंदर, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उन पर आप काम नहीं कर रहे हैं। नाबार्ड की जहां तक बात है, नाबार्ड से पैसा वहीं मिलेगा जो कि हम एम.एल.ए. प्रायोरिटीज़ में देते हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.3.2016/1530/av/ए0एस/1

श्री महेन्द्र सिंह------ जारी

हमारा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं न कि किसी विशेष जिला या किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के हैं। आप छठी बार मुख्य मंत्री बने हैं। आज भी

हमारे प्रदेश के सात विधान सभा चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं कि जबसे इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है उन सात विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में विधायक प्राथमिकता की एक भी डी0पी0आर0 नहीं बनी है। यह बड़ी शर्म की बात है और चिन्ता का विषय भी है। आप प्लानिंग की बैठक करते हैं और उसमें हम सभी विधायक अपनी प्राथमिकताएं रखते हैं लेकिन उन पर आगे कुछ नहीं होता। आपने एक ही चुनाव क्षेत्र के लिए नाबार्ड से 86.53 करोड़ रुपये की राशि दे दी। वह कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है, उसकी आपको जानकारी है तथा लोक निर्माण विभाग को भी पता है। आपने एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 86.53 करोड़ रुपये दे दिए इसलिए हमारा निवेदन है कि कृपया आप ऐसा न करें। आपने इस बजट में बहुत बड़ा अमाऊंट सप्लीमैंट्री बजट के लिए रखा हुआ है। सप्लीमैंट्री बजट तब पेश होता है जब हमारा अगला बजट प्रस्तुत होने में आता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जब आपने इस हाउस में बजट प्रस्तुत करना है, अगले साल की योजनाओं के लिए पैसा देना है। अगले साल की योजनाओं के लिए सप्लीमैंट्री में आप क्यों इस बड़े अमाउंट को रख रहे हैं? आप सारे-के-सारे पैसे का दस प्रतिशत सप्लीमैंट्री बजट के लिए रखें और बाकी सारा-का-सारा पैसा हिमाचल प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को वर्कवाइज जाना चाहिए।

भवन निर्माण की बात की जाए तो भवन निर्माण और पुल निर्माण के तहत जैसे मैंने कहा कि गुणवत्ता की ऐसी स्थिति है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि लोक निर्माण के तहत बिल्डिंग्ज निर्माण में इतना घटिया स्तर का काम होता होगा। इस लोक निर्माण विभाग को क्या हो गया है? प्रदेश में पुलों का निर्माण कार्य 10-10, 15-15 सालों से लम्बित पड़ा हुआ है। यहां पर जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां आई हुई हैं वे महीनों में पुल तैयार कर रही हैं। आप सरकाघाट से

28.3.2016/1530/av/ए0एस/2

घुमारवीं की तरफ आयें तो दखेंगे कि वहां पर निर्माणाधीन पुल दो-दो, तीन-तीन महीने में बनकर तैयार हो रहे हैं और उनको यातायात के लिए खोला जा रहा है। मगर हमारा लोक निर्माण विभाग कहता है कि अभी तो हमने डाटा भी नहीं लिया है। डाटा लेने के बाद हम डिजाईन बनायेंगे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक पुल के लिए नाबार्ड के तहत वर्ष

2012 में पैसा आया हुआ है। अब वर्ष 2016 चला हुआ है मगर उस पुल का काम अभी तक भी शुरू नहीं हुआ है। अब कहते हैं कि हमने लम्प्सम टैंडर लगाने हैं। अगर लम्प्सम टैंडर लगाने है तो उसमें क्या चार साल का समय लगता है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि हमारे वहां पर वर्ष 2012, 2013 व 2014 में भारी वर्षा हुई तथा वर्ष 2015 में बादल फटा जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं भी गये थे। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है और मेरा सरकार के ऊपर आरोप भी है कि वहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है। उन सड़कों की बजाय तो हमारी खड्डों में गाड़ियां चलाई जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे वहां आपने टूटी हुई सड़कों की रिपेयर के लिए कोई पैसा नहीं दिया। वहां पर एक या सवा करोड़ रुपये की राशि से सड़कें नहीं बनेंगी। वहां तो कम-से-कम 40-50 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक ठोठू पुल है। उस पुल का काम एक ठेकेदार को दिया गया और जब ठेकेदार ने उस पर स्लैब डाला तो वह पुल नीचे बैठ गया। वहां पर एक्सियन ने यह कहा कि भारी वर्षा के कारण पुल टूटकर नीचे बैठ गया। उस ठेकेदार को कहा गया कि आप उस पुल को दोबारा बनाइए, विभाग आपको दोबारा से पैसा दे देगा। क्या आप उसकी कोई जांच करवायेंगे? हम चाहते हैं कि उसके बारे में जांच की जाए। इस प्रकार से प्रदेश की जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपने कहा है कि हम जीरो टॉलरैंस पर काम करते हैं तो मैं आपको ठोठू पुल का नाम लिखवा रहा हूं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो नाबार्ड में पैसा दिया हुआ है उस नाबार्ड के पैसे से जो सड़कें बननी चाहिए थी, चार-चार साल हो गये हैं उनका कोई कार्य नहीं हुआ। नाबार्ड का पैसा एक स्टिपुलेटिड पीरियड के लिए मिलता है मगर दुख इस बात का है कि 5-5 साल के पश्चात भी उन सड़कों का कार्य नहीं हुआ।

टीसी द्वारा जारी

28.03.2016/1535/TCV/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह ----- जारी

जब से आपकी सरकार आई आपने वहां (धर्मपुर में) एक ऐसा एक्सीयन भेज दिया है जो कहता है कि मुझे यहां पर जबरदस्ती भेजा गया है, जिस काम को करने की मेरी

मंशा होगी, मैं उस काम को करूंगा और जिस काम को करने की मंशा नहीं होगी उसको मैं नहीं करूंगा। उसका सिर्फ एक ही काम रह गया है, वह केवल ठेकेदारों को ही बुलाता है लेकिन जनता-जनार्दन, सड़कों पुलों व भवन निर्माण के जो काम होने चाहिए थे, उनकी तरफ उसका कोई भी ध्यान नहीं है। डिपॉजिट का पैसा, शिक्षा विभाग या दूसरे विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग का पैसा है, 2012 से लेकर के 2016 हो गया लेकिन वे भवन अभी भी वैसे के वैसे ही पैंडिंग हैं। हमारा वर्तमान सरकार पर आरोप है कि जहां-जहां भाजपा के विधान सभा चुनाव क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के साथ आप भेदभाव करते हैं। अध्यक्ष महोदय आपने समय दिया आपका धन्यवाद करता हूं वहीं हमारे जो आरोप है वह बिल्कुल दरूस्त है और दुरूस्त आरोपों के साथ-साथ हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी आपकी सरकार निन्द्रा में सोई हुई है वह थोड़ी जाग जाए नहीं तो यह सरकार/विभाग सोए-सोए रह जाएगें और प्रदेश की सड़कों/पुलों/भवनों/मजदूरों की जो बदहाली है वह जनता के सामने हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2016/1535/TCV/AS/2

मुख्य मंत्रीः आपके साथ के सदस्य आपकी बात से सहमत नहीं हैं और आपकी फेवर में इन्होंने तालियां नहीं बजाई क्योंकि जो धांधली आपने की when you were the PWD Minister. वह सब जानते हैं। सी0आर0एफ0 रोड की बात कर रहे हैं, सारी सड़कें तो आपकी कांस्टीचुऐंसी में बनी जो आप आपको नज़र नहीं आती है। नेशनल हाईवे का अलाईनमैंट बदला गया ताकि आपकी कांस्टीचुऐंसी होकर जाये। आपने धर्मपुर में खड्ड में बस स्टैंड बना दिया और वह बह गया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी भेदभाव में विश्वास नहीं करती है। अधिकतर जगह पर अधिकांश अधिकारी अच्छी तरह से कार्य करते हैं और कुछेक अधिकारी लापरवाही/कामचोर भी

हो सकते हैं। इस बारे में हमारे अधिकारियों को देखना है कि ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये जो पैसा होते हुए भी काम नहीं करते हैं जैसे आपने कहा कि जो प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसको पैसा कहीं और जगह लगाया जाता है लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो पैसा जिस सड़क के नाम सैंक्शन होता है, वह एक-एक पैसा उसी सड़क पर खर्च होता है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं मगर यहां आप जानबूझकर एक सनसनी पैदा करने के लिए इस तरह के गलत बयान देते हैं। मैं आपके बारे में काफी ज्यादा जानता हूं और आपके बारे में व्हाईट पेपर ईशू कर सकता हूं। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि आलोचना किजिए मगर इतना बढ़ा चढ़ाकर न करें जैसे कोई काम हो ही नहीं रहा है और एक मद का पैसा दूसरे मद में जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है यदि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए पैसा आता है तो आप दूसरे सड़क योजना पर पैसा खर्च नहीं कर सकते है उसी योजना पर पैसा खर्च होगा जिसके लिए पैसा आया है। It cannot be diverted to any other Yojna even in the Pradhan Mantri Sadak Yojna और इसी तरह से जो नेशनल हाईवे का पैसा है वह नेशनल हाईवे पर ही लगता है। It cannot be diverted anywhere else. ये ठीक है कि कहीं-कहीं शिथलता से काम हो रहे हैं यह मैं खुद भी महसूस करता हूं । इसके लिए जो वहां पर फिल्ड स्टॉफ है, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर, एक्सीयन, एस0डी0ओ0 है, उनकी कार्यकुशलता पर बहुत

28.03.2016/1535/TCV/AS/3

कुछ निर्भर करता है, जो काम करने वाले आदमी है वह रिजल्ट दिखाते हैं और जो काम नहीं करना चाहते, जैसे आपने भी जिक्र किया है, चाहे उनके पास कुबेर का धन भी क्यों न हो फिर भी काम नहीं करेंगे। इसलिए इस बात को जनरेलाईज़ नहीं करना चाहिए। I can assure you, for me Himachal is one.

श्री आर0के0एस0 --- द्वारा जारी ।

28.03.2016/1540/RKS/DC/1

मुख्य मंत्री...जारी

उस हलके के बजट के मुताबिक विकास करना हमारा कर्त्तव्य है। अगर कहीं काम में शॉर्टफाल होता है तो मैं उसको विभाग की कोताही समझूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं don't raise such issues. हम भी जवाब देना जानते हैं कि पीछे क्या कुछ हुआ है? मगर मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता। आपने महत्वपूर्ण प्वाईंट रेज किए हैं, I will look into the matter.

अध्यक्षः देखिए आप डिस्कशन शुरू करेंगे तो यह खत्म ही नहीं होगी। अगर आपका ऑब्जैक्शन है तो आप बोलिए।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी , लोक निर्माण विभाग मुख्य मंत्री जी के पास है। ये मुख्य मंत्री के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं।

मुख्य मंत्रीः मैं मंत्री के रूप में बोल रहा हूं।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, इन्होंने इस पूरी मद का एक बार जवाब देना है। इन्होंने बीच में कहा कि आपके सारे कार्यों की सूचना मेरे पास है। आपने कहा कि मैं श्वेत पत्र जारी करुंगा। मुख्य मंत्री जी आप श्वेत पत्र जारी करने में देर न करें। इसी हाऊस में महेन्द्र सिंह के प्रति 7 अप्रैल से पहले एक श्वेत पत्र जारी कर दें। महेन्द्र सिंह की बड़ी खुली किताब है, इससे प्रदेश की जनता को भी पता चलेगा। दूसरी बात आपने कही कि पी.एम.जी.एस.वाई., नाबार्ड का पैसा उन्हीं कामों में प्रयोग होता है जिनके लिए वह सैंक्शन होता है। फिर आपने क्यों इस पैसे को एकमुश्त में रखा? हमारा आरोप है कि आपने उस पैसे को एकमुश्त में क्यों रखा? यह पैसा जिन-जिन कार्यों के लिए आया था, जिन-जिन सड़कों, पुलों के लिए आया था उस पैसे को उन-उन सड़कों, पुलों के सामने दर्शाना चाहिए था। पी.एम.जी.एस. वाई.का पैसा इतना है, नाबार्ड का पैसा इतना है, विश्व बैंक का पैसा इतना है। आपने क्यों उस पैसे को एकमुश्त राशि में डाला?

28.03.2016/1540/RKS/DC/2

मुख्य मंत्रीः आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जो भी पैसा चाहे वर्ल्ड बैंक से आता है, चाहे प्रधान मंत्री सड़क योजना से आता है, नाबार्ड से आता है जिस चीज के लिए वह पैसा सैंक्शन होता है, वहीं उस पैसे को खर्च किया जाता है। उस पैसे को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं।

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पता है कि वह पैसा उन्हीं कार्यों में खर्च होता है। लेकिन आपने एकमुश्त इसलिए रोका है क्योंकि आप हमारे चुनाव क्षेत्र के कार्यों को रोकना चाहते हैं। आप मेरे प्रति एक श्वेत पत्र जारी करेंगे। आप एक श्वेत पत्र और जारी करें जो एकमुश्त राशि आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर विभिन्न कार्यों के लिए रखी हुई है, उसका भी आप एक श्वेत पत्र ईश्यू कर दें ताकि इस प्रदेश की जनता को पता लगे कि पी.एम.जी.एस.वाई. में किस सड़क के लिए पैसा आया है, नाबार्ड में किस सड़क के लिए पैसा आया है और विश्व बैंक में किस सड़क के लिए पैसा आया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप उसके लिए भी एक श्वेत पत्र जारी कर दें।

मुख्य मंत्रीः ठीक है, आप बैठिए। जब आप पी.डब्ल्यू.डी.मंत्री थे तो आपने उस समय इस प्रथा को जारी क्यों नहीं किया? आप भी पावर में थे।

श्री महेन्द्र सिंहः आपने कहा कि आप मेरे प्रति श्वेत पत्र जारी करेंगे।

मुख्य मंत्रीः वह तो निकालेंगे।...(व्यवधान)... आपके ऊपर पूरी किताब लिखेंगे।

अध्यक्षः अब श्री रिखी राम कौंडल जी मांग संख्याः 10 पर चर्चा में भाग लेंगे। अभी 12 आदमी बोलने वाले हैं आप अपने समय का उपयोग करते हुए जिस विषय पर बोलना चाहते हैं, उस पर बोलिए।

28.03.2016/1540/RKS/DC/3

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, इसमें समय-सीमा नहीं होती । जो हमारे बोलने वाला समय है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी बीच में खड़े हो जाते हैं और

जवाब देना शुरू कर देते हैं। The House is controlled by the Hon'ble Speaker by certain Rules. हमारे लिए तो आप नियम बताते हैं कि नियम से हाऊस चलेगा और मुख्य मंत्री जी को जो जवाब अंत में देना होता है उसमें वे बीच-बीच में इंटरवीन करते रहते हैं।

अध्यक्षः वैसे मैं आपको रूल्ज बता दूं चीफ मिनिस्टर का इंटरवीन किसी भी समय हो सकता है। The Hon'ble Chief Minister can intervene any time and this is a Rule.

Sh. Rikhi Ram Kaundal: Hon'ble Chief Minister can intervene for one or two points. He should not give the full reply.

Speaker: He is not giving the full reply, he will give it later.

मुख्य मंत्रीः मैं फुल रिप्लाई अंत में दूंगा। कोई ऐसा प्वाईंट which is repeatedly wrong, I want to remove the impression immediately so that ये जो प्रैस वाले छापेंगे कि ऐसा कहा है उसका जवाब भी मैं साथ में दे रहा हूं । जो कंप्लीटली रोंग है उसका जवाब तुरंत मिलना चाहिए। नहीं तो गलतफहमी पैदा होती है।

अध्यक्षः आप अपने कटौती प्रस्ताव में अपने समय पर कटौती न लगाईए।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय मांग संख्याः10- लोक निर्माण -सड़क पुल एवं भवन इस पर जो आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री एस.एल.एस द्वारा ....जारी

28.03.2016/1545/SLS-DC-1

श्री रिखी राम कौंडल...जारी

अध्यक्ष महोदय, सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं। जब-जब सदन के नेता वक्तव्य देते हैं तो सबसे पहले इन भाग्य रेखाओं का ज़िक्र ज़रूर करते हैं कि सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं। सड़कें रूपी भाग्य रेखाएं जो थोड़ी-थोड़ी मिटनी शुरू हो गई हैं, उस बात को लेकर मैं अपने चुनाव क्षेत्र और प्रदेश के बारे में भी थोड़ा-सा प्रकाश डालूंगा।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते यहां पर्यटन की आपार संभावनाएं हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां ज्यादा एयर स्ट्रिप्स हों। यहां पर दो छोटी-छोटी एयर स्ट्रिप्स हैं जहां इतने पर्यटक नहीं आ सकते । रेल का साधन हिमाचल प्रदेश में है नहीं। मैं 1985 से राजनीति में हूं और तब से माननीय सदन के नेता मुख्य मंत्री महोदय भी कहते रहे हैं जो बीच में दो मर्तबा छोड़ उस समय से चलते आ रहे हैं, मैं उस समय से इनके भाषण सुन रहा हूं कि भनुपल्ली से रामपुर तक रेल लाईन बिछा दी जाएगी लेकिन आज तक उस रेल का कुछ नहीं हुआ। इसलिए इस प्रदेश के अंदर अब मात्र सड़कें ही ऐसा साधन हैं जिससे कि हमारा आवागमन हो सकता है। आज सड़कों और पुलों की क्या हालत है ? माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर हम इस माननीय सदन के अंदर कोई बात रखते हैं, आप उसको अदरवाईज लेते हैं, आप उसको पर्सनल करके लेते हैं। उसको आप पर्सनल मत लीजिए। हिमाचल प्रदेश की यह सारी प्रॉपर्टी हिमाचल प्रदेश की जनता की है। आप लोग सत्ताधारी दल में हैं। लोगों ने आपको इसलिए सत्ताधारी दल में भेजा है so that you protect the Rights of the people. लोगों के जान-माल की इफाज़त हो, सड़कें ठीक हों और पानी की समस्या दूर हो, यह सारी बातें देखने के लिए ही आप सत्ताधारी दल में हैं। जब हम अपने चुनाव क्षेत्र की कोई विशेष मांग रखते हैं, उसको आप अदरवाईज लेते हैं कि हम व्यक्तिगत बात बोल

रहे हैं। माननीय महेन्द्र सिंह जी के बारे में आपने कई बातें पर्सनल बोल दीं। मैं उनमें इंटरवीन नहीं करना चाहता। इन्होंने उसका उत्तर दिया है। Don't take it personally. हम अपने चुनाव क्षेत्र की और इस प्रदेश के हित की बात करने के लिए इस माननीय सदन के अंदर आए हैं। ...(व्यवधान)...

28.03.2016/1545/SLS-DC-2

हम अपने चुनाव क्षेत्र की और इस प्रदेश के हित की बात करने के लिए इस माननीय सदन के अंदर आए हैं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, आज सड़कों की हालत क्या है?

मुख्य मंत्री : आप केवल कट मोशन पर बोलो। Don't be personal.

श्री रिखी राम कौंडल : मैं कट मोशन पर ही बात कर रहा हूं। मैं लोक निर्माण विभाग पर दिए कट मोशन पर ही बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय महेन्द्र सिंह जी ने कहा कि ठेकेदारों की देनदारी 21.23 करोड़ रुपये देने को है। मैटिरियल कंपोनैंट का पैसा 6.15 करोड़ रुपये देने को बाकी है। जब आपने सड़कों के लिए बजट ईयरमार्क कर दिया तो जब उसके टैंडर लगे, वह टैंडर उसी हिसाब से लगने चाहिए थे जिस हिसाब से बजट हो। आज ठेकेदार पैसे के लिए तड़फ रहे हैं कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है और काम सब-स्टैंडर्ड हो रहा है।

मैं अपने चुनाव क्षेत्र की कुछ बातों का ज़िक्र करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप हर वर्ष नलवाड़ी मेले में जाते हैं, इस बार भी गए। बिलासपुर में लोगों ने आपका बहुत स्वागत किया, हम भी करते हैं। मुख्य मंत्री का दायित्व बनता है कि जहां बड़ा फंक्शन हो वहां उन्हें जाना चाहिए। आप हर बार वहां बबखाल पुल का ज़िक्र करते थे। उससे आप ऐसी सनसनीखेज़ स्थिति बना देते थे कि हो सकता है जैसे बबखाल पुल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही रोक रखा है। लेकिन इस बार आपने बबखाल पुल

का ज़िक्र ही नहीं किया। बैरी-दरोला पुल का ज़िक्र आपने इस बार किया जिस पुल का शिलान्यास आपने 15 साल पहले किया था। लेकिन वह जगह आज तक अक्वायर नहीं हुई है। डी.पी.आर. बनने के लिए मैंने उस पुल को एम.एल.ए. प्रॉयरिटी में डाला था। 6 सालों तक वह पुल न बन पाने के कारण आज वह बजट की एम.एल.ए. प्रॉयरिटी में भी नहीं है। आप वहां घोषणा कर आए कि वहां पर जगह अक्वायर करके सड़क बनाएंगे और उसको फोरलेन से जुड़ेंगे। आप भी

28.03.2016/1545/SLS-DC-3

ऐसी सनसनीखेज़ बातें मत किया करो। इससे लोगों में एक अनिश्चितता का वातावरण बनता है। आपका कैरियर बहुत लंबा रहा है। जो क्रैडिबिलिटी आपने सारे प्रदेश के अंदर प्राप्त की है, इस अंतिम समय में आप उसको लूज कर रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मेरा आपसे यह कहना है।

अध्यक्ष महोदय, चौंताधनी पुखर रोड का मैं ज़िक्र करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : अरे, अगर हमारी क्रैडिबिलिटी नहीं है तो फिर हम पंचायती राज चुनावों में क्यों जीते? फिर धर्मशाला में आपका सफाया कैसे हुआ? ...(व्यवधान)... हम जीते हैं और फिर भी आप हमारी क्रैडिबिलिटी की बात करते हैं।

श्री रिखी राम कौंडल: मैं चुनावों की क्रैडिबिलिटी की नहीं बल्कि आपकी घोषणाओं की क्रैडिबिलिटी की बात कर रहा हूं। जो आप घोषणाएं करके आते हैं और जो पूरी नहीं होती, मैं उस क्रैडिबिलिटी की बात कर रहा हूं। आप झूठी घोषणाएं मत कीजिए। ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : सुनिए, आपने बबखाल पुल की बात की। अगर वहां पर बनाने वाले ने टैक्निकल गलती की, पूरी खुदाई नहीं की, तो उसमें सरकार का कसूर तो नहीं है? उसके बाद आपकी सरकार आई लेकिन आपने 5 सालों तक उसमें कोई काम ही नहीं

किया। आप उसको रद्द करते और दूसरी जगह बनाते या उसका टैंडर दोबारा करते।

श्री रिखी राम कौंडल : जब उसका फाऊंडेशन आपकी सरकार के वक्त रखा गया। उस समय आपके टैक्निकल अफसर कहां थे जब उन्होंने वहां पर कॉलम खड़े करने शुरू किए? आज बबखाल पुल को लेकर कोटधार के अंदर एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

जारी ...गर्ग जी

28/03/2016/1550/RG/AG/1
श्री रिखी राम कौंडल के पश्चात

मुख्य मंत्री : मैं आज भी कहता हूं कि बबखाल का पुल बनना चाहिए। यह बहुत जरूरी है उस क्षेत्र के लिए। अगर टैक्नीकल फॉल्ट के कारण पहली जगह पर नहीं बन सका, कोशिश करेंगे कि उसी के बगल में दूसरा पुल बनाया जाए। इसके लिए अभी सरकार कार्रवाई कर रही है।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, यदि उसमें टैक्नीकल कमी है, तो सारी फॉमल्टीज पूरी करने के बाद ही हमेशा फॉउन्डेशन स्टोन रखा जाता है। जब उसमें टैक्नीकल गल्ती थी, तो how the foundation was laid और उस सारे क्षेत्र के अंदर एक ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया कि आपको बोलते हैं कि वे पुल नहीं बना रहे हैं, हमें बोलते हैं कि पुल नहीं बना रहे हैं। इसके बारे में गंभीरता से विचार करिए कि वह पुल कैसे बनेगा।
अध्यक्ष महोदय, जहां तक चौंताधड़ी पुखर सड़क का प्रश्न है, मैंने एक प्रश्न इस विधान सभा में किया था। उस प्रश्न का मुझे उत्तर मिला कि उस सड़क पर कोई अनियमित्ता नहीं हुई। मैंने उस पर आधे घण्टे की चर्चा मांगी थी। मेरी सूचना के मुताबिक 'नाबार्ड' का कोई भी टेण्डर स्पिलिट करने के लिए जब तक मुख्य अभियन्ता की अप्रूवल न हो, तब तक उसको स्पिलिट नहीं किया जा सकता और वह 'नाबार्ड' का सारा काम चौंताधड़ी पुखर पर छोटे-छोटे कामों में स्पिलिट करके दिया। उसमें अनियमित्ताएं हुई हैं और उस पर सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी इस माननीय सदन में

यह मांग है कि उस सड़क पर जो मुख्य अभियन्ता के बिना अनुमोदन के 'नाबार्ड' का काम स्पिलिट हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए। तब पता लगेगा कि अपने चहेते आदमियों को काम देने के लिए वह सारा काम स्पिलिट किया गया।
अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि हमारी एक सड़क और से बीजापुर और घालिया तक की सड़क है। अभी पीछे सर्दियों में उसकी कारपेटिंग हुई है। आज उस सड़क की आप इन्क्वायरी कर लीजिए कि क्या हालत है? सारी-की-सारी उसकी कारपेटिंग उखड़ गई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 'नाबार्ड' की हमारी एक सड़क मुरथल रोड है जिस पर एफ.सी.ए. क्लीयरैंस है और आप कहते हैं कि हमने सड़कों का बहुत विस्तार किया है।

28/03/2016/1550/RG/AG/2

एफ.सी.ए. क्लीयरैंस होने के बाद डेढ़ साल से वन विभाग को पैसा नहीं दिया गया और लोग उस सड़क से महरूम हैं।
अध्यक्ष महोदय, ऐसी अनेकों सड़कें हैं जिन पर सारे चुनाव क्षेत्र में पूरे हिमाचल में जो सड़कों की दुर्दशा बनी हुई है, इसके लिए ये प्रदेश का एक बार बाई रोड भी भ्रमण करके देख लें, तभी इनको यह पता लगेगा कि जो अधिकारी इनको यहां ब्रीफ करते हैं, वहां वस्तुस्थिति कुछ और है और यहां कुछ और है। इसी प्रकार से हमारे यहां पम्प हॉऊस तक सड़क है जोलपीरथान। मैंने बार-बार इस सदन में विषय उठाया, लेकिन आज तक उस पर भी कोई छानबीन नहीं की गई और वह सड़क बनाने के दो महीने के बाद ही उखड़ गई। ऐसी सड़कों की हालत जिस प्रदेश में हो और उस प्रदेश में आप accountability की बात करते हैं। यह सत्ता तो आती-जाती रहती है, कभी एक आएगा, कभी दूसरा आएगा। लेकिन प्रदेश में चाहे सड़कों के निर्माण के बारे में वातावरण हो, चाहे और किसी काम के बारे में प्रदेश का वातावरण जो बिगड़ेगा, उसको सुधारने के लिए बहुत समय लगता है।
अध्यक्ष महोदय, श्री महेन्द्र सिंह जी ने यहां विस्तार में बहुत सी बातें कह दी हैं। इन 3-4 सड़कों का मैंने जिक्र किया जिनकी हालत बहुत खराब है। मैं पुल के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे यहां एक बैरीद्रोला पुल है जिसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी वहां

बोलकर आए हैं, मैं चाहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र उसकी जगह acquire हो और उसकी डी.पी.आर. बने और वह पुल बने और जो फोन लेन से जोड़ने का इनका वायदा है, इस चुनाव से पहले-पहले आप अपने उस वायदे को पूरा करिए ताकि आप पर जो विश्वास लोगों का बना है, वह बना रहे और वह विश्वास आप पर से न उठे। इसके अतिरिक्त आपने मेरे चुनाव क्षेत्र में जो घोषणाएं की हैं, उन पर भी थोड़ा अमल करिए। इन घोषणाओं से सरकार चलने वाली नहीं है। अनेकों बातों का जिक्र श्री महेन्द्र सिंह जी ने कर दिया है। इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। अपने कटौती प्रस्ताव की चर्चा पर जो मैंने यहां 4-5 बातें रखीं है उन पर ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक प्राथमिकता के बारे में बात करना चाहूंगा। हम विधायक प्राथमिकता में जिन सड़कों का नाम देते हैं उनकी डी.पी.आर. नहीं बनतीं। आप हर बार अपनी मीटिंग में कहते हैं कि ऑउटसोर्सिंग कराएंगे, डी.पी.आर. बनाएंगे और हर एक साल के बाद फिर मीटिंग होती है। इस बार हमने इसलिए इस मीटिंग में आना अच्छा नहीं समझा कि जब मीटिंग में आने पर हमारी प्रपोजल्ज

28/03/2016/1550/RG/AG/3

लेकर भी डी.पी.आर्ज. नहीं बनती हैं, तो इससे बेहतर है कि एक या दो दिन का जो पैसा हमें आने-जाने का मिलेगा उसको लेने का भी कोई ओचित्य नहीं बनता था। इसीलिए हमने ये बैठक अटैन्ड नहीं की। ये डी.पी.आर. चाहे ऑऊटसोर्सिंग से कराइए, यदि आपके पास स्टाफ कम है, तो ऑऊटसोर्सिंग के माध्यम से डी.पी.आर. बनवाएं ताकि विधायक प्राथमिकताओं की सड़कें तैयार हों। 4-4, 5-5 सालों तक डी.पी.आर. ही नहीं बनती और उसके बाद ऑटोमैटिकली 6 साल के बाद वे एम.एल.ए. प्रायोरिटी से डिलिट हो जाती हैं। या तो उनको डिलिट न किया जाए या फिर उनकी डी.पी.आर. बनाकर उनका काम तुरन्त शुरू किया जाए। सड़कों की हालत प्रदेश में बहुत खराब है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि इनका सुधार करिए

एम.एस. द्वारा जारी

28/03/2016/1555/MS/AG/1

श्री रिखी राम कौंडल जारी----------

और पिछले सत्र में आपने कहा था कि जहां-जहां कारपेटिंग उखड़ी है, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। मेरे चुनाव क्षेत्र की चार-पांच सड़कों का मैंने जिक्र किया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कोई विधायक अपने क्षेत्र से संबंधित कोई विषय उठाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कम-से-कम लोगों में एक विश्वास हो कि यह सरकार कार्रवाई करती है। परन्तु मुझे कोई भरोसा नहीं है कि आपकी तरफ से हमें कोई इन्साफ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

28/03/2016/1555/MS/AG/2

अध्यक्षः अब श्री इन्द्र सिंह जी मांग संख्या -10 पर हो रही चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मांग संख्या- 10 पर हमने जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, कौंडल जी ने सही कहा कि सड़कें हमारे प्रदेश की जीवन रेखाएं हैं। वायु मार्ग तथा रेल की सुविधा न होने के कारण यहां पर एकमात्र आने-जाने का साधन केवल सड़कें ही हैं। लेकिन आज हमारी सड़कों की क्या हालत है, माननीय मुख्य मंत्री जी हाल ही में मेरे चुनाव क्षेत्र में गए थे, उन्होंने देखी होगी। सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि पता ही नहीं चलता कि सड़कें गड्ढों में हैं या गड्ढे सड़कों में हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में मात्र दो सड़कें ऐसी हैं जो विश्व बैंक की मदद से बन रही हैं। वे आइडियल सड़कें हैं जिनके पुलों का माननीय महेन्द्र सिंह जी ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है कि एक महीने के अंदर-अंदर 100 मीटर वाला पुल तैयार हो जाता है। आपके पुल बनने में दस-दस

साल ले लेते हैं। कभी ग्राउंड वाटर का डाटा चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। बाई द टाईम XEN उस पर एक्शन करता है तो उसकी बदली हो जाती है। There is no system as such. जो काम करे, ऐसा मैं समझता हूं। यह सिस्टम टोटली पैरालाइज्ड हो गया है। ऐसा मेरा मानना है। इसको करैक्ट करने की जरूरत है। महेन्द्र सिंह जी ने यह भी कहा कि आपका प्लान का ले-आउट तो बढ़ा लेकिन मण्डी जोन के लिए जो पिछले साल का ले-आउट था, उसको आपने इस वर्ष कम कर दिया है। क्या मण्डी जोन की सारी सड़कें ठीक हैं? आप एक नज़र से सबको देख रहे हैं या नहीं? मेरे ख्याल में यह उस क्षेत्र के लिए अन्याय है। पिछले तीन सालों में मेरे चुनाव क्षेत्र में मात्र एक सड़क की डी0पी0आर0 बनी है। How we can face the public? You tell me, Sir. अगर आप एक नजर से देखेंगे तो ऐसा कैसे होगा? कइयों की पांच-पांच डी0पी0आर्ज0 बन गई हैं और कइयों की एक भी नहीं बनी है। इतनी डिस्पैरिटी क्यों है? आपका सिस्टम टॉप हैवी सिस्टम है। आपके विभाग में XEN, SE और चीफ इंजीनियर भरे पड़े हैं लेकिन ग्राउंड लैवल पर काम करने वाला न आपका सर्वेयर है, न आपके पास ड्राफ्ट्स मैन है और न जे0ई0 है। अगर

28/03/2016/1555/MS/AG/3

जे0ई0 एक डिवीजन में है तो सारे के सारे प्रमोटी हैं। प्रमोटी जे0ई0 don't know how to prepare the DPRs. कम से कम डायरैक्ट एंट्री वाले भी वहां भेजिए।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

There is absolutely lack of planning in this Department. फिर आप पैसा एकमुश्त रखे हुए हैं। जिस XEN को पता ही नहीं है कि मेरे डिवीजन में कितना पैसा खर्च करना है, मैं एकॉर्डिंगली वर्कआउट करूं तो वह कैसे करेगा जब उसको रिसोर्सिज का पता ही नहीं है? ये मैंने कुछ बातें आपसे कहनी थी।

उपाध्यक्ष जी, जो हमारी सड़कें खराब हैं उनकी वजह से हमारी बहुत सी चीजों पर असर पड़ रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में जितनी भी इण्डस्ट्रीज लग रही हैं वे पैरीफरी में लग रही हैं। सेंट्रल हिमाचल में एक भी इण्डस्ट्री नहीं लग रही हैं Where is

the source of employment? ये सड़कों की वजह से है क्योंकि आना-जाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने उद्योगपतियों से बात की है। वे कहते हैं कि आप पहले अपनी सड़कें ठीक करो, आने-जाने के साधन ठीक करो Our time is precious. Our time is money. आपकी सड़कों में आधा आदमी मर जाता है। मुख्य मंत्री जी, आप बाई एयर जाते हैं आप जरा सड़कों पर घूमकर देखिए। आप पराली तो जाते हैं लेकिन थाली जाकर देखिए कि नीचे क्या हालत है। It is very sad state of affairs. आपके विभाग की वजह से हर साल हमें गाड़ी बदलनी पड़ती है। Kindly look into this aspect. मैंने इण्डस्ट्रिलाइजेशन की बात की। हमारे बच्चों को नौकरियां ही नहीं हैं। क्योंकि आने-जाने के साधन ही नहीं है। इण्डस्ट्रीज बरोटीवाला की पैरीफरी में लग रही है या उधर नगरोटा पैरीफरी में लग रही हैं और सेंट्रल हिमाचल में जीरो है। No source of employment. ये सब आपकी सड़कों की नालायकी की वजह से है। ऐसा मैं मानता हूं। मेरी 43 सड़कें ऐसी हैं जिनकी डी0पी0आर्ज0 ही नहीं बनी हैं। How to invest money on those roads जब डी0पी0आर्ज0 ही नहीं बनी है। अनुसूचित जाति के लिए आपने 497 करोड़ रुपये का ले-आउट किया हुआ है। पिछले साल हमें केवल एक करोड़ 37 लाख रुपया मिला है जिसमें से 94 लाख रुपये खर्च हुआ है और टोटल ले-आउट आपका तकरीबन 400 करोड़ रुपये से ऊपर था।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

28.03.2016/1600/जेएस/एएस/1

श्री इन्द्र सिंहः-----जारी-------

यह क्या है? Is it the equal distribution. 40 सड़कें मेरी अनुसूचित जाति में ऐसी हैं जिनकी डी0पी0आर0 ही नहीं बन रही है। मामूली सी बात है। उन सड़कों पर गाड़ियां भी चल रही है, लेकिन डी0पी0आर0 नहीं बन रही है। who is responsible for this. ये आप सोचिए। मेरे ख्याल से यह जो बजट बनता है it is only on papers and there is nothing in the ground. आप ग्राऊंड में जा करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि उन क्षेत्रों की हालत क्या है? महेन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा कि डंगे लग रहे हैं और मैंने अपने डिविज़न को डंगा डिविज़न कहा था। हमारे एक कहावत है कि सरकाघाट का

डिविज़न डंगा डिविज़न है। It is not Sarkaghat division. उसको करैक्ट करिए। वे जो डंगे लगते हैं और मैंने पिछले बजट सैशन में कहा कि एक डंगा ऐसा लगा किसी के आंगन को बनाने के लिए वह केवल 25-50 मीटर लम्बा डंगा लगा दिया और 5 मीटर ऊंचा लगा दिया। किसी की मदद करने के लिए यह किया गया। पी0डब्लयू0डी0 विभाग ने वह डंगा खुद लगाया। That is surprising me बाकी डंगे सब कान्ट्रेक्टर के माध्यम से लगते हैं और वह डंगा उन्होंने खुद लगा दिया। खुद क्यों लगा दिया? क्योंकि फिर कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। पेमैंट तो विभाग अपने आप करेगा। ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी है और उसमें अभी तक कोई इन्क्वायरी बगैर नहीं हुई है। मैंने पीछे भी कहा था कि ये जो ठेकेदार हैं ये सभी सबलैट करते हैं। जो बड़ी मछलियां हैं वे सारा कुछ इकट्ठा कर लेती हैं। 10-15 ठेके ले लेते हैं और बाद में अपने मित्रों को सबलैट करके डिस्ट्रिब्युट करते रहते हैं और अपना कमीशन घर में बैठे-बैठे 10-15 परसेंट खा रहे हैं। अब देखिये कितना ठेका होता है और 15 परसेंट वह ठेकेदार उसमें से खा जाएगा। जिसने ठेका एग्जिक्युट करना है वह भी कुछ खाएगा। ग्राऊंड में क्या लगेगा और कुछ पैसा इधर-उधर जाता है वह आपको भी पता है कि कहां जाता है? यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर ग्राऊंड पर क्या लेगेगा? Where is quality? 7 करोड़ 42 लाख रूपया मेरी सड़कों पर एनुअल सरफेसिंग और पैच वर्क के लिए खर्च हुआ और 15

28.03.2016/1600/जेएस/एएस/2

दिन के अन्दर-अन्दर सारी की सारी सड़के वॉश आऊट हो गई। कहां पर गुणवत्ता है? पूरे क्षेत्र में कोई गुणवत्ता नाम की चीज़ नहीं है। न कोई वहां किसी को पूछता है। हम सड़कों में घूमते हैं तो हम एक्सिन को फोन करते हैं कि फलां सड़क है। दुर्गापुर से लेकर एक सड़क थाना तक आती है। वहां पर पांच दिन पहले सरफेसिंग हुई थी और वह पांच दिन के बाद उखड़ गई। मैंने एक्सियन को कहा कि आप यहां आ करके इसको देखिए। Why don't you look after this? और उस ठेकेदार को पेमैंट नहीं करनी है।

अब आगे से कोई ज़वाब ही नहीं है सिर्फ हां जी, हां जी करते हैं और काम के लिए न जी, न जी करते हैं। यह टोटल सिस्टम आपका फेल्योर है। आप इसको एन्श्योर करो कि जितना पैसा ग्राऊंड पर लगे उस पैसे से गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। मेरे चुनाव क्षेत्र में तो कोई गुणवत्ता नहीं है। कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जितना वर्क एग्जिक्युट करने में पैसा लगेगा वे अण्डर बिड करते हैं और जानबूझ कर अण्डर बिड करते हैं। जब अण्डर बिड करते हैं तो काम नहीं करते हैं। दो-ढाई परसेंट तो उनकी सिक्योरिटी होती है। They surrender the security very easily. आपका सारे का सारा सिस्टम एक साल के लिए डिले हो गया और एक साल में इन्फ्लमेशन कितनी होगी? आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं। जो काम ग्राऊंड पर होना है वह ग्राऊंड पर नहीं हो रहा है। क्योंकि there is monitoring at all. जब मॉनिटरिंग ही नहीं है तो इतना पैसा पी0डब्ल्यू0डी0 क्यों खर्च कर रही है? ऊपर सब है और ग्राऊंड में काम करने वाला कोई नहीं है। आपके पैरामीटर्ज होने चाहिए। It is a pyramidal structure. मगर बेस में काम करने को बहुत है।। और उल्टा इन्वर्टिड पैरामिड बन गया आपका टॉप हैवी है और ग्राऊंड पर काम करने वाला कोई नहीं है। आप जा करके देखिए। ग्राऊंड में क्या हालत है? जब कोई आदमी रिटायर हो जाता है तो उसके साथ पोस्ट भी रिटायर हो रही है। आप उस काम को ठेकेदार को दे रहे हैं और वह मजे मार रहा है। ये सारे काम बिल्कुल गलत हो रहे हैं। मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी एक और विनती है कि पी0डब्ल्यू0डी0 के पास हम पैसा जमा करवाते हैं काम करने के लिए। मेरे

28.03.2016/1600/जेएस/एएस/3

डिविज़न में if you inquire, जितना पैसा एम0एल0ए0 हैड से, एम0पी0 हैड से और डी0सी0 हैड से पी0डब्ल्यू0डी0 को गया है, लेकिन वे कोई काम नहीं करते हैं। 5 लाख 10 लाख छोटा-छोटा काम होता है but work not to be executed. हम पी0डब्ल्यू0डी0 की तरफ देखते हैं कि यह ईमानदार ऑर्गेनाईजेशन है। let them do it properly. They have got the technical know-how. लेकिन वे काम ही नहीं करते

और वे ठेकेदार को काम दे देते हैं और ठेकेदार उनके ऐसे ही घूमते रहते हैं और वे काम नहीं होते हैं। इस तरह से इन्फ्लमेशन हो जाती है और बाद में उस काम को और पैसा देना पड़ता है। You kindly look after this also.

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

28.03.2016/1605/SS-AS/1

श्री इन्द्र सिंह क्रमागतः

पी0डब्ल्यू0डी0 ने वह बिल्डिंग बनानी है लेकिन नहीं बन रही है। वैसे-का-वैसा ही शिलान्यास पड़ा हुआ है। आपने सरकाघाट में कार पार्किंग का शिलान्यास रखा उसका भी कुछ नहीं हुआ। जितने भी कार्यों के शिलान्यास आपने किये हुए हैं no work is being executed on the ground. जब तक वह काम एग्जीक्यूट होगा, जितने का वह कंट्रैक्ट है बाद में उस पर डबल पैसा लगाना पड़ेगा। that is why there is failure in every front. इसलिए इसकी मोनिटरिंग की विभाग में बहुत ज़रूरत है। बिना मोनिटरिंग के कोई काम प्रॉपर नहीं हो रहा है और न मोनिटरिंग अच्छी हो रही है। आपका गुणवत्ता देखने वाला यानी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमैंट है That is defunct or they are in league with the PWD Department और वे जमीन पर काम नहीं करते। आते हैं और चाय वगैरह पीकर तफरी करके चले जाते हैं और ठेकेदारों की चांदी है। 31 मार्च को ठेकेदारों को पेमैंट हो जाती है और उनकी चांदी हो जाती है जब सारा कुछ क्लॉज होता है। ग्राऊंड पर कुछ भी क्लॉज नहीं होता लेकिन पेपर पर सब क्लॉज हो जाता है। Kinldy look into this. मैं समझता हूं कि आपने जो बजट में अमाऊंट रखा हुआ है इस अमाऊंट को रिडयूस करके एक रुपया कर दिया जाए। It is not worth to spend the money like that.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2016/1605/SS-AS/2

उपाध्यक्षः श्री विजय अग्निहोत्री जी।

श्री विजय अग्निहोत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-10, लोक निर्माण सड़क, पुल एवं भवन कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी इस विषय पर काफी बातें सरकार के ध्यान में लाई हैं। जैसे कर्नल इंद्र सिंह जी ने कहा कि जो काम ग्राऊंड पर हो रहा है उसकी मोनिटरिंग करने के लिए कोई नहीं है। वह डिपार्टमैंट बिल्कुल डिफंक्ट है। आज सड़क का काम होता है और एक महीने के बाद वह उखड़ जाती है तो इसकी अकाऊंटेबिलिटी और रिस्पोंसिबिलिटी किसकी है यह फिक्स करने की आवश्यकता है। किसी की जवाबदेही नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह जो पी0डब्ल्यू0डी0 का रिपेयर एंड मैंटीनेंस का बजट है यह पूरा एक भ्रष्टाचार का माध्यम है। रिपेयर मैंटीनेंस में पैसा आता है, हम यहां पूछते हैं कि किस सड़क में कितना खर्च हुआ तो कागज़ों में आ जाता है लेकिन ग्राऊंड पर कुछ खर्च नहीं हुआ होता है। शो किया जाता है कि अप्रैल, मई या जून में सड़क की रिपेयर की थी लेकिन जुलाई में बारिश पड़ी तो उसमें धुल गई। उसके बीच में कहां क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता। इस करके अकाऊंटेबिलिटी फिक्स करने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति, ठेकेदार, डिपार्टमैंट काम कर रहा है वह उसके लिए जिम्मेवार हो ताकि कम-से-कम कितने समय तक वह सड़क बनी रहे, उसकी जिम्मेवारी हो कि वह उसे मैंटेन रखे। ऐसे ही चाहे भवन निर्माण की बात है या सड़कों की है इस प्रदेश में जो सड़कों की हालत है वह किसी से छुपी नहीं है। हमारे जिला में भी और मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी यहां से बोलते हैं कि पी0डब्ल्यू0डी0 के लिए इतना बजट हो गया, रोडस के लिए हो गया है, नाबार्ड में फलांनी सड़क आ गई लेकिन ग्राऊंड लेवल की रिपोर्ट क्या है, वहां क्या काम हो रहा है उसके विषय में सोचने वाला और फोलो अप करने वाला डिपार्टमैंट कुछ नहीं करता है। मेरा यह सीधा आरोप है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की कई सड़कें ऐसी हैं जिनकी नाबार्ड के तहत फंडिंग है। 2012 में उसका टैंडर हुआ है। 2014 में उसका कम्प्लीशन टाइम है। लेकिन 2016 तक उसमें काम ही शुरू नहीं हुआ है। मैंने

पीछे भी एक प्रश्न किया था। हमारी भी एक सड़क मैड-बडूलडे-जियाना-सुकराला-टिक्कर है। 2012 का उसका टैंडर है। आज तक उस पर बिल्कुल नैग्लीजिबल काम हुआ है। अब जब प्रश्न किया तो उन्होंने लिख कर दे दिया कि अक्तूबर, 2016 तक पूरा कर देंगे। लेकिन काम आज भी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे ही

28.03.2016/1605/SS-AS/3

पी0एम0जी0एस0वाई0 में बहुत-सी सड़कें हैं जिनका स्टेज-I का काम हो गया है। लेकिन उसको 10-10 साल हो गये, एक थाईमोड-सोरीजोल-सपड़ की पी0एम0जी0एस0वाई0 में सड़क है, उस सड़क का दूसरे फेज का काम शुरू नहीं हुआ। वह डी0पी0आर0 ही नहीं गई।

जारी श्रीमती के0एस0

28.03.2016/1610/केएस/डीसी/1

श्री विजय अग्निहोत्री जारी---

जो खर्चा हुआ है उसका क्या लाभ है? ऐसे ही एक पंसाई-रामनगर-मंझेली-तरकेड़ी-भूंपल सड़क है। मैं हर बार इस विषय को उठाता हूं। करोड़ों रु0 इसके ऊपर खर्च कर दिए हैं। इसके दोनों तरफ दो पुल बनने हैं। वे दोनों पुल आज तक बन कर तैयार नहीं हुए हैं। छः साल से उस सड़क का काम चल रहा है। एक पुल है जिसका काम चार ठेकेदार छोड़कर चले गए। न जाने विभाग क्या करता है, क्यों वह पुल नहीं बन रहा है और उस ठेकेदार की क्या रिस्पोंसिबिलिटी है, क्या अकाऊंटेबिलिटी है? दो साल फिर टैंडर करने के लिए लग जाते हैं और जब ठेकेदार आता है, वह काम नहीं करता है। एक और पुल है, अभी पीछे मैंने उसके बारे में प्रश्न किया था जिसका जवाब आया कि फ्लां व्यक्ति उस पुल के लिए जमीन नहीं दे रहा है। मैं तीन वर्ष से विधायक प्राथमिकता में जो सड़कें डाल रहा हूं उन सड़कों में से एक की भी डी.पी.आर. नहीं बनी। जब विभाग से बात की जाती है तो कहते हैं कि जमीन का मामला नहीं सुलझ रहा है । अब अगर डी.पी.आर. जमीन के मामले के बिना नहीं बन रही है तो जो पहले डी.पी.आर. बनी हैं, उनमें क्या जमीन का ध्यान ही नहीं रखा गया था? अगर उस समय डी.पी.आर. बनी थी और जमीन के बारे में कोई अंडरटेकिंग ली थी, कोई ऐफिडेविट लिया था,

जमीन एक्वायर की थी या कुछ और किया था तो वह पुल क्यों नहीं बन पा रहा है? उस पुल के बिना वह सड़क बेमानी है, उसकी कोई रैलीवैंसी नहीं है। ऐसे अनप्रोडक्टिव खर्चा करने से इस प्रदेश के विकास को धक्का लग रहा है। जो सड़कें हैं, भवन है या पुल हैं, इन सबके लिए कोई दिशा नहीं है, कोई अकाऊंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पोंसिबिलिटी नहीं है। एक पी.एच.सी. कांगू की बिल्डिंग पी.डब्ल्यू.डी. विभाग बना रहा है। पिछले साल कहा गया था कि हम इसमें सितम्बर में शिफ्ट कर देंगें, इसका काम पूरा हो जाएगा लेकिन आज तक वह नहीं हो पाया। सी.एच.सी. नादौन की बिल्डिंग का काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। एक वहां पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल है, उसकी साईंस लैब को बनते हुए 15 साल हो गए हैं। उसका काम कम्पलीट ही नहीं हो रहा है। विभाग क्या कर रहा है? जैसे अभी यहां पर कहा गया कि सिर्फ बजट बुक में लिखने

28.03.2016/1610/केएस/डीसी/2

से सारी चीजें सॉल्व नहीं होंगी। सड़कों की हालत खस्ता है, हम गाड़ी में बजट बुक रख कर घूमते रहें कि जम्प नहीं लगेंगें लेकिन जम्प तो लगेंगें क्योंकि वहां पर गड्ढे हैं। उनको भरना पड़ेगा, उसको बजट बुक नहीं बचाएगी़ उसके लिए ग्राऊंड लैवल पर कार्य करने की आवश्यकता है और जिसने काम किया उसकी रिस्पोंसिबिलिटी, अकाऊंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कई सड़कें ऐसी हैं जिनका हर साल काम होता है और एक ही ठेकेदार काम करता है और वह हर साल ही उखड़ती है। लोक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस विभाग में जैसे अभी कहा गया कि रिटायरमैंट के साथ ही पोस्ट भी रिटायर हो जाती है। फंक्शनल पोस्टें बिल्कुल खत्म होने के कगार पर पहुंच गई हैं। वहां कोई बेलदार नहीं है, दफ्तर में सर्वेयर नहीं है और सारी फंक्शनल पोस्ट्स खाली होती जा रही है। इसलिए डी.पी.आर. कब बनेगी, उनके ऊपर केस कब जाएगा, नाबार्ड में कब पास होगा, कब अप्रूवल होगी, कब उसके ऊपर पैसा आएगा, कब सड़कें बनेगी? हम यहां विधायक प्राथमिकता में सड़कें दे कर जाते हैं और चुनाव क्षेत्र में जा कर कह देते हैं कि आपकी सड़क हमने नाबार्ड में भेज दी है, विधायक प्राथमिकता में डाल दी है,

आपकी सड़क बन जाएगी और लोग बाद में हमें पूछते हैं। इसलिए पारदर्शिता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार को काम करने की आवश्यकता है जो यह सरकार नहीं कर पा रही है। सड़कों की बहुत बुरी हालत है। उनमें गड्ढे हैं। बार-बार उन सड़कों के नाम इस सदन में लेने की आवश्यकता भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में पुलों की बात रखी हैं और ये पुल क्यों नहीं बन पा रहे हैं इसमें पता नहीं सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है या विभाग की इच्छा शक्ति की कमी है। जब इच्छा शक्ति सरकार में या विभाग में होगी तो काम होते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में रंगस का पुल नेशनल हाईवे के ऊपर बना है, वह रिकॉर्ड छः महीने में बन कर तैयार हुआ है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.3.2016/1615/av/डीसी/1

श्री विजय अग्निहोत्री------ जारी

वह भी तो किसी ने बनाया है। वह आदरणीय धूमल जी के नेतृत्व वाली सरकार में बनकर तैयार हुआ है। अगर इतना बड़ा पुल 6 महीने में बनकर तैयार हो सकता है तो दूसरे छोटे-छोटे पुल बनकर तैयार क्यों नहीं हो सकते? विभाग की यह हालत है कि जो विधायक निधि से पैसा दिया होता है उसके टैंडर करने में भी दो-दो साल का समय लग जाता है। जब दो साल के बाद टैंडर लगता है और आगे ठेकेदार को काम दिया जाता है तो उसको यह कहा जाता है कि यह काम नहीं करना है क्योंकि इस काम में विपक्ष के विधायक निधि का पैसा है। अगर सरकार और विभाग इस सोच के साथ चलेगा तो विकास नहीं हो पायेगा। ऐसा होने पर घाटा तो जनता का होता है जिसको सेवाएं/सुविधाएं समय पर नहीं मिलती। आज जनता यह सब समझती है कि यह काम किसके कारण से नहीं हो रहे हैं। अगर ये चीजें ठीक नहीं हुई तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत जल्द विपक्ष की तरफ आने वाले हैं। मैंने जो आपके सामने बातें रखी हैं इनकी ओर सरकार को ध्यान देने तथा प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने की आवश्यकता है। होना तो यह चाहिए था कि इतने वर्षों से विभाग जो मुख्य मार्ग और नेशनल हाई-वे का काम कर रहा है उसके साथ-साथ गांव के छोटे-छोटे रोड्ज को टेक-ओवर करते

हुए उनकी चिन्ता भी करता। मगर हम तो अभी मुख्य सड़कों को ही मैंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मुख्य सड़कें टूटी हुई हैं। हर जगह सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। जिस गांव में हम जाते हैं तो वहां लोग पूछते हैं कि आप सड़क से होते हुए आए? आपने सड़क का हाल देखा? अगर ऐसी ही हालत रही तो हमें मजबूरन सड़कों पर आन्दोलन करने के लिए उतरना पड़ेगा। इसलिए मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि प्रदेश में सड़कों, पुलों और भवन निर्माण की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। इसमें बजट ठीक लगे तथा उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स की जाए ताकि हर चीज की इम्प्लीमैंटेशन ठीक हो और लोगों को इसका लाभ मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

28.3.2016/1615/av/डीसी/2

श्री बिक्रम सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-10 : लोक निर्माण -सड़क, पुल एवं भवन पर जो कटौती प्रस्ताव आया है मैं उस पर बोलने के लिए ख़ड़ा हुआ हूं। आपने बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

आज बड़ा हर्ष का विषय है कि इस सैशन में पहली बार मैं बोल रहा हूं और मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। यहां पर लोक निर्माण विभाग के विषय पर काफी चर्चा हुई है। विभाग किस ओर जा रहा है; इस बारे में आदरणीय महेन्द्र सिंह जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से चर्चा की है। इसमें क्या-क्या कमियां हैं उस बारे में चर्चा की है। जिस समय किसी मंत्री के विभाग की कमियों की चर्चा होती है तो मंत्री चिन्ता में जरूर होते हैं और बार-बार उठकर बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तथा ऐसा होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि हम यहां पर जो-जो बातें बोल रहे हैं माननीय मुख्य मंत्री इनका ठीक जवाब दें क्योंकि जिस समय हमारे जवाब की बारी आती है तो इनका समय उससे पहले-पहले खत्म हो जाता है। मैं चाहूंगा, क्योंकि लोक निर्माण विभाग में 3053 करोड़ रुपये का बजट रखा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें से हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंदर कोई पाई भी लगती हो। हमने पिछले तीन वर्षों में विधायक प्राथमिकता में जो सड़कें दी हैं उन सड़कों में से किसी की भी डी0पी0आर0 नहीं बनी है। जब सड़क की डी0पी0आर0 ही नहीं बनेगी तो जो बजट का प्रावधान आपने किया है उस बजट का हमारे विधान सभा क्षेत्र को क्या फायदा होगा? आप शैड्यूल कास्ट कम्पोनैंट प्लान में पैसा रख रहे हैं लेकिन शैड्यूल

कास्ट कम्पोनैंट प्लान के तहत पूरे विधान सभा क्षेत्र में कोई सड़क नहीं बन रही है।

टीसी द्वारा जारी

28.03.2016/1620/TCV/AS/1

श्री बिक्रम सिंह-- जारी

मुझे पता चला मुख्य मंत्री पिछले दिनों जस्वां परागपुर क्षेत्र के दौरे पर गये हुए थे। कोटला के अन्दर इनका कार्यक्रम था और इनको अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा क्योंकि इनको बताया गया कि उस तरफ की सड़कें खराब होने के कारण लोगों में रोष है और इन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। इस प्रकार का जो वातावरण वन रहा है उस वातावरण के पीछे हाथ है क्योंकि मुख्य मंत्री महोदय, फील्ड के अन्दर जाते हैं लोग इनको बताते हैं कि सड़कों की हालत ठीक नहीं है पुलों का निर्माण ठीक नहीं हो रहा है और जो ठेकेदार है वह ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो माननीय मुख्य मंत्री बड़े जोरशोर से बोल देते हैं की मैं एस0डी0ओ0 को जे0ई0, एक्सीयन को एस0डी0ओ0 बना दूंगा। जब आप कहते हैं कि मैंने तो सिम्बोलिक कहा था वैसे ही डराया था अब उनको भी पता लग गया है कि ये केवल डराते हैं ऐक्शन नहीं करते हैं। यही कारण है कि जो सड़क पिछले वर्ष बनती है वह अगले वर्ष टूट जाती है। मैंने विभाग, चीफ इंजीनियर साहब और एक्सीयन साहब को पत्र लिख-लिख कर बताया है कि आपकी नाबार्ड/प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कें एक वर्ष के बाद टूट गई है लेकिन मुख्य मंत्री महोदय के पास इन सारी चीजों को देखने के लिए समय ही नहीं है। आप फॉरेस्ट क्लीयरेंस की बात करते हैं । हर बार प्रश्न लगता है लेकिन मुख्य मंत्री जी का एक ही रट्टा रटाया जवाब रहता है कि काम चल रहा है, कार्रवाई हो रही है और शीघ्र हो जाएगा। मगर होगा कहां से आपके पास वहां पटवारी तो है नहीं । जब आपके पास पटवारी ही नहीं है तो केस कैसे बनेगा? देहरा डिविजन के अन्दर डाडा जो हमारा सब डिविजन है उस सब डिविजन के अन्दर और उसके बाद परागपुर सब डिविजन के अन्दर पटवारी नहीं है और 8-9 सड़कों की फॉरेस्ट क्लीयरेंस पिछले 3 वर्षों से इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां पटवारी ही नहीं है और इनको कोई

चिन्ता ही नहीं है कि पटवारी वहां लगा नहीं है स्टॉफ वहां है नहीं । इन सारी चीजों के कारण बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिनकी हालत खास्ता है। मैं उन सड़कों के नाम भी यहां बताना चाहूंगा- रक्कड-शांतला,बणी-सेरी,बणी-डांगड़ा, सदवां-कलेसर, ग्लोवा-स्लेटी, चिन्तपुरनी से

28.03.2016/1620/TCV/AS/2

तलवाडा,संसारपुर-डाडासिबा, कोटला-अमरोह, कोटला-कानपुर। इन सड़कों के बारे में बार-बार बोलने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय से इस बार एक प्रश्न के माध्यम से पूछा था कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सैंट्रल रोड फंड और इंटरस्टेट कनैक्टिविटी ब्रिज का क्या स्टेट्स है? बड़े दुख का विषय है कि सैंट्रल रोड फंड आज तक जसवां परागपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कोई पैसा ही नहीं आया। वर्ष 2003 की विधायक प्रायोरिटी में चिन्तपुरनी-तलवाड़ा रोड को दिया गया था लेकिन विभाग को बार-बार कहने के बावजूद भी आज तक उस रोड के लिए किसी भी प्रकार का धन मुहैया नहीं करवाया गया। वर्ष 2007 के अन्दर इंटरस्टेट कनैक्टिविटी ब्रिज जो हमारे अमरोह/पंजाब की तरफ जाता है उसके बारे में चर्चा की गई, उसके बारे में विभाग ने 2007 के बाद डी0पी0आर0 बनाने शुरू की और 2015 में विभाग को यह जवाब आ रहा है कि इंटरस्टेट कनैक्टिविटी ब्रिज इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जो सड़क इसके साथ लगते हैं वह मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड नहीं हैं। मुझे यह समझ नहीं आता कि एम0डी0आर0 बताने के लिए विधायक इनके पास जाएगा? इनके पास इतनी इच्छा शक्ति/सोच नहीं है कि इंटरस्टेट कनैक्टिविटी ब्रिज वहीं बनेगा जहां मेज़र डिस्ट्रिक्ट रोड़ होगा। क्या कारण है कि विभाग 2007 से लेकर 2016 तक सोया रहा कि इंटरस्टेट कनैक्टिविटी ब्रिज बनाने के लिए एम0डी0आर0 नहीं बनाया गया और दूसरे तरफ इनके प्रश्न के उत्तर से पता चलता है कि एम0डी0आर बनता कौन सा रोड है। मेज़र डिस्ट्रिक्ट रोड़ घोषित करने के क्या मापदण्ड है? उसमें मादण्ड बताये गये हैं कि जहां ट्रैफिक ज्यादा हो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। इस रोड के साथ भी चिन्तपूरनी माता का मन्दिर लगता है, ज्वाला जी का मन्दिर है और आगे जाकर कालेश्वर महादेव का मन्दिर लगता है तो क्या कारण है कि इस छोटे से रोड को आपने मेज़र डिस्ट्रिक्ट रोड़ घोषित क्यों नहीं किया? मैं चाहूंगा

कि इन सारी बातों को जवाब माननीय मुख्य मंत्री महोदय जरूर दें। इन सड़कों की खास्ता हालत के लिए मुख्य मंत्री महोदय मैंने तो डाडासिबा में धरना दिया और उसके बाद टेरस से लेकर डाडासिबा तक पैदल यात्रा की ताकि आपका विभाग जाए जाये, आप जाग जाये लेकिन आपकी समस्या बहुत गंभीर है आपके पास समय नहीं है, आपका ध्यान दिल्ली में हैं। आपका ध्यान कसिज़ में हैं, आपका ध्यान भष्टाचार में हैं, विभाग अपना भष्टाचार कर रहा है और आप अपना काम कर रहे हैं।

श्री एस0के0एस0 ---- द्वारा जारी ।

28.03.2016/1625/RKS/AG/1

श्री बिक्रम सिंह ...जारी

इसलिए जिस समय आप इस तरफ से अपना ध्यान हटाएंगे, जिस समय आपका ध्यान पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट में जाएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या कारण है? कौन-कौन से ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं जिनके अंदर सैंटर रोड फंड में, इंटर स्टेट कनैक्टिविटी ब्रिज में, एम.एल.एज. प्रायोरटिज के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। केवल एक ही कारण है कि इस विभाग के अंदर मुख्य मंत्री महोदय का किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है।

मुख्य मंत्रीः मैं आपकी प्रोब्लम के बारे में ही पूछ रहा था।

श्री बिक्रम सिंहः सर, इसी काम में जिंदगी बीत गई। आप प्रोब्लम करेंगे, प्रोब्लम को कभी सोल्व नहीं करेंगे।

मुख्य मंत्रीः मैं आपको बता दूं आपके चुनाव क्षेत्र में जो ढलियारा रोड़ है वह प्रधान मंत्री सड़क योजना में मंजूर हो गया है।

Shri Bikram Singh: Sir, Dhaliara is not in my constituency और जो आप बता रहे हैं वह पी.एम.जी.एस.वाई. में मंजूर नहीं हुआ है, वह सेंटर फंड रोड़ में हुआ है। आप

गलत बता रहे हैं। That is in CRF. गडकरी जी, गडकरी जी आप कुछ नहीं। नीतिन गडकरी जी।

मुख्य मंत्रीः राजनीतिक बीमारी का मेरे पास कोई ईलाज नहीं है।

श्री बिक्रम सिंहः मुख्य मंत्री महोदय, मैं यह बात बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि जो चीजें आपने अपने दिमाग में रखी हैं कि इस तरफ के लोग हमेशा ही डिस्ट्रक्टिव बातें करते हैं, इस चीज को आप निकाल दीजिए। मैंने जितनी बातें रखी हैं, आंकड़ों के आधार पर रखी है और कंस्ट्रक्टिव बाते रखी हैं। मैंन आपके ध्यान में यह बातें लाई हैं। आपके पास समय नहीं है। आपके पास झमेला लगा हुआ है, काम चला हुआ है "may be done" इस तरफ ध्यान दो। मैं सचे मन से कह रहा हूं कि

28.03.2016/1625/RKS/AG/2

सी.आर.एफ., इंटरस्टेट कनैक्टिविटी, एम.एल.ए. प्रायोरटी में एक भी सड़क आज तक तैयार नहीं हुई है। एम.एल.ए. प्रायोरिटी की एक भी डी.पी.आर. नहीं बनी हुई है। जिस सड़क के बारे में आप पूछ करके आए हैं वह मेरा विधान सभा क्षेत्र नहीं है। वह देहरा विधान सभा क्षेत्र है। आपने वहां के रोड़ की बात की है। वह भी पी.एम.जी.एस.वाई में नहीं है, सी.आर.एफ. में है। अगर आपका कोई चीफ इंजीनियर, सैक्रेटरी (पी.डब्लयू.डी.) यहां से एक इंटरस्टेट कनैक्टिविटी ब्रिज की डी.पी.आर. भेजते हैं तो मुझे यह समझ नहीं आता कि उनको यह पता नहीं कि इंटर स्टेट कनैक्टिविटी, डी.पी.आर. उस समय तक नहीं मानी जाएगी जब तक यह मेजर रोड़ के साथ जुड़ी नहीं होगी। कुठेड़ा में आप पंडित राम प्रकाश जी के घर में जाकर आए हैं। अब उनकी डैथ हो गई है। वहां जो रोड़ है उस रोड़ में एक ब्रिज है। 5 किलोमीटर का रोड़ है उसके साथ चिंतपुरनी -तलवाड़ा रोड़ है। आपके विभाग ने इस रोड़ को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ में आने के लिए नोटिफिकेशन नहीं की है। सर, मैं बड़ी अच्छी बाते कर रहा हूं और आप इसे पॉलिटिकली बाते बोल रहे हैं। जो बातें मैंने कही है उन बातों की तरफ आप ध्यान दें। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपका विभाग क्या कर रहा है? अब आप फिर कहेंगे कि मैं पॉलिटिकल बातें कर रहा हूं। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा

हूं। मैं चाहूंगा कि जो आपके विभाग के अफसर यहां बैठे हुए हैं, वे डाडासीबा में जाकर देंखें कि जिन लोगों को आप राजनीतिक संरक्षण देते हैं उनके वहां होटल बन रहे हैं और जो होटलों के साथ दीवारें लग रही हैं, वह पी.डब्ल्यू.डी विभाग लगा रहा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे सजा दें। डाडासीबा के अंदर आपका एक जे.ई. सीमेंट बेचता हुआ पकड़ा गया। अब आपने उसको सस्पेंड कर दिया है। यह बातें उस समय होती हैं जब ऊपर से नकेल नहीं कसी जाती। यह बातें तब होती हैं जब आपका ध्यान विभाग की तरफ नहीं होता है। यह बातें उस समय होती हैं जब आपका ध्यान हर वक्त दिल्ली में रहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप दिल्ली का भी ध्यान रखें क्योंकि वहां से भी आपको बचना है परन्तु यहां का भी ध्यान रखें क्योंकि हमसे भी आपको बचना है। अगर आप हमारा

28.03.2016/1625/RKS/AG/3

ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर विधान सभा की जो इतनी अच्छी बातें आती हैं, आपको जो सजैशन जाते हैं उन सजैशन की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं जाता है। मेरा निवेदन है कि जो भी विषय आपके सामने रखे हैं इनका आप समाधान करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2016/1625/RKS/AG/4

उपाध्यक्षः श्री जय राम ठाकुर।

श्री जय राम ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः 10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन इस पर जो कटौती प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं, मैं भी इस पर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक वक्त ऐसा था

श्री एस.एल.एस द्वारा ....जारी

28.03.2016/1630/SLS-AS-1

श्री जय राम ठाकुर...जारी

जब, हिमाचल प्रदेश में सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, उसको मापने का एक पैरामीटर इस विभाग का काम, इसकी गतिविधियां होती थीं कि सड़कें कैसी हैं, सड़कों की लंबाई बढ़ रही है या नहीं और सड़कें अच्छी तरह से मेन्टेन्ड हैं या नहीं। लेकिन वर्तमान सरकार के इस अर्से से इसमें कमी है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं महसूस करता हूं कि सचमुच में आपके पास बहुत सारे विभाग हैं। इस विभाग को प्राथमिकता देने के लिए जो समय की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि उसमें कमी रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में यातायात का साधन मात्र सड़कें हैं। न तो यहां हवाई जहाज का माध्यम है, न समुद्री जहाज का माध्यम है और न रेल का माध्यम है। ऐसी परिस्थिति में लोगों की यात्रा सुखद हो, लोगों की पीठ का बोझ उतरे, उसके साथ-साथ ही इस बात को भी महत्व देने की आवश्यकता है कि हिमाचल प्रदेश, जो पर्यटन नगरी है, जो देवभूमि के नाम से जानी जाती है, यहां पर दुनियां भर के पर्यटक आते हैं, उस दृष्टि से भी यहां पर सड़कों का बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन पिछले 3 साल के कार्यकाल में सचमुच में इसमें निराशा हुई है। यही एक वजह है कि जब विपक्ष की ओर से कटौती प्रस्ताव देने की बात आई तो हमें महसूस हो रहा है कि आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा कोई बात कहने की आवश्यकता है, किसी कटौती प्रस्ताव को प्राथमिकता पर इस माननीय सदन में सरकार के सामने रखने की आवश्यकता है तो सड़कों और पुलों की बात है। बजट के हिसाब से मैं मानता हूं कि ठीक है कि इसमें लगभग 3054 करोड़ रुपये का बजट है, जिसमें से, मैं मानता हूं कि लगभग 85 प्रतिशत सैलरी में चला जाता है। लेकिन उसके साथ-साथ एक बात आती है, जिसका ज़िक्र यहां पर माननीय सदस्यों ने किया। वह बात है कि एक शब्द जिसका ज़िक्र यहां पर एकमुश्त के रूप में किया जा रहा है, एकमुश्त का अभिप्राय हम समझ रहे हैं। हम वर्षों से इस माननीय विधान सभा के सदस्य हैं। इसमें गुंजाईश रहती है।

28.03.2016/1630/SLS-AS-2

जो आपका स्पैस्फिक प्रोजैक्ट है, जिसकी डी.पी.आर. बन कर स्वीकृत हुई है, उसके विरुद्ध आपने बजट प्रोविजन क्या किया, हम तो वह देखना चाहते हैं। जब आप एकमुश्त का ज़िक्र कर रहे हैं तो वह एकमुश्त का ज़िक्र इसलिए होता है कि वह एकमुश्त उधर जाती है और इस तरफ के सारे-के-सारे विपक्ष के विधायक और विपक्ष के विधान सभा क्षेत्र राजनैतिक द्वेष का शिकार बनते हैं। अब बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि ऐसा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों का ज़िक्र करना चाहता हूं। मैंने एक प्रश्न इसी विधान सभा के इस सत्र में लगाया कि मेरे सिराज विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल में सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी? उत्तर आया कि 21 किलोमीटर सड़क बनी। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि 21 किलोमीटर सड़क बनी है। लेकिन फिर मैंने कहा कि सड़कों के नाम भी दो। माननीय मुख्य मंत्री जी, यह सचमुच में चिंता का विषय है। जिन सड़कों का नाम यहां पर दिया गया है, उन सड़कों पर एक गैंती तक नहीं लगी लेकिन कागज़ों में जो उत्तर यहां पर दिया गया, वहां सचमुच में चिंता का विषय है। कहीं कहा गया कि हमने 500 मीटर सड़क बनाई, कुछ जगह कहा गया कि हमने अढ़ाई किलोमीटर सड़क बनाई और कुछ जगह कहा गया कि हमने डेढ़ किलोमीटर सड़क बनाई जबकि सड़क जहां थी वहां से एक ईंच आगे नहीं बढ़ी। मैं इस प्रश्न का उत्तर भी आप तक पहुंचा सकता हूं। यह प्रश्न संख्या 2660 है। वहां लाखों और करोड़ों रुपया ख़र्च हो गया

जारी ...गर्ग जी

28/03/2016/1635/RG/AS/1

श्री जय राम ठाकुर----क्रमागत

लेकिन उसके बावजूद सड़क आगे बनी नहीं, तो वह पैसा कहां गया? सिर्फ कागज़ों में सड़क का निर्माण हो रहा है। यह सचमुच में बहुत चिन्ता का विषय है।

मुख्य मंत्री : प्रश्न संख्या क्या है?

श्री जय राम ठाकुर : सर, यह प्रश्न संख्या 2660 है जो दिनांक 1-03-2016 को लगा है। इसमें हमारे गांव की भी एक सड़क है जो वहीं-की-वहीं है और उसके बारे में भी कहा गया है कि हमने 500 मीटर आगे सड़क बना दी है। यह बहुत गंभीर मसला है। सड़क बनी ही नहीं, वहां काम ही नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, थोड़ा ही कहूंगा। इसके अतिरिक्त एक और प्रश्न लगा था, प्रश्न संख्या 2966 जिसमें मैंने यह पूछा था कि 'क्या यह सत्य है कि वर्तमान लोक निर्माण मण्डल, गोहर से मशीनरी को अन्य मण्डलों में भेजा गया है? यदि हां, तो कब और कौन-कौन सी मशीनरी को अन्य स्थान पर भेजा गया है? इसकी सूचना सभा पटल पर रख दी गई थी। प्रश्न के 'क' भाग का उत्तर आया है 'जी हां'। उसके बाद 'ख' भाग का उत्तर आया है कि गोहर मण्डल से जो मशीनरी अन्य मण्डलों को भेजी गई है उसका ब्योरा निम्न प्रकार से है :- मशीनरी का नाम-टिप्पर नं. HP 32 - A 1173 दिनांक 16-10-2014 को गोहर मण्डल से शिफ्ट करके मण्डल नं.-1, मण्डी में भेजा गया है। मेरे चुनाव क्षेत्र की मशीनरी श्री अनिल शर्मा जी के यहां सड़क बना रही है। वह टिप्पर वहां सड़क बना रहा है। आप (मुख्य मंत्री) तो इनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, लेकिन इस गरीब पर क्या गुजर रही होगी? एक Excavator cum लोडर (dodger) नं. D-50 DG 13677, यह दिनांक 15-10-2014 को गोहर मण्डल से शिफ्ट करके धर्मपुर में भेजा गया।

अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए

अध्यक्ष महोदय, एक और Excavator cum लोडर (dodger) जे.सी.बी. नं. HP 32 B-9807, दिनांक 7-8-2014 को करसोग मण्डल में भेजा गया। मैंने आज भी प्रश्न लगाया था कि एक लोक निर्माण निर्माण के मण्डल में मशीनरी को रखने के क्या नॉर्म्ज हैं? इसमें उसकी डिटेल दी है जिसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी जब हम आपको इस बारे में स्पेसिफिक जानकारी दे रहे हैं, तो कम-से-कम इतना तो करना चाहिए। मैं विपक्ष का सदस्य हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी दल का विधायक हूं, कम-से-कम इस प्रकार का व्यवहार न हो। क्योंकि यह

28/03/2016/1635/RG/AS/2

महक़मा आपके पास है, आप इस विभाग के मंत्री हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं, ऐसा नहीं

होना चाहिए।

मुख्य मंत्री : मशीनरी को यहां से वहां भेजने का काम मेरे लेवल पर नहीं होता है।

श्री जय राम ठाकुर : मैं मानता हूं कि यह आपके लेवल पर नहीं होता है।

मुख्य मंत्री : अगर ऐसा हुआ है, तो मुझे अभी मालूम हुआ है कि एक चली गई श्री कौल सिंह जी के यहां और श्री मन्शा राम जी के यहां चली गई करसोग में। इसलिए करसोग का तो मैं देखूंगा। क्योंकि उनकी आवश्यकता भी आप से कम नहीं हैं। लेकिन ये जो दो जगहें मशीनरी गई हैं वह within two days it will be back.

श्री जय राम ठाकुर : ठीक है, आपका धन्यवाद। लेकिन बाकी भी सभी भेज दो, करसोग की मशीनरी वहां काम कर रही है।

मुख्य मंत्री : वहां रिपलेस करना पड़ेगा।

श्री जय राम ठाकुर : महेन्द्र सिंह जी नाराज़ हो रहे हैं, इनको एक और आपने दे देना।

मुख्य मंत्री : अगर आपने उनकी उठाई है, तो वापस जरूर जाएगी।

श्री जय राम ठाकुर : इन्होंने तो नहीं उठाई होगी, यह तो अधिकारियों ने उठाई है। यह किस स्तर पर निर्णय हुआ है? एक अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूं कि

एम.एस. द्वारा जारी

28/03/2016/1640/MS/DC/1

श्री जय राम ठाकुर जारी----------

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 21 किलोमीटर सड़क आपने तीन साल के कार्यकाल में बनाई और यही लोक निर्माण विभाग पहले कैसे काम करता रहा है, मैं बताता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में टोटल 200 किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार हुईं

जिनमें आज गाड़ियां चल रही हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बड़ा आंकड़ा दे दिया तो मैं आपको सड़कों के नाम बता सकता हूं। 23 किलोमीटर गाड़ागुशैणी से छतरी सड़क, माननीय उस वक्त के मुख्य मंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने उसका उद्घाटन किया था। थलौट से पंजाई 16 किलोमीटर सड़क, बालीचौकी से खणी 6 किलोमीटर सड़क, गाड़ागुशैणी से घाट के गांव 19 किलोमीटर सड़क, थाची से डीडर 20 किलोमीटर सड़क, ये सड़कें बनकर तैयार ही नहीं हुईं बल्कि इन पर गाड़ियां चल रही हैं। उसके बाद सुधाणी से थाटा 18 किलोमीटर सड़क, गोहर से देवधार 7 किलोमीटर सड़क, गोहर से कांडा 16 किलोमीटर सड़क, गोहर से बस्सी 10 किलोमीटर सड़क और जंजैहली से रेशन, उपाध्यक्ष जी, जिसमें आपके चेतराम जी का गांव है उनको भी मैंने सड़क दी है। वे आपके दिल के बहुत करीब है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वहां पर लोक निर्माण विभाग में जो XEN लगाया है, वह उनका क्लासफैलो है। वे दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी विभाग से ले लें। तभी ये सारी चीजें हो रही हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। उपाध्यक्ष जी, इसी प्रकार से त्यूणी से चेत 6 किलोमीटर सड़क और पुखला से पार शिमलीधार की सड़क 18 किलोमीटर है। इस प्रकार से भी सड़कें बनी हैं। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में विभाग काम नहीं कर सकता है। विभाग काम कर सकता है लेकिन इनको जिस प्रकार से मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, जिस प्रकार से ढील छूटती जा रही है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति है।

मुख्य मंत्री जी, एक बात और है। यह जो पी0एम0जी0एस0वाई0, वर्ल्ड बैंक और नाबार्ड की सड़कें हैं इनमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन सालों में सिर्फ एक सड़क की स्वीकृति आई है। एक सी0आर0एफ0 का जो हमारा पुल टूट गया था और बह गया था जिसको मैंने विधायक प्राथमिकता में डाला था, उसकी

28/03/2016/1640/MS/DC/2

सी0आर0एफ0 में स्वीकृति आई है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से केन्द्रीय मंत्री जी के पास जाकर आया और उनसे निवेदन भी किया। अब उसकी दो करोड़ रुपये की सैंक्शन आई है और उसका काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त तीन साल के कार्यकाल

में एक भी डी0पी0आर0 नहीं बनी और जो डी0पी0आर0 पिछली बनी थी उनकी भी स्वीकृति इस प्रकार से नहीं मिल पाई। यह सचमुच में चिन्ता का विषय है। तभी मैं मजाक में कह रहा था कि ये नाबार्ड साहब सिर्फ कांग्रेसी सदस्यों के क्षेत्र में ही घूम रहे हैं या विपक्ष के लोगों के विधान सभा क्षेत्रों में भी आएंगे? हमें न सी0आर0एफ0 की, न नाबार्ड की और न ही वर्ल्ड बैंक की स्वीकृतियां आ रही हैं।यह जो एकमुश्त का जिक्र आ रहा है उसमें गुंजाइश रहती है और मुझे लगता है कि इसको ठीक करने की आवश्यकता है। जैसे जो पिछड़े क्षेत्र हैं वे प्राथमिकता में होने चाहिए क्योंकि जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जहां पर सड़कें नहीं पहुंच पा रही हैं। वह प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन सारी बातों पर ध्यान देंगे। जहां तक डी0पी0आर0 की बातें हैं वे हमने बहुत कह दी हैं। इसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि हम बातें बहुत कर चुके हैं। एनुअल प्लानिंग की मीटिंग में भी हम बात करते हैं। जवाब फिर आता है कि DPR not received. DPR awaited. DPR not received due to private and forest land involved. यही जवाब आता है। मुख्य मंत्री जी, ऐसी कौन सी सड़क बनेंगी जहां या तो प्राइवेट जमीन नहीं लगेगी या फिर वहां पर फॉरैस्ट लैण्ड नहीं लगेगी? मेरे पास जो एनुअल प्लानिंग की वर्ष 2007 के बाद की डिटेल है उसके अनुसार हमारे क्षेत्र की कुछेक डी0पी0आर्ज0 तैयार हुईं, उसके अलावा अधिकांश जगह यही जवाब है। एक ही जवाब में वे काम खत्म कर देते हैं कि हमारा काम खत्म, तुमने लिख दिया है। ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि विधायक प्राथमिकता में हमें अपनी योजनाएं डालनी भी चाहिए या नहीं। इस मान्य सदन में हमने एक बार नहीं बल्कि कई बार चर्चा कर ली लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला। आपने कहा कि एक हैक्टेयर तक की पावर डी0एफ0ओ0 को दे दी गई है लेकिन जब हम नीचे उनके पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि ऐसा तो है लेकिन कोई कर नहीं रहा है। अगर आपको सचमुच में लगता है कि एक हैक्टेयर तक की फॉरैस्ट लैण्ड की क्लीयरैंस देने की पावर्ज डी0एफ0ओ0 को है तो उनको अपने यहां शिमला में बुलाकर क्लीयर करो कि इस प्रकार का कोई भी मामला,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

28.03.2016/1645/जेएस/डीसी/1

श्री जय राम ठाकुरः-----जारी--------

चाहे वह स्कूल की बिल्डिंग का मामला है, चाहे हॉस्पिटल की बिल्डिंग का मामला है और चाहे वह छोटे से रोड़ की कनैक्टिविटी का मामला है। तमाम इस तरह के मामले को अगर वे अपने स्तर पर कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि उससे भी बहुत बड़ी राहत होगी। लेकिन ये सच्चाई है कि आज की तरीख में कोई भी डी0एफ0ओ0 इस काम को हाथ नहीं लगा रहे हैं। कोई भी नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे ही फौरेस्ट लैंड की बात आती है। आपके पंचायती राज एण्ड रूरल डवैल्पमैंट डिपार्टमैंट में बी0डी0ओ0 के साथ कोई एग्रीमैंट करने को तैयार नहीं है। रास्ता बना हुआ है और उसे पक्का करना है। उसको पक्का करने के लिए वे कहते हैं कि आप जमीन के कागज़ लाएं, इसलिए इसमें बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है। एग्रीमैंट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा पैसा ब्लॉक में पड़ा हुआ है। हमारी विधायक निधि का पैसा पड़ा हुआ है। सांसद निधि का पैसा पड़ा हुआ है। बैकवर्ड सब प्लान का पैसा पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी वह काम हो नहीं पा रहे हैं। रास्ता पक्का करना है और रास्ता बना हुआ है और वर्षों से लोग उसमें चल रहे हैं उसके बावजूद भी बी0डी0ओ0 बोलता है कि ये फॉरमल्टी पूरी करो, लेकिन वे फॉरमल्टीज़ पूरी नहीं हो पा रही हैं उसके कारण काम रुका पड़ा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से इस विभाग में काम की उम्मीद हम लोग कर रहे थे उस प्रकार से विभाग काम नहीं कर पा रहा है। आपसे मेरा निवेदन है कि खासतौर से जिस मुद्दों को ले करके हम लोगों ने आपसे यहां पर निवेदन किया है उन पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद आदेश दें और खासतौर से ऐसे पिछड़े क्षेत्र जहां पर सड़कों की नितान्त आवश्यकता है। जहां पर सड़कों की कनैक्टिविटी अभी बहुत सारी पंचायतों को होनी है और कई गांवों को होनी है तो उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए अलग से प्रावधान करने की आवश्यकता है। इस पर मुझे लगता है कि इसमें काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारी सड़कें हमने ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी बना करके रखी है जिससे लोगों का सेब जा रहा है, मटर जा रहा है और आलू जा रहा है लेकिन वह सड़क बस के लायक

28.03.2016/1645/जेएस/डीसी/2

नहीं है। वहां पर ट्रक नहीं जाता होगा, लेकिन जीप जाती है। उस पर ट्रेक्टर जाता है

लेकिन उसमें कोई मेंटिनैंस नहीं है। हमने उन सड़कों के लिए विधायक निधि से, सांसद निधि से और दूसरे हैड के प्लान से वह सड़क तो बना दी लेकिन मेनटेंन नहीं हो पा रही है। उसमें मेरा आपसे निवेदन है कि जब लोग हमारे पास आते हैं कि सड़क बनाओ और उसको पी0डब्ल्यू0डी0 में डालो। पी0डब्ल्यू0डी0 कहता है कि हम उस सड़क को नहीं ले सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कि पी0डब्ल्यू0डी0 बहुत सख्त रहता है और वे किसी काम को करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से करें कि जो सड़क बनी है, गाड़ी उसमें चलती है चाहे वह पंचायत ने बनाई है, चाहे वह पी0डब्ल्यू0डी0 ने बनाई है और चाहे फौरेस्ट डिपार्टमैंट ने बनाई है अगर उसकी मेंटिनैंस की बात आती है उसके लिए निश्चित एक नीति बननी चाहिए ताकि उसकी मेंटिनैंस होती रहे। उस सड़क पर गाड़ी चलती रहे। इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसमें पी0डब्ल्यू0डी0 उन सड़कों को अपने पास ले सकता है और मेंटिनैंस की दृष्टि से हम पैसा देंगे और पी0डब्ल्यू0डी0 उसमें काम करें। यह मुझे लगता है कि इस तरह की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2016/1645/जेएस/डीसी/3

अध्यक्षः अब श्री महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-10 लोक निर्माण- सड़क, पुल एवं भवन की कुल मांगें मान्यवर मुख्य मंत्री महोदय ने 367 करोड़ 10 लाख, 18 हजार रूपए की इस माननीय सदन में प्रस्तुत की है। मेरे द्वारा दिए गए कटौती प्रस्तावों में चर्चा करने के लिए आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं।

महोदय, सड़कों व पुलों के निर्माण हेतु इस साल 10 हजार करोड़ रूपया प्रस्तावित किया गया है। जो कि चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 2 हजार करोड़ रूपए कम है और चालू वित्तीय वर्ष में जो मशीनरीज़ व उपकरणों को खरीदने के लिए पैसा रखा गया है वह 4 हजार 228 करोड़ गत वर्ष में था, लेकिन इस वर्ष में भी उतना ही है जितना कि पिछली वर्ष में था।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----------

28.03.2016/1650/SS-AG/1

श्री महेश्वर सिंह क्रमागतः

महोदय जहां तक उपकरणों का संबंध है, जैसे यहां चर्चा भी हुई कि अनेकों स्थानों पर पुरानी मशीनरी अक्सर खराब रहती है। मैं कुल्लू डिवीजन-I का उदाहरण देना चाहूंगा। वहां एक बुलडोजर है और वह अनेकों बीमारियों से घिरा हुआ है। उनसे ग्रस्त है। आये दिन उसको इलाज के लिए वर्कशॉप में जाना पड़ता है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि उसको रिप्लेस किया जाए और नया बुलडोजर दिया जाए क्योंकि मनिकर्ण घाटी की सारी सड़कें उस बुलडोजर से ही चलती हैं जोकि सारा ही दुर्गम क्षेत्र है।

महोदय, जहां तक विधायक निधि योजनाओं या प्राथमिकता वाली योजनाओं का संबंध है, निश्चित रूप से कहीं-न-कहीं कमी है। गत तीन वर्षों में जिन भी योजनाओं की हमने प्रस्तावना की है उसकी डी0पी0आर0 विभिन्न स्तरों पर पड़ी है और नाबार्ड के मुख्य कार्यालय तक नहीं पहुंच पाई है। एक भी नहीं पहुंच पाई है। मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण यह है कि जो लोअर स्टाफ है उसकी निचले स्तर पर बहुत कमी है चाहे वह ड्राफ्टमैन की बात करिये, सर्वेयर की बात करिये या पटवारी की बात करिये। ऊपर से लगता है कि शायद एक यह भी कारण रहा हो कि जो दो डिवीजन कुल्लू में हैं इन तीन वर्षों में तीन बार वहां के एक्सियन ट्रांसफर होते रहे हैं। जब हर साल ट्रांसफर होगी तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी पड़ता है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कम-से-कम जो इस प्रकार की डी0पी0आर0 बनी हैं और ई0एन0सी0 के ऑफिस में फाइनल के लिए लम्बित पड़ी हैं शायद वे दो हैं। जो चीफ इंजीनियर और ई0एन0सी0 के ऑफिस के बीच में शटल हो रही हैं। वे भी इसी प्रकार की दो योजनाएं हैं। बाकी चाहे इन तीन वर्षों की या पुरानी डी0पी0आरज़0 हों, वे चीफ इंजीनियर और एक्सियन के ऑफिस के बीच में शटल होती रहती हैं। मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी विभाग को निर्देश देंगे कि कम-से-कम अप्रैल मास तक दो-तीन इस प्रकार की डी0पी0आरज़0 फाइनल होकर नाबार्ड के मुख्य ऑफिस में पहुंच जाएं। विलम्ब के पीछे एक और भी कारण है क्योंकि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तृतीय वन भूमि है और एफ0सी0ए0 क्लीयरैंस में बहुत समय लगता है। यहां से बार-बार निर्देश जाने के बावजूद अभी काम

करने में थोड़ा-सा सुधार तो हुआ है लेकिन जो तीव्रता आनी चाहिए उसका अभाव है। जहां तक

28.03.2016/1650/SS-AG/2

चालू वित्त वर्ष का सवाल है इसमें जो मैटीनेंस या रख-रखाव का पैसा है उसमें निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। वह 33,72,00,879/- रुपये है जोकि गत वर्ष की तुलना में चार करोड़ अधिक है। महोदय, जहां तक क्वालिटी कंट्रोल की बात है, मेरा एक प्रश्न भी आज इस संदर्भ में था और मुख्य मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि हमने कोई समिति गठित नहीं की है लेकिन ई0एन0सी0 के ऑफिस में क्वालिटी कंट्रोल विंग है और तीन प्रकार की कार्यप्रणाली वहां पर स्थापित की गई है। मुझे लगता है कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए इस विंग को कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है क्योंकि जितनी भी हमारी ग्रामीण सड़कें हैं वहां पर सोलिंग, टारिंग और मैटलिंग के जो मापदंड हैं, जो थिकनैस है, मुझे लगता है कि वर्षों से उनको रिवाइज नहीं किया गया है।

जारी श्रीमती के0एस0

28.03.2016/1655/केएस/एजी/1

श्री महेश्वर सिंह जारी---

और इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि तुलनात्कम दृष्टि से आज के समय में उन सड़कों पर 100 गुणा ट्रैफिक बढ़ा है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी ट्रैफिक जाम एक समस्या बन रहा है। निश्चित रूप से सड़कों पर लोड बढ़ा है इसलिए क्वालिटी कंट्रोल वालों को उस थिकनैस को बढ़ाना चाहिए। जो यहां पर तारकोल इस्तेमाल होता है, उसको भी बार-बार चैक करने की आवश्यकता है। कौन से कारण है कि तारकोल बिछाने के बाद छः महीने के भीतर ही सड़कें उखड़ रही है। कहीं न कहीं तो कमी है। मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि क्वालिटी टैस्टिंग को सुदृढ़ करने हेतु सात प्राईवेट लैब ऐम्पेनैल्ड है। अगर ऐसा है तो इनके पास जो सैम्पल जाते हैं, इसको देखने की आवश्यकता है कि अगर सैम्पल भी ठीक है, पास हो जाता है तो कौन सा कारण है कि ये सड़कें उखड़ रही हैं। यह सबसे बड़ी चिन्ता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की भी यह स्थिति है कि बार-बार मैटलिंग-टारिंग उखड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, अभी जो केबल

डाला जा रहा है, इस सन्दर्भ में भी मेरा प्रश्न था और मुख्य मंत्री जी ने उत्तर देते हुए कहा था कि सख्ती से अब उन बातों का अनुपालन करवाया जाएगा। कम्पनी ढाई सौ मीटर से अधिक सड़क नहीं खोदेगी। कम्पनी पहले उसको पक्का करेगी फिर आगे बढ़ेगी और यह भी कहा था कि इसमें नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगें, बत्तियां लगाई जाएंगी, सिग्नल लगाए जाएंगें। हफ्ता भर तो उसका असर रहा लेकिन आज स्थिति ज्यूं की त्यूं है। ढाई सौ मीटर नहीं बल्कि ढाई-ढाई, तीन-तीन किलोमीटर सड़क दोनों तरफ खोद दी गई है, ट्रैफिक जैम हो रहा है और कम्पनियों पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा है। साथ में मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही थी कि अब सड़कों की रीपेयर के लिए 9 लाख रु0 प्रति किलोमीटर ये कम्पनियां जमा करेंगी और वह पैसा उन्हीं सड़कों पर खर्च होगा जहां की असैसमैंट हुई है तो मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए कि आखिर कितने किलोमीटर कार्य इनको दिया गया है वह अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकार के सामने रखना चाहूंगा लेकिन इससे पूर्व मैं क्वालिटी कंट्रोल की एक बात भूल गया,

28.03.2016/1655/केएस/एजी/2

उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या यह सत्य है कि जो आपके पैरापिट या क्रेश बैरियर हैं, विशेषकर पैरापिट सबस्टैंडर्ड बन रहे हैं। एक स्टील का फर्मा तैयार किया गया है उसको उठाया जाता है, जगह-जगह उसमें कंकरीट भर दी जाती है । उसकी कोई फाऊंडेशन नहीं है और जब उससे गाड़ी टकराती है तो आपका पैरापिट सूचक का रोल अदा करता है यानि आगे-आगे वह लुढ़कता है और पीछे-पीछे गाड़ी चली जाती है। ये किस प्रकार के पैरापिट लगे हैं, हैरानी की बात है। और मुख्य मंत्री जी द्वारा जो यह उत्तर दिया गया है, यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस बात को देखना होगा। मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारे एक सड़क बस योग्य बन कर तैयार हो गई जिसका नाम कुल्लू-पीज़ सड़क है। उसमें अपग्रेडेशन का काम अभी-अभी कम्पलीट हुआ है। मैटलिंग भी हुई है लेकिन पैरापिट कहीं-कहीं दिखते हैं और परिणाम क्या हुआ कि जिस दिन पंचायत इलैक्शन के नॉमिनेशन थे, नवम्बर के अन्त में, उस दिन एक छोटी गाड़ी जिसमें आठ सवारियां बैठी थी, नीचे गिर गई। उस गाड़ी के नीचे

गिरने से आठों लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। कारण क्या हुआ कि पीज़ गांव से लेकर जो ढंकार है, उसमें एक भी पैरापिट नहीं लगा है। अगर पैरापिट होता तो यह दुर्घटना नहीं होती और यदि वह गाड़ी लुढ़ककर एक जगह टिक न जाती तो सीधी कुल्लू के सर्किट हाऊस के पीछे पहुंचती और अनेकों लोगों की जान-माल का जिनके कि वहां रास्ते में मकान थे, नुकसान हो जाता। मैंने तुरन्त एस.ई. महोदय को पत्र लिखा, ई.एन.सी. महोदय को कॉपी की कि इस कारण से एक्सिडैंट हुआ है ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.3.2016/1700/av/ए0एस/1

श्री महेश्वर सिंह------ जारी

तो कम-से-कम भगवान के लिए उस ढंकार वाले एरिया में 5-10 पैरापिट या क्रेश बैरियर लगा दें ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना अभिघटित न हो। मैंने बोलने से पहले आज भी वहां पर पता किया मगर कोई भी पैरापिट नहीं लगा। अगर विभाग इस प्रकार की कोताही करेगा तो दुर्घटना नहीं घटेगी तो और क्या होगा; आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। जो सड़कें केबल कम्पनियां उखाड़ रही हैं वह मैंने सारी सूचना प्राप्त की है। उसमें सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 56 किलोमीटर सड़क कुल्लू डिविजन न0 I और II की है जो कि इस कार्य के लिए उखाड़ी गई है। नेशनल हाई-वे के समेत इन सड़कों का टोटल भी मेरे पास है और लगभग 22 करोड़ रुपये इन्होंने डिपोजिट किये हैं। मैंने जब कुल्लू का टोटल किया और हमें जो पैसा मिला है वह लगभग 400 करोड़ रुपये है। जबकि मैंने 900 प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका टोटल किया तो हमें कम-से-कम 6 करोड़ रुपये की राशि मिलनी चाहिए थी। फिर मैंने पता किया कि ऐसा क्यों हुआ तो कहा गया कि प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को कोई अंडर टेकिंग दी है। भारत सरकार को जो अंडर टेकिंग दी है उसमें यह कहा गया है कि टेली-कम्युनिकेशन का विभाग पब्लिक सर्विस का विभाग है इसलिए हिमाचल सरकार इनसे कोई पैसा नहीं लेगी अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में यह 900 रुपये प्रति किलोमीटर नहीं मिलेगा। अब चिन्ता का विषय यह है कि अगर इसमें सच्चाई है तो यहां पर विभाग के

उच्च अधिकारी भी बैठे हुए हैं। मुख्य मंत्री जी कम-से-कम यह तो बता दें कि ये सड़कें जो अब खोद दी गई हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कटौती लगी है कि वहां पर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर इनकी मुरम्मत कहां से होगी? पिछले कल मैंने देखा और जो अभी तक नेशनल हाई-वे का पार्ट है यानि जो सड़क अखाड़ा बाजार से होकर जाती है। वहां और ढालपुर के बीच में जो डेढ़ फुट की जगह खोदी गई थी उसमें सोलिंग करके उसके ऊपर रोलर चलाया जा रहा है। मैंने पूछा क्या इसकी पूरी सर्फेसिंग नहीं करेंगे आपको तो इस एरिया के लिए 9 लाख रुपये मिलेंगे। कहते नहीं जनाब, यहां पर पैच वर्क होगा। यह पैच वर्क एक सबसे बड़ी समस्या है। मुझे

28.3.2016/1700/av/ए0एस/2

नहीं मालूम कि यहां से इस प्रकार के निर्देश हैं कि रीसर्फेसिंग मत करो। जब मशीनरी लगती है और सड़क खोदी जाती है तो उसकी सारी-की-सारी सर्फेसिंग डिस्टर्ब हो जाती है। मगर वहां कहा गया कि पैच वर्क होगा। मुझे अपने बचपन की एक बात याद आती है। उन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी। जब वे लोग शहर में आते थे तो उनके कपड़ों में कई जगह पैचिज लगे होते थे जिसको हम अपनी भाषा में टलि कहते थे। वह टलियां तो खत्म हो गई क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है। मगर लोक निर्माण विभाग की आर्थिक स्थिति को क्या हो गया है? अब तो सारी सड़कों पर टलियां पड़ रही है। क्या सिर्फ पैच वर्क में ही सारा पैसा खत्म कर दिया जायेगा? दूसरा, मैं नेशनल हाई-वे के फोर लेन की बात करना चाहूंगा। मैंने पिछले सत्र में भी यह बात उठाई थी कि रामशीला पुल से आगे डबल लेन जायेगा। पंडोह से लेकर टनल में होते हुए दलाशड़ी - पनारसा सड़क अलग बनेगी और वर्तमान सड़क डबल लेन ही रहेगी जो कि केवल 19 किलोमीटर का पैच है । दलाशड़ी-भुन्तर-जियापुल से रामशीला तक फोर लेन किया जा रहा है। मैंने इसका विरोध इसलिए किया था और मैंने उस समय भी स्पष्ट किया था कि यदि इसको फोर लेन किया जाता है तो इस एरिया में 60-65 प्रतिशत लोग ऑफ सीजन वैजिटेबल ग्रोअर है।

टीसी द्वारा जारी

28.03.2016/1705/TCV/AS/1

श्री महेश्वर सिंह----- क्रमागत

और ये अधिकांश दलित समुदाय के हैं। इनको पैसा तो मिल जाएगा लेकिन बदले में जमीन कहीं नहीं मिलेगी और इनका सारा धन्धा चौपट हो जाएगा। इसको बचाया जा सकता है। दूसरा, कृषि विज्ञान केन्द्र, उनकी 80 बिघे जमीन है और वह एक प्लॉट है। वह किसी युनिवर्सिटी के लिए काम आ सकता है लेकिन उसके भी 2 भाग हो जाएंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था it is a good suggestion we will take it up with the National Highway Authority of India. क्या हुआ मुझे मालूम नहीं लेकिन मैंने एक पत्र उनको अवश्य लिखा और सुझाव दिया कि इसको आप बेकार में फोरलेन क्यों कर रहे हों, इसको दो लेन ही रहने दो क्योंकि यहां से गति से गाड़ियां जाएगी, आगे फिर रूकेगी और एक्सीडेंट होंगे। जो खराल का एरिया है, जिससे हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी भी भली-भान्ति वाकिफ है ये जिया से लेकर रामशीला तक का सारे का सारा बिजली महादेव के नीचे का पहाड़ स्लाईडिंग एरिया है। इसमें लोकल लाईन हैं मैने लोक निर्माण विभाग के जो FC -cum- Secretary है उनके दफ्तर में जाकर भी सारी बात एक्सप्लेन की है कि अगर इसको छेड़छाड़ करोगे तो ये सारे -के -सारे गांव नीचे उत्तर जाएंगे और इसमें दरारें आ रही हैं। इस बार मैंने इस संदर्भ में एक प्रश्न पूछा था कि यह सड़क कितनी चौड़ी है, कितनी इसमें जमीन एक्वायर की गई है? यह सड़क डबल लेन हैं और जिया से आगे इसकी बिडथ 18 से 20 मीटर तक होनी चाहिए थी। लेकिन स्लाईडिंग के डर से आपके विभाग ने कहीं 9 मीटर और कहीं 10 मीटर चौड़ी बनाई है और वे उसको चौड़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से स्लाईडिंग हो रही है। इसके आगे अगर जायें तो जहां शनि मंदिर है वहां यह सड़क सिर्फ 5 मीटर चौड़ी है और विभाग के अधिकारियों ने उसके किनारे ड्रेन बनाने का कार्य शुरू कर दिया है और मैटलिंग टायरिंग करने की तैयारी शुरू कर दी है। जब अधूरे कार्य में आप ड्रेन बनाओगे तो ड्रेन सबको इन्क्रोचमैंट करने के लिए एक वॉण्डरी बन

जाती है। अब कह रहे हैं कि यह सब काम नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ

28.03.2016/1705/TCV/AS/2

इण्डिया करेगी। और जो यहां पर आपके प्रोजैक्ट के अधिकारी, मिस्टर कौल हैं मैंने उनको पूछा तो मुझे जवाब आया कि अगर हम इनको दोनों तरफ डबल लेन ले जाएंगे तो It will require to connect the bridges and then I said how many do you require? आप भी इस बात को एप्रीशिएट करेंगे कि बजौरा में डबल लेन ब्रिज है, भुंतर में डबल लेन ब्रिज है, कुल्लू बस स्टैंड जिया में डबल लेन ब्रिज है रामशीला में डबल लेन ब्रिज है और पांचवें का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, वह दलासणी के पास है। अगर जो दलासणी में पुल है इसको भी डबल लेन कर दिया जाये तो 5 ऐसे कनैक्टिंग ब्रिज़िज हो जाएंगे और 19 किलोमीटर में 5 नेशनल हाईवे के लिए डबल लेन कनैक्टिंग ब्रिज़िज मिलेंगे। इसलिए मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि भू-वैज्ञानिक को भेजिए और वह जिया के पहाड़ को देखें कि सड़क बनेगी तो सारे-के-सारे गांव चौपट हो जाएंगे। इसलिए कोई न कोई भू-वैज्ञानिक भेजें और पुनः इस मामले को नेशनल अथोरिटी ऑफ इण्डिया से उठाएं ताकि इसमें सुधार हो सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया और यहां माननीय सभी सदस्यों ने ध्यान पूर्वक सुना मैं, आपका और आपके माध्यम से सारे सदन का आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

28.03.2016/1705/TCV/AS/3

अध्यक्षः अब श्री सुरेश भारद्धाज जी, मांग संख्याः 10 पर चर्चा करेंगे ।

श्री सुरेश भारद्धाजः माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्याः 10 सड़क, पुल और भवन निर्माण से संबंधित डिमाण्डज/कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अभी तक जितने भी माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार रखें हैं, सभी सी0आर0एफ0,

पी0एम0जी0एस0वाई0

श्री आर0के0एस0 --- द्वारा जारी।

28.03.2016/1710/RKS/DC/1

श्री सुरेश भारद्वाज....जारी

और विधायक प्राथमिकता के ऊपर बात करते रहे हैं। शिमला जिला में बहुत काम हुआ है, सड़कें भी बनी हुई हैं। लेकिन आज भी मैं समझता हूं कि सारे हिमाचल प्रदेश में शायद चम्बा के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कोई दिक्कत हो अन्यथा शिमला जिला सड़कों की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। विशेष रूप में इसका कारण यह है कि यहां का जो टेरेन है, यहां का जो एरिया है उसमें जो सड़क दूसरे जिले में 1 लाख में बन जाती है, यहां पर इसके लिए 10 लाख की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से हम पिछले कुछ समय से शिमला जिला में एक प्रमुख सड़क की ओर सरकार ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। पिछली साल भी किया था। उसके बाद काफी काम हुआ । लेकिन आजकल फिर से ऐसा लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। ठियोग-हाटकोटी सड़क में जो काम हुआ है, जो कटिंग कर दी है, कटिंग करके उसकी टारिंग, मैटलिंग या कोई सोलिंग इत्यादि कुछ नहीं हुई है। निहारी से लेकर हाटकोटी तक के एरिया में अगर एक बारिश आ जाए तो वह एरिया धान की खेती में परिवर्तित हो जाता है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि सेब सीजन निकट है। वैसे बहुत सारे सेब के पौधे आजकल काटे जा रहे हैं। लेकिन जितनी सेब की फसल बचेगी, सड़क न बनने के कारण वह भी मंडियों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए कंपनी को इस दृष्टि से काम करने के लिए कहा जाए कि जो सड़क की कटिंग कर दी गई है, जो सड़क को चौड़ा कर दिया गया है वहां पर कम-से-कम सोलिंग तो कर दी जाए। अगर सोलिंग हो जाएगी तो सड़कें पानी के तालाब में नहीं बदलेंगी, कीचड़ नहीं होगा और सेब की फसल को मंडियों तक पहुंचाया जा सकेगा। पिछले वर्ष भी मैंने एक निवदेन किया था जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने पैसा भी दिया है। जो सड़क नारकंडा से सुंगरी होते हुए रोहड़ू जाती है या सुंगरी से रामपुर को जाती है, इन सड़कों को अलटरनेटिव रोड़ज के रूप में बनाने की आवश्यकता है। ये ऑल वैदर रोडज हो

सकते हैं। ये सैन्य दृष्टि से भी बहुत उपयोगी रोडज हैं। खदराला वाला रोड़ बहुत पुराना रोड़ है। इस रोड़ पर सन् 1953 में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी गए थे। लेकिन आज इस रोड़ की स्थिति

28.03.2016/1710/RKS/DC/2

इतनी बदतर है कि नवम्बर में यह बंद हो जाता है और अप्रैल तक इस रोड़ में चलना मुश्किल हो जाता है। इस पर कुछ काम प्रारम्भ हुआ है परन्तु इस कार्य को एक्सपेडाइट करने की जरूरत है। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार पैसा दिया है उसमें और इजाफा करने की जरूरत है। अलटरनेटिव रोड़ एक खदराला की ओर जाएगा और दूसरा टिकर की ओर जाएगा तो पूरे शिमला जिले का सर्कल इससे कवर हो जाएगा। इस कारण शिमला के बागवानों की समस्या हल हो सकती है। इससे पहले भी बागवानों को हाटकोटी-ठियोग रोड़ के लिए सत्याग्रह करना पड़ा था। मुझे लगता है कि माननीय रोहित ठाकुर जी को भी सत्याग्रह में बैठना पड़ेगा क्योंकी सबसे ज्यादा इनको मुश्किल होने वाली है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप मुख्य मंत्री जी को जगा करके रखें। आप इनको अपने साथ ले जाएं। ये गुमा से वापिस न आएं और आगे तक जाएं।

मुख्य मंत्रीः मैं 3-4 बार गया हूं।

श्री सुरेश भारद्वाजः क्योंकि आपकी सड़कें बनेंगी तो मेरी भी बनेंगी। इसके अतिरिक्त जो चर्चा यहां पर करते रहे हैं, शिमला की दृष्टि से उसकी उपयोगिता नहीं है। शिमला हिमाचल प्रदेश का एकमात्र शहरी निर्वाचन क्षेत्र है। यहां पर हमको पुलों की आवश्यकता नहीं है। जो पुल बनना था वह पुल बन गया है।

श्री एस.एल.एस द्वारा ....जारी

28.03.2016/1715/SLS-DC-1

श्री सुरेश भारद्वाज...जारी

बाईपास पर नेशनल हाईवे पर बनने वाले पुल आजकल बन रहे हैं, लेकिन उनके निर्माण की गति धीमी है। लोक निर्माण विभाग के पास ही नेशनल हाईवेज भी होते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि शिमला जैसे राजधानी क्षेत्र में अगर काम की गति इतनी धीमी होगी तो निश्चित रूप से बाकी जगह गति बहुत तेज नहीं हो सकती है। इसलिए उस ओर ध्यान दें। अगर उस रोड पर पुल बन जाएंगे तो जो बड़े-बड़े ट्रॉले और ट्रक सेव सीजन में आते हैं वह शहर के बीच से न होकर उस सड़क से आ-जा सकते हैं। लेकिन पुलों के अभाव में उस सड़क का उपयोग नहीं हो पा रहा है। वह पुल बहुत सारा तो बन चुका है लेकिन उसको पूरा करने की आवश्यकता है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप उस ओर ध्यान देकर उसको पूरा करवाएंगे।

शिमला शहर में सबसे बड़ी समस्या कंजैशन की हो गई है। आप आजकल विधान सभा के बाहर सर्कुलर रोड को देखें तो यहां से लेकर गाड़ियों की लाईन शुरू होती है और आगे विक्टरी टनल तक रहती है। उसके बाद सामने देखें तो होलीडे होम होते हुए जितनी भी सड़क है वह पूरी-की-पूरी कंजैशन से बंद होती है। यहां तक कि बच्चों को भी कई बार दूसरे रोड से जाना पड़ता है। इसलिए यहां पर आवश्यकता इस बात की है कि हम इसका आलटरनेटिव ढूंढ़े। सरकार ने आलटरनेटिव ढूंढ़ कर 3 सुरंगों की डी.पी.आर. बना रखी है। केवल डिटेल्ज उसकी बननी है जबकि उसका खाका बना हुआ है। उन सुरंगों के ऊपर अगर काम होगा तो समस्या हल हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश सरकार उन्हें स्वयं बना सकती है। लेकिन उसको किसी भी फंडिंग एजैंसी के लिए भेजा जा सकता है। हम मॉल रोड की ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। पिछली सरकार के समय एशियन डवलपमैंट बैंक से लोन लिया गया था जिससे आजगत ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है। इसी प्रकार से हम इन सुरंगों के लिए भी एशियन डवलपमैंट बैंक फंड से या वर्ल्ड बैंक से या किसी और एजैंसी से बात क्यों नहीं करते। इसके साथ-साथ बहुत

28.03.2016/1715/SLS-DC-2

सारी अन्य चीज़ें हैं। माननीय बाली जी अपने बहुत से बस अड्डों को बो. ओ. टी. बेसिज पर बनाने की बात करते हैं। इन सुरंगों को भी उसी आधार पर बनाया जा सकता है। जब

वह बनेंगी तो उनमें आप टोल लगा सकते हैं और कुछ समय के लिए टैक्सेशन कर सकते हैं। यहां पर माननीय अर्बन डवलपमैंट मीनिस्टर और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी मोनोरेल की बात की थी। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि यहां के लिए मोनोरेल फिजिबल नहीं है। इसलिए अगर टनल की ओर आप ध्यान देंगे, तो हम इस शहर को बचा सकेंगे। वरन् यहां पर कंजैशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आने वाले समय में यहां पर जगह नहीं रहेगी और शिमला टूरिज्म प्वायंट ऑफ व्यू से समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप इस पर काम करें। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट बोर्ड है, लोक निर्माण विभाग है और कई सारी दूसरी एजेंसीज हैं जिनके द्वारा अगर इसकी तरफ ध्यान देंगे तो यह काम हो सकता है और शिमला की समस्या हल हो सकती है।

शिमला में रोड्ज के लिए पैसा नहीं मिलता। आपने जैसे कहा, यहां विधायक प्राथमिकता में कुछ नहीं मिलता। सी.आर.एफ. में और पी.एम.जी.एस.वाई. में भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहां पर सरकार मकान बहुत हैं। जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें हम कहीं-न-कहीं पैसा लगाते ही हैं। कई बार हम बहुत सारे ऐसे कार्यालय बना देते हैं जिनका पैसे के हिसाब से उपयोग नहीं होता। हमने जिला कचहरी के लिए कोर्ट कंपलैक्स बना दिया जिसके कारण लिटिगैंट्स को भी, एडवोकेट्स को भी और जजिज को भी परेशानी है। हालांकि हमने वह भवन फाईव स्टार की तरह बना दिया है लेकिन उसका उपयोग वैसा नहीं है। इसलिए ऐसी चीजों के स्थान पर ऐसे मकान, जिनमें हमारे कर्मचारी रहते हैं, उनकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है।

जारी ...गर्ग जी

28/03/2016/1720/RG/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज----क्रमागत

नाभा की कॉलोनी है। किसी जमाने में राजा-महाराजाओं के जमाने के मकान वहां बने हुए थे। लेकिन अब वे जर्जर अवस्था में हैं। लोगों को वे मकान आबंटित हुए हैं और लोग उनमें रहते हैं। उनको टोटली रिपलेस करने की नीति बनी थी और वर्ष 2011-12 में वहां

जो 52 यूनिट्स बनने थे वे भी अभी तक पूरे नहीं बन पाए हैं। काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इसलिए वहां सारी-की-सारी कॉलोनी को बदलने की आवश्यकता है। हमारे जो कर्मचारी हैं उनको वहां स्थान मिले, उसके लिए मकानों की आवश्यकता है और नाभा की ही बात नहीं है। जो यू.एस. क्लब में मकान हैं वे भी जर्जर अवस्था में हैं। जो राजभवन के पास मकान हैं जिनमें सचिवालय के कर्मचारी रहते हैं वे भी जर्जर अवस्था में हैं। वहां अगर किसी को अपने मकान में कोई काम कराना हो, तो कर्मचारी कोशिश करते हैं कि उनकी डियुटी जब सरकारें बदलती हैं, तो किसी अच्छे मंत्री या किसी बड़े सैक्रेट्री के पास लग जाए। इस प्रकार वे अपने मकान के अंदर का कुछ-न-कुछ काम करवा लेते हैं। लेकिन बाहर की सारी बिल्डिंग टूटफूट में या जर्जर अवस्था में ही रहती है। इसलिए उसमें यदि आपको सुधार करना है, तो पुराने मकानों को रिपलेस करिए और उनके स्थान पर नए मकान बनाइए। क्योंकि वे पुराने तरीके से बने हुए हैं और स्थान ज्यादा घिरा हुआ है इसलिए यदि नए तरीके से वे मकान बनाएंगे, तो उनमें ज्यादा लोगों को अकोमोडेशन उपलब्ध हो सकती है। लेकिन यदि आप नए सिरे से नहीं बना सकते हैं, तो कम-से-कम उनकी मरम्मत के ऊपर पैसा खर्च करिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। यदि बड़े-बड़े लोगों के मकानों की मरम्मत होनी है, तो रातो-रात लाखों रुपया लग जाएगा, किसी मंत्री के बंगले तैयार होने हैं, तो उनके लिए भी लाखों रुपये लग जाएगा, लेकिन छोटे कर्मचारी के मकान की छत यदि ऊपर से टूटी हुई है और अंदर पानी आ रहा है, सीवरेज की हालत खराब है, पानी नहीं आ रहा है, वे उसको ठीक करने के लिए कहे, तो जे.ई. ही काम नहीं करता है। इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शहरों में सड़कों इत्यादि के लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो चीजें यहां हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे कर्मचारी रहते हैं अगर उनको सहुलियत मिलेगी, उनको मकान ठीक मिलेंगे, तो इससे प्रदेश और कर्मचारी दोनों का भला होगा तथा सरकार का भी भला होगा। अब यहां बहुत सारे मकान बन रहे हैं, सरकारी मकान बनते हैं। पहले तो नक्शा ही नहीं होता था। अब हमारे शिमला में एक

28/03/2016/1720/RG/AG/2

मजाक चलता है कि यहां सबसे अवैध भवन कौन सा बना है, तो सब दिखा देते हैं कि

वह 11 मंजिला भवन हाई कोर्ट का है। वह सबसे पहले 11 मंजिल बिल्डिंग बनी थीं। उसमें थोड़ी सी पार्किंग नीचे दिखाई है, लेकिन वहां 5-7 जजों की गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं बाकी तो गेट लग जाता है और अंदर कोई गाड़ी नहीं ले जा सकता। बाहर पार्किंग आपने वकीलों को भी दी है, हाई कोर्ट के बाकी लोगों को भी अलग-अलग दी है और पूरी पार्किंग बना रखी है। लेकिन जितने भी सरकारी मकान, सरकारी भवन या सरकारी कार्यालय बनते हैं उनमें पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं होता। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जब बिल्डिंग बनाएं, तो उसमें पार्किंग का पूरा प्रावधान करें और जब पार्किंग होगी, तभी शहर के बीच में उन बिल्डिंग्ज को बनाने की अनुमति दी जाए।
अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग में कर्मचारियों की बात माननीय श्री महेन्द्र सिंह एवं अन्य सदस्यों ने की और यह बिल्कुल सही भी है। अब नगर निगम, शिमला में भी सारा-का-सारा बी.एण्ड आर. का विंग लोक निर्माण विभाग से ही आता है। हमारी एक माननीय सांसद महोदया ने पार्किंग बनाने के लिए दस लाख रुपये नगर निगम को दिया। उसका फॉऊन्डेशन स्टोन भी रख दिया। उसके बाद जब हमने पता किया कि इसका क्या हुआ और यह क्यों नहीं बनी? तो निगम वाले कहते हैं कि न तो हमारे पास सर्वेयर है, न हमारे पास काई डिजाईन बनाने का वाला है। इसलिए हमने यह कार्य हिमुडा को दिया है। फिर बाद में जब पता किया कि अब उसका क्या हुआ, तो कहते हैं कि हिमुडा ने इसका नक्शा बना दिया है और दस में से पांच लाख रुपये तो वे ही ले गए। अब तो पांच लाख रुपया ही बचा है और इसमें तो पचास लाख रुपये की आवश्यकता है। इसलिए स्टाफ की कमी के कारण जहां इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है, काम की कॉस्ट ऐसक्लेट हो जाती है और फिर उसके बाद ठेकेदार काम नहीं करता है। जो होशियार और बड़े ठेकेदार होते हैं, वे तो कोशिश हीं ये करते हैं कि कम पैसे का टेण्डर भरा जाए, उसके बाद उसमें कोई गलती निकले और वह आर्बिट्रेशन में चला जाए। फिर आर्बिट्रेशन में तो एक ही आदमी लोक निर्माण विभाग का होता है और आर्बिट्रेशन में उसका पैसा ले लिया जाए। काम वहीं-का-वहीं रह जाता है।

एम.एस. द्वारा जारी

28/03/2016/1725/MS/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी----------

इसलिए इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम इनीशियली कोई काम शुरू करते हैं तो उसके लिए पूरा पैसा, स्टाफ और उसकी पूरी डिजाइनिंग करें। यदि हम इस तरह से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बिल्डिंग कम पैसे में बन सकेगी। शिमला में कई बार छोटी-छोटी सड़कें बनानी होती हैं उनमें समस्या आती है क्योंकि बड़ी सड़कों की यहां आवश्यकता नहीं है। जो एम0एल0ए0 फण्ड से सड़कें बननी हैं, जैसे यह फण्ड भी अब एक करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन यहां पर कोई एजैंसी ही नहीं है। बी0डी0ओ0 यहां पर होता नहीं है और बाकी जगह भी कहा गया है कि अब बी0डी0ओ0 एग्रीमैंट नहीं कर रहे हैं। यहां पर तो एस0डी0एम0 को अगर पैसा भेजते हैं तो वह पैसा ही नहीं देता है। जो काम लोक निर्माण विभाग 10 लाख रुपये में करता है यदि वही काम हम किसी लोकल रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन वगैरह को पैसा देकर करवाते हैं तो वह काम 5 लाख रुपये में हो जाता है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि एजैंसीज को, डी0सी0 या एस0डी0एम0 को निर्देश हों कि आपकी जो एम0एल0ए0 लैड में इन्स्ट्रक्शन्ज हैं उनको फोलो करें और जो प्रॉपर सोसाइटीज हैं उनको पैसा देकर इस प्रकार का काम करवाएं। इस तरह से यहां पर जो सड़कों इत्यादि के छोटे-छोटे काम हैं वे हो सकते हैं।

एक और समस्या है। जो कोर्ट्स हैं वे लिटीगेन्ट्स के लिए होते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि जब आप कोर्ट में कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो जजिज के लिए बड़े कोर्ट रूम बना देंगे, उनके लिए आप चैम्बर भी बना देंगे, वकीलों के लिए बार रूम्ज बना देंगे और स्टाफ के लिए भी सब कुछ कर देंगे लेकिन जिनके कारण वे कोर्ट्स चलते हैं, उन लिटीगेन्ट्स के लिए कुछ नहीं होता है। वे बाहर धक्के खा रहे होते हैं।

इसी प्रकार से अस्पताल हैं। वहां पर मरीज नहीं होगा तो डॉक्टर, फार्मासिस्ट या बाकी लोगों की जरूरत ही नहीं है और न ही बिल्डिंग की आवश्यकता है। अगर उस मरीज को सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर उसके कारण अस्पताल की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आई0जी0एम0सी0 में देख लो। वहां पर फैकल्टी मैम्बर्ज के लिए, डॉक्टर्ज के

लिए और स्टाफ के लिए चाहे सड़क में ही

28/03/2016/1725/MS/AG/2

पार्किंग बनाई है लेकिन है या कोई अलग भी पार्किंग होगी जहां वे गाड़ियां पार्क करते होंगे लेकिन अगर कोई व्यक्ति मरीज को अकेले वहां लेकर आएगा तो वह वहां गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। उसको गाड़ी खड़ी करने के लिए सर्कुलर रोड पर आना पड़ता है और जब मरीज को दिखाकर वह वापिस आता है तो वहां पर उसकी गाड़ी के शीशे पर चालान चस्पा होता है। इसलिए जब आप इस प्रकार के अस्पताल इत्यादि बनाते हैं तो जिस जनता और जिस मरीज के लिए बना रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी तरह से स्कूल इत्यादि जिन विद्यार्थियों के लिए बनाए गए हैं उनको अगर आप सुविधा नहीं देंगे तो आखिर इन संस्थानों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। इसलिए इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम बिल्डिंग्ज बनाएं तो उसमें पार्किंग की व्यवस्था करें और जो उसमें लाभार्थी हैं, जो स्टेक होल्डर हैं उनको उसमें आवश्यकतानुसार स्थान प्राप्त हो।

एक बात माननीय जय राम जी ने यहां सड़क खोदने की कही। शिमला में भी यह समस्या है। शिमला के मालरोड में भी जब पीक पर्यटक सीजन मई में आता है तो उस समय सड़क को खोदना शुरू कर देंगे। कभी उसको पानी की लाइन के लिए खोदेंगे, कभी बिजली की लाइन के लिए तो कभी BSNL वाले खोदते हैं। अब तो और भी कई कम्पनीज आ गई हैं। कहते हैं कि पहले थ्री जी था अब फोर जी के लिए खोदना है। कभी रिलायंस खोदेगी, कभी एयरटेल खोदेगी और कभी कोई और खोदेगा। जो पैसा उन कम्पनीज से इसके एवज में लिया जाता है वह वहां यूज नहीं होता है। अनेकों महीनों तक तो वह सड़क बेहाल रहती है लेकिन बाद में भी उसको सही करने के लिए बहुत समय लगाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सड़क को मैटलिंग/टारिंग करके पक्का कर देते हैं उसके बाद इमीडियेटली खोदना शुरू कर देते हैं। एक बार मैटलिंग/टारिंग हो गई फिर खराब कर देंगे ताकि दुबारा मैटलिंग/टारिंग के लिए सड़क हो जाए। इसमें ऐसा हो सकता है कि लोक निर्माण विभाग, म्युनिसिपल कारपोरेशन, टेलीफोन कम्पनीज और बिजली बोर्ड, इन सबसे कॉर्डिनेट करके या तो आप डक्ट बना दीजिए

अगर नहीं बना सकते और आपने खोदना ही है तो कॉर्डिनेशन करके ऐसे सीजन में खोदें जब बहुत ज्यादा पर्यटक नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा चलने वाले

28/03/2016/1725/MS/AG/3

लोग नहीं होते हैं। तब मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा काम हो सकेगा। लेकिन मुश्किल यह है कि हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। एक विभाग परमिशन देता है, दूसरा विभाग काम कर लेता है और तीसरे की सड़क होती है। इसलिए इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये कुछेक बिन्दु थे। अध्यक्ष जी, जो आपने मांग संख्या-10 यहां पर चर्चा के लिए रखी है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

28.03.2016/1730/जेएस/एएस/1

श्री सुरेश भारद्वाजः ....जारी-----

और उसमें कटौती प्रस्ताव हमने दिया है इस पर कुछ सुझाव दिए हैं और इस तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान देंगे। मुश्किल मुझे यह लग रही है क्योंकि यहां पर चर्चा भी आई थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर कोई जे0ई0 काम नहीं करेगा तो मैं उसको सर्वेयर बना दूंगा। अगर कोई एस0डी0ओ0 काम नहीं करेगा तो मैं उसको जे0ई0 बना दूंगा। ___(व्यवधान)___

मुख्य मंत्रीः क्या चीफ इंजीनियर भी सर्वेयर बन सकता है? I said that stringent action will be taken against them. ये कैसी बात है कि एग्जैक्टिव इंजीनियर को एस0डी0ओ0 बना देंगे, एस0डी0ओ0 को जे0ई0 बना देंगे। Is it possible? No court will allow that. We will take action against them for this laxity.

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि जो चीज हो नहीं सकती, जो कोर्ट नहीं कर सकती और आप भी नहीं कर सकते हैं वह फिर आप क्यों बोलते हैं?

आप ऐसा बोला ही न करो। आपके मुंह से निकली हुई बात एक रूल बन जाती है।

मुख्य मंत्रीः ऐसा मैंने नहीं कहा। सुनिए बात ऐसी है I have never said that . I am an experienced person how can I say that Chief Engineer will made into SE and SE will be made into JE. ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि जो काम नहीं करेंगे who are not efficient in doing their work then appropriate action will be taken against them, this is what I said.

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस डीमांड पर बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2016/1730/जेएस/एएस/2

अध्यक्षः अब श्री रविन्द्र सिंह जी मांग संख्या-10 पर चर्चा करेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-10 लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन इस पर जो हमने कटौती प्रस्ताव दिए हैं जिसमें हमने कहा है कि सरकार की सड़कों,पुलों एवं भवनों के निर्माण एवं मुरम्मत व रख-रखाव की नीति का अनुनमोदन, सरकार की मशीनरी एवं उपकरण क्रय एवं आबंटन की नीति का अनुनमोदन और तीसरा था सरकार की जिला व अन्य सड़कों को जोड़ने की नीति का अनुनमोदन।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में यह विभाग माननीय मुख्य मंत्री महोदय के पास है। हिमाचल प्रदेश जिसको लगतातार माननीय मुख्य मंत्री जी बोलते हैं कि सारी की सारी सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं। लेकिन इस समय इन सड़कों का पूरे प्रदेश में क्या हाल है यहां का पर्यटक जो यहां आता है, यहां के लोग जो इन सड़कों पर चलते हैं और यहां के वाहन जितने भी यहां चलते हैं। प्रदेश का जो बाऊंडरी एरिया जो हमारा पड़ता है जब आप वहां से एन्ट्र करेंगे तो साथ लगते प्रदेश या तो पंजाब है या हरियाणा है या

उत्तराखंड है। मुख्य मंत्री महोदय इन सभी प्रदेशों से आज हमें एक दर्पण लेने की आवश्यकता है। पिछले कल घूमते-घूमते मैं अपने घर से चला था और आज यहां इस माननीय सदन में पहुंचा हूं । लेकिन वहां की सड़कें ठीक है क्योंकि वहां प्लेन एरिया है उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना बड़ा बजट देने के उपरान्त भी 3100 करोड़ रूपया इस विभाग के लिए इस आने वाले वर्ष के लिए आपने आबंटन किया है। हम मानते हैं कि मूलतः इसका बड़ा भाग सैलरीज़ के ऊपर चला जाता है। कर्मचारियों के ऊपर खर्च होता है। कुल मिला करके अगर आप देंखेंगे तो 15 से 20 प्रतिशत तक उसमें खर्चा आएगा। चाहे वह नई सड़कों के निर्माण का हो, चाहे रख-रखाव का हो, भवनों के निर्माण का हो या अन्य कोई भी जो इसके अन्तर्गत विकास के काम करने होते हैं वे सारे के सारे इसमें आते हैं। मुझे तरस आता है हमारे जो चम्बा के विधायक, हमारे चुराह के विधायक, श्री हंस राज जी, श्री जरयाल जी, श्री बी0के0 चौहान जी, श्रीमती आशा कुमारी जी और इनको

28.03.2016/1730/जेएस/एएस/3

भी हम गिन सकते हैं ये कभी-कभी जाते होंगे भरमौरी जी। श्री रवि ठाकुर जी, लाहौल-स्पिति से आते हैं, किन्नौर से हमारे उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी जी और रोहड़ू से माननीय विधायक, श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी और शिलाई से हमारे बलदेव सिंह तौमर जी इनके शिमला पहुंचते-पहुंचते क्या दुर्दशा होती होगी, ये आप कल्पना कर सकते हैं? जरयाल जी माननीय विधायक तो पीछे लगातार डिस्क प्राब्लम से बीमार भी रहे और इनका उपचार होता रहा। ये सड़कें पूरे हिमाचल को दर्शाती हैं कि हम किस दिशा की ओर इन सड़कों के निर्माण के लिए, इन सड़कों के रख-रखाव के लिए किस ओर जा रहे हैं?

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

28.03.2016/1735/SS-AS/1

श्री रविन्द्र सिंह क्रमागतः

यह सही है कि आज़ादी के उपरांत हिमाचल में जो आप लगातार कहते हैं कि जब हमारा पांच जिलों को लेकर प्रदेश बना था तो उस समय 288 किलोमीटर सड़कें थीं। वह तो ठीक है लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 1947 से लेकर 1977 तक जो आपका समय रहा, उसके मध्य आपने 288 किलोमीटर सड़कों को बढ़ाकर कितने किलोमीटर किया था? जिस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय इसको थोड़ी दिशा दी गई थी। गांव की तरफ विकास का रुख मोड़ा गया। सड़कों के निर्माण की कल्पना की गई। उसके बाद लगातार जो भी सरकारें सत्ता में आती रहीं उसमें निरंतर यहां काम होते रहे। लेकिन सारे-का-सारा श्रेय आज के दिन हिमाचल प्रदेश या देश के किसी प्रदेश में देना होगा तो निश्चित रूप से वह हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। जिन्होंने 1998 में आकर भारतवर्ष के उन तमाम गावों को जिनकी आबादी एक हजार और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में 500 की आबादी और वर्तमान में 250 और आजकल कलस्टर में लेना शुरू कर दिया है उन तमाम गावों को सड़कों के साथ जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी योजना 'प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना' इस प्रदेश और देश को दी। लेकिन हम उसके अन्तर्गत देखेंगे तो हमें हैरानी होती है कि इतना कुछ बजट मिलने के उपरांत भी कुछ विकास नहीं हुआ। मुझ से पूर्ववक्ताओं ने यहां पर कहा भी है। जैसे हम प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना लें तो उसके अन्तर्गत हमारे समय जब धूमल जी 1998 से लेकर 2003 में मुख्य मंत्री रहे तो प्रधानमंत्री सड़क योजना का फेज़-I और फेज-II हुआ करता था। एक पूरे-का-पूरा पैकेज बनता था। एक सड़क को लिया जाता था। वह सारी सड़क सैंक्शन होकर उसका पूरा निर्माण कर दिया जाता था। सड़क बनने के उपरांत 5 वर्ष तक ठेकेदार उसका रख-रखाव करता था। लेकिन बीच में जब 2003 में सरकार बदल गई तो आपने इसमें बदलाव कर दिये। वह बदलाव यह किया कि पहले फेज-I की सड़कें बनाओ। ऐसी कल्पना करनी भी नहीं चाहिए थी और होना भी नहीं चाहिए था। जो पूरे प्रदेश का कोर नैटवर्क बना, उसमें जैसे पहले चार-पांच साल काम होता रहा, उसमें उसी ढंग से काम होना चाहिए था। लेकिन बीच में आपने सारा बदलाव कर दिया। हमारे माननीय सदस्य कह भी रहे हैं कि उसके कारण आज भी फेज-I की सड़कें अधूरी पड़ी हैं। उनमें कईयों को 10-10 साल हो गये। उसके पीछे कारण क्या है? विभाग को फेज-II के लिए भी

28.03.2016/1735/SS-AS/2

प्रायोरिटी देनी चाहिए। यह फेज-। की सड़क बन गई है तो फेज-॥ में हम पहले उनको प्राथमिकता देंगे जो कोर नेटवर्क बन चुका है। लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई तवज्जो विभाग/सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। यह मैं कहना चाहता हूं।

इस तरह से जहां तक विधायक प्राथमिकता वाली सड़कों का प्रश्न है, मुख्य मंत्री महोदय मुझे याद है कि आपने एक बार प्लानिंग की मीटिंग में कहा था कि हर साल इसकी दो बार मीटिंग हुआ करेगी। एक तो हम बजट सत्र से पहले जनवरी या फरवरी माह में करते हैं और दूसरी आपने कहा था कि सितम्बर माह में मीटिंग किया करेंगे। वह सब कुछ आपका कागज़ों और भाषणों में ही रह गया। आज हमारी स्थिति क्या है जो विपक्ष के विधायक हैं और मुझे लगता है कि पक्ष वाले भी ऐसे ही होंगे। इसके पीछे कारण क्या है? जो आपने पिक एंड चूज़ शुरू कर दिया उसकी वजह से है। मुख्य मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि जो अधिकारी/कर्मचारी किसी विधान सभा क्षेत्र में डिवीजन में बैठे हैं उनको उस समय तक न बदला जाए जब तक कि वे एम0एल0ए0 प्रायोरिटी की सड़कों की डी0पी0आरज़0 न बना दें। आपने उनको प्रॅमोट भी कर दिया, वे खुश भी हो गये लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रॅमोशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते लेकिन अगर उनकी प्रॅमोशन हुई है तो उनको वहीं रखो। आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप जे0ई0, सर्वेयर, एस0डी0ओ0 या एक्सियन हैं इस प्रकिया को पूरा करने के उपरांत ही आप आगे जाओगे। नहीं तो आप यहीं पर रहेंगे। भले ही उनको प्रॅमोशन दे दो, लेकिन उन्हें वहीं रखो और कहो कि आपके कार्यकाल में विधायक प्राथमिकता की जो सड़कें लम्बित पड़ी हैं उनकी डी0पी0आर0 बनाकर ही आप अन्य जगह जायेंगे। अगर आप ऐसी योजना बनायेंगे तो मुझे लगता है कि इससे विधायक भी खुश होंगे। लेकिन दूसरा मैं इसमें निश्चित रूप से कहना चाहूंगा जो माननीय महेन्द्र सिंह जी और अन्य विधायकों ने कहा है कि नाबार्ड साहब देखे हुए हमें कई दिन हो गये। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे यहां इसमें दो सड़कें सैंक्शन हुई हैं लेकिन मेरे वहां विधायक बनने के बाद कोई डी0पी0आर0 नहीं बनी है।

जारी श्रीमती के0एस0

28.03.2016/1740/केएस/डीसी/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी---

वे दोनों की दोनों सड़कें मेरे से पहले जो प्रायोरिटी में डाली थी, पुराना जो जसवां विधान सभा क्षेत्र हुआ करता था, जो आज देहरा में आया है, वहां की दो सड़कें नाबार्ड में आई हैं, वे उस समय की है। 2013-14, 2014-15, 2015-16 जो आपने इन सड़कों या पुलों के निर्माण के लिए, जो हमारी बन गई हैं, मुझे लगता है तीन साल की हमारी छः-छः बन गई है, अब दो और बन जाएगी तो आठ बन जाएगी उनकी स्थिति क्या है, वह आप देखें और जरा उस नाबार्ड के दर्शन हमें भी कराएं, नाबार्ड की हम भी पूजा कर लेंगें लेकिन यह नाबार्ड है तो है कहां? अध्यक्ष महोदय, यहां पर रिक्त पदों का जिक्र किया गया। सही मायने में जो रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह कोई नहीं रखा जा रहा। ड्राईंग ब्रांच जो इसमें सही मायने में काम करती है उसमें सारे के सारे पद रिक्त पड़े हैं। जो डी.पी.आर. बननी है, उसके लिए अगर फोरैस्ट क्लीयरैंस लेनी है, आज ही मेरा एक प्रश्न लगा था, शहीद विजेन्द्र सिंह मार्ग के बारे में । विजेन्द्र सिंह कारगिल के युद्ध में सबसे पहले शहीद होने वाला है। हम उस समय जब यहां से धूमल जी के साथ चम्बा के लिए चले तो सपनी ज्वालाजी लैंड किया था और वहां से उनके घर तक लगभग छः किलोमीटर हम पैदल गए थे । उस समय धूमल जी ने वहां पर घोषणा की थी कि शहीद विजेन्द्र सिंह के नाम पर सड़क को हम प्राथमिकता पर बनाएंगें। सारे पैसे भी उस समय दिए। अभी तक भी वह नहीं बन पाई है क्योंकि बीच में उस सड़क में फोरैस्ट क्लीयरैंस की प्रॉब्लम आ गई है और मैं ही इस सम्बन्ध में विभाग के डी.एफ.ओ., एक्सिअन को बुलाकर तीन बार मीटिंग कर चुका हूं। अब कहां, क्या ऑब्जैक्शन उसके ऊपर लग रहे हैं हमें यही समझ नहीं आ रहा है और उसके ऊपर आज भी यही जवाब दिया है कि इससे आगे फोरैस्ट आ गया है इसलिए यह सड़क नहीं बन सकती। ऐसे ही पूरे प्रदेश के सभी विधायकों के जो फोरैस्ट क्लीयरैंसिज़ के केसिज़ हैं, इनको प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। आपने अब कह भी दिया कि एक हैक्टेयर तक अब यहीं पर आप क्लीयरैंस दे देंगें तो सड़कों का कार्य प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। एक तरफ तो मुख्य मंत्री महोदय जंगल के जंगल कट जाते हैं। आपकी रिपोर्ट आई 1400-1500 पेड़ चम्बा में

28.03.2016/1740/केएस/डीसी/2

कट गए, 400-500 पेड़ यहां पर कट गए उसके बाद लगातार प्रदेश की कई जगहों से सूचना आती रही है लेकिन सड़कों के निर्माण में, शहीदों के नाम से जब सड़कों का निर्माण होना होता है तो बीस तरह के ऑब्जैक्शन लग जाते हैं। यह जो प्रक्रिया है इसको चेंज करने की आवश्यकता है। साथ ही मेरा यह भी अनुरोध रहेगा कि रेवन्यू डिपार्टमैंट में कानूनगो और पटवारी चाहिए होते हैं, सही मायने में उनकी कमी है लेकिन जो रिटायर हो गए हैं, उनको आप अगेंज करते हैं और अंगेज़ करने के बाद जो उनको पैसा मिलना चाहिए, जो तनख्वाह उनकी होती है, उसके बराबर का पैसा नहीं मिलता। इसलिए वे काम नहीं करना चाहते इसलिए मेरा आग्रह है कि उनको जो फीस देनी होती है, जो उन्होंने रेवन्यू के कागज़ात तैयार करने हैं, उसमें बढ़ौत्तरी की जाए। इसी तरह से पूरे प्रदेश की जो टैंडर प्रक्रिया है, मैं लगातार मेरे पास जो विभाग था, उसमें भी करता आया लेकिन यह प्रक्रिया बड़ी लम्बी रखी है। इस टैंडर प्रक्रिया को कम करें। अब तो डिज़िटल इंडिया का नाम आ गया। अब तो सारे का सारा ऑन लाईन हो गया। उस ऑन लाईन की प्रक्रिया को यहां अडॉप्ट करें। किया तो यहां पर है लेकिन जो समय पूरे का पूरा दे दिया, एक टैंडर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन महीने का समय दिया, आज टैंडर डालेंगें तो तीन महीने के उपरांत टैंडर निकलेंगें और उसके बाद भी फिर पता नहीं नैगोसिएशन करेंगें, उसके उपरांत दूसरे को बुलाएंगें, नहीं होगा तो बीच में जब वहां पर उनका रेट कम करेंगें तो वह मामला लम्बित पड़ जाता है, ठेकेदार करते ही नहीं है। नहीं करते फिर उसको रिज़ाइन करना पड़ता है और रिज़ाईन की प्रक्रिया छः महीने की चलती है। छः महीने से पहले आप उस कॉंट्रैक्ट को रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। इसमें भी अब समय आ गया है कि इसमें बदलाव किया जाए। रिज़ाइन करने के लिए इतना लम्बा समय लगाने की क्या जरूरत है? उसका समय कम कर दो। उसमें दो महीने-तीन महीने का समय दे दो। एक्सपैरिमैंट के तौर पर शुरू तो करो ताकि वहां पर जल्दी काम हो। साथ ही जो डिपोज़िट वर्कस आपके हैं, विभिन्न विभागों का पैसा आपके पास लम्बित पड़ा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 9 स्कूलों के पैसे लोक निर्माण विभाग के पास

28.03.2016/1740/केएस/डीसी/3

पड़े हैं। तीन पी.एच.सी. के पैसे वहां पर पड़े हैं। ऐसे ही अन्य विभागों के डिपोज़िट लोक निर्माण विभाग के पास पड़े हुए हैं। अभी तक उनकी टैंडर प्रक्रिया भी नहीं हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि डिपोजिट के पैसे या तो विभाग को कहो अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरे किसी को अन्य एजैंन्सीज़ भी आजकल काम करने के लिए तैयार है उनको वहां पर उस काम में लगाए। दूसरे, आजकल पूरे प्रदेश की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध रहेगा कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

28.3.2016/1745/av/डीसी/1

श्री रविन्द्र सिंह------ जारी

मुख्य मंत्री महोदय, आपने जो इतना बड़ा बजट रखा है इन सड़कों के रख-रखाव के लिए या ड्रेनेज सिस्टम के लिए या इनकी मुरम्मत के लिए एक अलग अमाउंट 500-700 करोड़ रुपये पूरे प्रदेश के लिए अलग रखें ताकि केवलमात्र उनकी मुरम्मत हो और ड्रेनेज सिस्टम बनें। यह मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सिस्टम को एडोप्ट करें ताकि सड़कों की रिपेयर और रख-रखाव ठीक से हो सके। यहां पर आदरणीय महेन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा था कि सैंट्रल रोड फंड, नेशनल हाई-वे और वर्ल्ड बैंक प्रोजैक्ट पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने सभी के लिए अलग-अलग सिस्टम तो किए मगर जो आपने एक मुश्त पैसा रख दिया इसका क्या मतलब है? हमने पिछले साल भी कहा था और इस बार फिर से कह रहे हैं कि एक मुश्त पैसा किस लिए रखा जा रहा है? जहां-जहां, जिन-जिन इलाकों की सड़कें सैंट्रल रोड फंड, नेशनल हाई-वे या वर्ल्ड बैंक प्रोजैक्ट में आई हुई हैं आप इनके लिए पैसों का सीधे आबंटन कीजिए। वहां पर पैसा सीधे काम के लिए जाए ताकि काम बीच में न लटके। आपकी सरकार के आने के उपरांत एक नई प्रथा शुरू हो गई है। हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। आप जहां

जाते हैं वहां घोषणा कर देते हैं कि मैंने इतना पैसा दे दिया और कटौती एक मुश्त के लिए विधायक के बजट से की जाती है। वहां जो विधायक का कोटा बनता है उसमें से कटौती करके उसको एक मुश्त रखा जाता है। इस एक मुश्त का आप विभिन्न विधान सभा क्षेत्र के तहत वर्क वाइज आबंटन कर दें। आप 31 मार्च को जब इस बारे में जवाब देंगे तो जहां-जहां के लिए सैंक्शन्ज आई हैं वहां-वहां के लिए निश्चित तौर पर करें, मेरा आपसे यह अनुरोध रहेगा। इसके अतिरिक्त आपने सड़कों के निर्माण के बाद उनके रख-रखाव के लिए वैसे ई0एन0सी0 ऑफिस में एक क्वालिटी कंट्रोल विंग बना हुआ है। यहां पर उस बारे में महेश्वर सिंह जी के प्रश्न का जवाब आया था कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपने तीन तरह की प्रणालियां एडोप्ट की हैं। वह प्रणाली बहुत लम्बी है। विभाग अपने सेवानिवृत इंजीनियर्ज को मॉनिटर के तौर पर भर्ती कर रहा है। उनको इससे कुछ लेना-देना नहीं होता है। वह टूर प्रोग्राम बनाते हैं, रैस्ट हाउस में जाकर सोते हैं और उनके खूब मजे करवाए जाते हैं। जब उनकी वहां पर सेवा हो जायेगी तो उस डिविजन के अगेंस्ट नेगेटिव कैसे लिखेंगे? आज हमारे जिन नौजवानों ने डिग्रियां कर रखी हैं, आप उनको बुलाइए। उनकी क्लास लीजिए, उनको समझाइए कि आपको विभाग क्वालिटी चैक करने का काम दे रहा है। इससे आपकी बेरोजगारी की समस्या भी

28.3.2016/1745/av/डीसी/2

हल होगी। युवा शक्ति सड़कों के क्वालिटी कंट्रोल को चैक करने के लिए लगें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 58 साल नौकरी करने के उपरांत फिर मॉनिटरिंग का काम देना मुझे उचित नहीं लगा। ये लोग तो पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं, इन मॉनिटरों से बचो। हम कई बार पता करते हैं और पूछते हैं तो बताया जाता है कि ठेकेदार तो मॉनिटर के पास गया है। जब मॉनिटर की सेवा होगी तो वह नेगेटिव कैसे लिखेगा? वह तो उनके पक्ष में लिखेगा इसलिए मेरा सुझाव है कि उन मॉनिटरों को निकाल कर इस काम को बेरोजगार डिग्री होल्डर या डिप्लोमा होल्डर को दिया जाए। यहां पर प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क की क्वालिटी कंट्रोल को जांचने के लिए तीन स्तरीय जांच प्रणाली बताई है। प्रथम आप विभागीय स्तर पर करते हैं। द्वितीय स्तर पर स्टेट क्वालिटी मॉनिटरिंग करते हैं तथा तृतीय स्तर पर नेशनल

क्वालिटी मोनिटर है। इनके द्वारा समय-समय पर वहां जांच की जाती है। इसी तरह से नाबार्ड और सी0आर0एफ0 पर भी आपने द्वितीय स्तर की प्रणाली बताई है उसमें यह कहा है कि इसको आपका क्वालिटी कंट्रोल विंग देखता है। आपने यह भी बताया है कि यहां पर सात प्राइवेट लैब को काम दे रखा है। महेन्द्र सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई समय था जब सरिया 6000 रुपये तक पहुंच गया था मगर आज उस सरिया का रेट 3200-3500 रुपये तक डाउन आ गया है। उस समय जो माल पर्चेज करके भेज दिया, अगर आज उसकी स्थिति देखेंगे तो रेट कितना डाउन आ गया है। इसी तरह से बिचुमन का रेट है।

टीसी द्वारा जारी

28.03.2016/1750/TCV/AG/1

श्री रविन्द्र सिंह ----- जारी

वह भी डाउन आ गया है लेकिन बिचुमन की क्वॉलिटी नहीं है। बिचुमन आप डालते हैं और दूसरे दिन वह उखड़ने लग जाती है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब आपका दौरा होता है तो हम देखते हैं कि जब आप आते हैं तो सड़कें सारी चक्का-चक्क हो जाती है लेकिन जैसे ही आप जाते हैं उसके 10 दिन बात सड़क का पता ही नहीं होता है कि सड़क थी भी या नहीं । यह स्थिति देखने में आई है और ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। हम चाहेंगे कि इसके ऊपर निश्चित तौर पर आपका जो विंग बना है उसको सशक्त करें। यह भी चैक करें कि जो बिचुमन आ रहा है उसकी क्वालिटी सही आ रही है या जो सरिया परचेज किया जा रहा है इसको समय पर परचेज करें , इसके लिए मार्च महीने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। इसकी जब-जब और जहां-जहां आवश्यकता होती है यह उसी समय पर होना चाहिए। एक और मैं सुझाव देना चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग के एस्टीमेट्स बहुत भारी बनते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय 2-2 ट्रक सरकार सीमेंट के बेचते हुए मैंने पकड़े हैं। अभी डाडासिबा में एक जे0ई0 सस्पेंड है और ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश के अन्दर है। इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इनको बुलाइये और कहिए कि इतना एस्टीमेट क्यों बनाते है? एक छोटी-सी कलवर्ट बनाने के लिए 5 लाख का एस्टीमेट बनाया जाता है वहीं ग्रामीण विकास विभाग

उसी कलवर्ट को उससे भी ज्यादा मजबूत लगभग 2 लाख में बना देता है। उसमें भी क्वालिटी वही है, सारी चीजें वहीं है लोक निर्माण विभाग का जे0ई0 ही वहां पर डैपूटेशन पर जाता है। लोक निर्माण विभाग का जे0ई0 जब ग्रामीण विकास विभाग में डैपूटेशन पर जाएगा तो एस्टीमेट 2 लाख में बनाएगा और जब वह लोक निर्माण विभाग में वापिस आएगा तो वही एस्टीमेट 5 लाख में बनाएगा। इसलिए इसको भी चैक करने की आवश्यकता है। एक मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात आपके समक्ष रखूंगा। मुख्य मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर नगरोटा-सूरियां से लेकर रानीताल तक उस इलाके की स्थिति इतनी दयनीय हैं कि रेलवे वाले गुलेर से लेकर नगरोट- सूरियां तक जो हमारी सड़क है, उसको नाबार्ड में डाला हुआ है और इसके लिए हर साल बजट पड़ता है। रेलवे वाला एक लोकल जे0ई0 वहां का लगा हुआ है वह उस काम को बार-बार रूका देता है।

28.03.2016/1750/TCV/AG/2

अभी मैंने पीछे फिरोजपुर से रेलवे का स्टॉफ बुलाकर उसकी डिमार्केशन करवा दी है। अब सिर्फ 200 मीटर का पैच रह गया है जहां हमें रेलवे की एन0ओ0सी0 चाहिए है। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक तो उसको रेलवे अथोरिटी के साथ टेकअप करने के लिए प्रयास करें। वहां काम करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लोकल स्टॉफ ज्यादा तंग करता है। आज उस सड़क को नगरोटा-सूरियां जो गुलेर क्षेत्र और हरिपुर का इलाका पड़ता है उसको जाने के लिए 18 या 20 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। यदि यह सड़क हमारी पूरी बना जाएगी तो कुल मात्र 6 किलोमीटर रह जाएगा। उस सड़क का काम ऊना के एक कांट्रेक्टर को दे रखा है और उसने वह काम सबलैट करके आगे दे रखा है, यह बात मैं पिछले 3 साल से सुन रहा हूं लेकिन न तो वहां पर कलवर्ट/पुल बन रहे हैं और न डंगे लग रहे हैं। ऐसी ही उस रेलवे लाईन के ऊपर फाटक या क्रॉसिंग बननी है। इसको हमने भारत सरकार के साथ भी टेकअप किया है मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर विभाग इसको टेकअप करेगा तो जल्दी हो जाएगा। इसी तरह से मैंने आपके समक्ष जो शहीद वजिन्द्र सिंह मार्ग की बात कही है इसमें

सारे-का-का सारा केस बना हुआ है इसका एन0ओ0सी0 अगर शीघ्रातिशीघ्र हो जाएगा तो उस परिवार और गांव को भी सड़क देखने को मिलेगी। ऐसी ही हमारी सड़क ज्वालामुखी से देहरा और देहरा से ज्वाली है, इस सड़क का इस समय इतना बुरा हाल है कि खड्डों में सड़क है कि सड़कों में खड्डा है इसका कोई पता नहीं लगता। वैसे तो यह हाल पूरे प्रदेश में ही है। क्योंकि लंज से जब मैं निकला तो नगरोट-सूरियां जो ज्वाली विधान सभा क्षेत्र में ही आता है मैं तो सोच रहा था कि मेरे ही इलाके में बहुत बुरा हाल है लेकिन श्री सुजान सिंह पठानियां जी के इलाके में भी वैसा ही हाल है। मैंने चम्बा पतन का जो पुल बना हुआ है उसके आगे कुटयारा में आना था श्री संजय रतन जी उस सड़क का तो बहुत बुरा हाल है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ये पूरे प्रदेश की सड़कों का हाल है। इन सड़कों को निश्चित तौर पर देखने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि देहरा विधान सभा क्षेत्र में आप जाते तो रहे हैं लेकिन कई बार आपने अपना दौरा कैंसल भी कर दिया और

श्री आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

28.03.2016/1755/RKS/AG/1

श्री रविन्द्र सिंह...जारी

जैसे महेन्द्र सिंह जी को आपने कहा कि आपका बस अड्डा खड्डु में बना था। धर्मपुर का बस अड्डा जो खड्डु में बना था बाढ़ आने के कारण बह गया।

मुख्य मंत्रीः अगर नाले में बनाएंगे तो बहेगा ही।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जो नेशनल हाईवे के ऊपर जमीन दे रखी है उस केंद्रीय विश्वविद्यालय को आप चलान खड्डु में क्यों बना रहे हैं?

मुख्य मंत्रीः मुझे नहीं पता।

श्री रविन्द्र सिंहः आप उसे देख लेना। उसका शिलान्यास करने के लिए जब आप आएंगे

तो आपका स्वागत करने के लिए मैं और संजय रतन जी आएंगे। 3 हजार कनाल भूमि वहां उसके नाम ट्रांसफर कर दी गई है। जब खड्ड में अड्डा नहीं बन सकता है तो यह तो बहुत बड़ा संस्थान है। बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी जिसके बारे में आपको ज्यादा मालूम है। यह बात मैं आपकी बात के साथ जोड़ कर कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2016/1755/RKS/AG/2

अध्यक्षः अब श्री राजीव बिन्दल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजीव बिन्दलः माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्याः 10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद। मैं चंद सुझाव जिन पर पहले भी चर्चा हुई है उसी के बारे में बात करुंगा। अभी हमारे सभी विधायकों ने डी.पी.आर. का विषय रखा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्लानिंग की मीटिंग में यह आदेश दिए थे कि रेवन्यू डिपार्टमेंट, फोरेस्ट डिपार्टमेंट और पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट ये ज्वाईंटली मिलकर डी.पी.आरज. को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। सभी लोगों ने इसका स्वागत किया। परन्तु उस प्लानिंग की मीटिंग से आज तक किसी भी विभाग ने इनिशिएटिव लेकर इस दिशा के अंदर कोई काम नहीं किया। पिछले हफ्ते जिलाधीश कार्यालय में मीटिंग थी। वन विभाग के अधिकारी कहते हैं फाइल डी.सी. साहिब के पास है, डी.सी. साहिब कहते हैं पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के पास है, पी.डब्ल्यू.डी. वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है। जब तक हम इसको इम्पलीमेंट नहीं करेंगे तब तक स्थिति इस तरह की ही रहेगी और हम उसी प्रकार से चलते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय सड़कों की खुदाई को लेकर अनेक बार बात हो गई। मैंने प्राईवेट मैंम्बर डे में भी इस विषय को उठाया था। उस समय भी आपने आश्वस्त किया था। हिमाचल की सभी सड़कें खोदी हुई हैं। आपने कहा था कि 200 मीटर के बाद बंद करने का प्रावधान है। कोई भी सड़क 200 मीटर के बार बंद नहीं कर रहे हैं। सभी सड़कों पर तारें डालने का काम चला हुआ है, जिस कारण सारी सड़कें खुदी हुई हैं। अगर आप इस बात को नहीं मानना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। मुझे तो यह बताया गया है कि इन सड़कों का ठेका कांग्रेस के बड़े नेता को दिया गया है इसलिए

यह सड़कें नहीं बन रही है।

मुख्य मंत्रीः वह ठेकेदार कौन है?

श्री राजीव बिन्दलः आपको बता देंगे। आपको पता है।

28.03.2016/1755/RKS/AG/3

मुख्य मंत्रीः बताइए कौन सी सड़क है और कौन ठेकेदार है? मुझे नहीं पता है। आप मुझे बताइए।

श्री राजीव बिन्दलः सर, आप पता कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय जो सड़कों के बारे में बार-बार आता रहा है कि जीपेबल सड़कों को पास करने का प्रावधान है। पंचायतों द्वारा जो सड़कें बनाई गई हैं वे जीपेबल रोड़ हैं और वे सड़कें मोटरएबल नहीं बन नहीं सकती है। उनका ग्रेड वाजिब नहीं है। जब तक हम उसको पास नहीं करेंगे उसके ऊपर सवारी, गाड़ी चलना संभव नहीं है। चाहे वह 10 सीटर हो या 5 सीटर हो, गाड़ियां न चलने से बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके लिए आपने सदन में पिछले साल भी आश्वस्त किया था और शायद हमारी सरकार के समय में भी इसमें विचार हुआ था। परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। यह बहुत जरूरी है।

श्री एस.एल.एस द्वारा ....जारी

28.03.2016/1800/SLS-AS-1

डॉ० राजीव बिन्दल ...जारी

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बात आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। हो सकता है इनके ध्यान में हो। आज जो बात सड़कों की दुर्दशा को लेकर सभी सदस्यों ने की है, जिस भी डिविजन में रिपेयर या मेंटेनैंस के लाख, दो लाख या पांच लाख रुपये के छोटे ठेके हो रहे हैं, उनके लिए सीधे-सीधे एक्स-ई-एन दफतर में कांग्रेस से संबंधित ठेकेदारों को बुलाकर अलॉटमैंट हो रही है

और वह कोई भी कार्य स्वयं न कर दूसरे व्यक्ति को सबलैट कर रहे हैं। जिसको सबलैट किया, उससे परसैंटेज मिल रही है जिसके कारण यह स्थिति खराब हो रही है। अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो प्रदेश के पैसे का सत्यानाश हो रहा है और सरकार को यह बदनामी मिल रही है। इसलिए इसको रोकने की नितांत आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, जिस सड़क के ऊपर किसी ठेकेदार का टैंडर हुआ है, चाहे नाबार्ड सड़क है या पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़क है, ठेकेदार को उसके लिए पैसा दिया जा रहा है लेकिन उस सड़क पर सरकारी मशीनरी काम कर रही है। यह चिंता का विषय है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप पिछले दिनों मेरे विधान क्षेत्र भेड़ों गांव में गए थे। भेड़ों सड़क पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत बनी। उसमें पी.एम.जी.एस.वाई. का सारा पैसा लगा और सरकारी मशीनरी ने लगातार 6 महीनों तक उस सड़क पर काम किया है। वह किस हैड से चार्ज हुआ है? इसका मतलब है पी.एम.जी.एस.वाई. का भी पैसा गया और हमारी मशीनरी में हमारा भी पैसा लगा। मैंने बार-बार एक्स-ई-एन को बोला कि जब यह पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़क है तो इसमें सरकारी मशीनरी क्यों लगी है? परंतु विभाग की कौन-सी ऐसी मजबूरी है कि ठेकेदार को भी पैसा दे रहे हैं और सरकारी मशीनरी भी काम कर रही है। यह गंभीर बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जय राम ठाकुर जी का प्रश्न लगा था। उसी से हमने डिटेल निकाली है। माननीय मुख्य मंत्री जी, विधान सभा क्षेत्रों में जो मशीनरी लगी है उसमें मैं केवल दो चीजों की बात करूंगा। डोजर और जे.सी.बी. - एक्सकावेटर-कम-लोडर। कितने ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं जहां 7 हैं और किसी में 8 भी हैं लेकिन हमारे विधान सभा क्षेत्रों में केवल 2 हैं। दो में से पिछले 6 सालों से एक बिल्कुल बंद पड़ा है, उसमें जंग लगा है। दूसरे के बारे में मुझे बिल्कुल स्पष्ट कहना है, हमारे मित्र (श्री विनय कुमार जी) यहां पर

28.03.2016/1800/SLS-AS-2

बैठे हैं, ये 90 परसैंट टाईम उसको रेणुकाजी विधान सभा क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं। मैं बार-बार एक्स-ई-एन साहब और इनको भी बोलता हूं कि मेहरबानी करो। आपके यहां पर 5 एक्सकावेटर-कम-लोडर डोजर हैं, अपने चला लो, नाहन विधान सभा क्षेत्र के

मत ले जाओ। इसलिए कृपया विभाग को आदेश दें कि नाहन विधान सभा क्षेत्र में मशीनरी कम है, उसको बढ़ाने की कृपा करें और मेरे पड़ोसी मित्र वहां से मशीनरी को न ले जाएं। ये पूरे सिरमौर का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषकर दो सड़कों का ज़िक्र करूंगा। कोलर-बिलासपुर इंटर स्टेट कनैक्टिविटी की सड़क है। इसी तरह से मैंने पिछले बजट के दौरान भी बताया था कि खजूरना से सकेती हरियाणा को जोड़ने वाली सड़क है। सकेती पार्क में इस बार इंटरनेशनल कॉंफ्रेंस हो रही है। उसकी 16.50 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. बनी है। मैंने आग्रह किया था कि उसको किसी-न-किसी हैड में डाल दें। एम.एल.ए. प्रॉयरिटी पर वह डी.पी.आर. बनी है; उसको डालने से हिमाचल प्रदेश की शान बढ़ेगी क्योंकि पूरी दुनिया से लोग सकेती फौसिल पार्क देखने के लिए आएंगे। आप भी जब वहां पर जाएंगे तो आपको भी फिर यह शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी कि हम इस सड़क के लिए पैसे नहीं दे पाए। आप इसको चाहे नाबार्ड को भेज दें, चाहे सी.आर.एफ. को भेज दें या इंटर स्टेट कनैक्टिविटी को भेज दें लेकिन कहीं से इसकी फंडिंग कराने का इंतजाम करें।

जारी ...गर्ग जी

28/03/2016/1805/RG/AS/1

डॉ. राजीव बिन्दल---क्रमागत

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां विधान सभा का एक प्रश्न संख्या 1857 लगा था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें जो पत्र लिखा, उसमें कहा था कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना में ज्यादा-से-ज्यादा पैसा हमको लेना चाहिए क्योंकि 90:10 की रेशो में मिलता है और प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना में तो शायद पूरा ही मिलता है।

मुख्य मंत्री : नहीं उसमें भी अब 15% कम हो गया।

डॉ. राजीव बिन्दल : ठीक है, सर। अब नाहन विधान सभा चुनाव क्षेत्र की एक भी सड़क

की पी.एम.जी.एस.वाई. में न तो डी.पी.आर. बनी, न वह फण्डिग के लिए गई और फर्स्ट फेज़ की आठ सड़कें ऐसी हैं जिनकी अभी तक डी.पी.आर. नहीं बनी। पूरे प्रदेश में शायद नाहन विधान सभा क्षेत्र ही ऐसा होगा जिसमें पी.एम.जी.एस.वाई. की फर्स्ट फेज़ की डी.पी.आर. नहीं बनी है। सेकण्ड फेज़ की कोई भी डी.पी.आर. बनाने का काम अभी नहीं चला है। इसमे तीसरी बात मैं यह बताना चाहूंगा कि 13 पुल जो वहां बनने हैं उनमें से 7 पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित हैं जो इसका पुराना खाका ड्रॉ किया है। अगर हम उनकी डी.पी.आर्ज. बनाकर केन्द्रीय प्रायोजित योजना यानि पी.एम.जी.एस.वाई. में भेज देंगे, तो प्रदेश का जो लोन अकॉउन्ट है उसके ऊपर इसका वजन नहीं पड़ेगा। यह भी मेरा यहां बहुत स्ट्राँगली कहना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा था, बात भी की थी और विभाग से भी बात की थी। हमारे यहां 13 पुल बनने हैं और इनके बिना लोगों का जीवन दूभर है। कुछ डी.पी.आर्ज. बन गई हैं और कुछ in progress हैं, परन्तु जो डी.पी.आर्ज. बन गई हैं उनकी फण्डिग शीघ्रता से हो जाए और जिनकी फण्डिग हुई है उनका काम शीघ्रता से हो। यह बहुत जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो quality of work की बात है उस बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप पिछले दिनों नाहन विधान सभा क्षेत्र में भेड़ो और पावंटा में आए और एन.एच.-72, खजूरना से लेकर के कटासन मंदिर तक सड़क के ऊपर पूरी रिपेयर एन.एच. ने की। सब कुछ किया और पता नहीं कितना खर्चा उसके ऊपर किया? जिस दिन आप निकल गए, तीसरे दिन बरसात हुई और आजकल

28/03/2016/1805/RG/AS/2

12-12 फुट चौड़े और 1-1 फुट गहरे गड्ढे उस नेशनल हाइवे पर पड़े हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, इसके ऊपर जांच करनी चाहिए कि वह खर्चा किस हैड से हुआ, किसने उस सड़क की रिपेयर की और वह पैसा कहां गया कि तीसरे दिन वह सड़क उखड़ गई। आज लोगों की गाड़ियां वहां टूट रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में अनेक सड़कें ऐसी हैं जिनके ऊपर न तो पैच वर्क हुआ, न ही किसी प्रकार का और कोई काम हुआ और मिट्टी भरने के अलावा वहां और कोई काम नहीं हो रहा है। जो डी.पी.आर. बनाने का काम विधायक प्राथमिकता में है उसमें भी हमें बार-बार आग्रह करना पड़ रहा है कि वे डी.पी.आर्ज. तेजी से बने। मैं केवल एक चीज आपके ध्यान में लाकर अपनी बात को समाप्त करुंगा। बार-बार यह कहा गया कि जो अधिकारी उस क्षेत्र में रहने वाला है, लगातार वहां पोस्टेड है और आज भी मेरा एक प्रश्न संख्या 3011 विधान सभा में लगा हुआ है। रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में एक अधिकारी जिसका नाम नरेन्द्र है, वह लगातार जे.ई. से लेकर ए.ई. से लेकर, लगातार वही पोस्टेड है। क्या वजह है हमें नहीं मालूम। परन्तु विभाग के नियमों कों ताक पर रखने का एक और प्रयास यहां हो रहा है।

मुख्य मंत्री : कहां लगा हुआ है और क्या है? लेबर होगा।

डॉ. राजीव बिन्दल : श्री नरेन्द्र रोहड़ू में लगा है। मैं आपको पूरी डिटेल भेज दूंगा and I will sign. नहीं जी, वह इंजीनियर है। लगातार वहां है, लेबर की कोई बात नहीं, लेबर तो वहीं रहेगा बेचारी, वह कहां जाएगी?

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। कल मैं बहुत दिनों के बाद चायल गया। चायल में पर्यटकों की भरमार थी,

एम.एस. द्वारा जारी

28/03/2016/1810/MS/DC/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी----------

परन्तु सड़क की दुर्दशा देखकर लगा कि इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता है। साधुपुल का पुल अभी नहीं बना है। लोगों की क्लच प्लेटें लगातार उड़ रही हैं। बहुत परेशानी है और बाकी की सड़कों की रिपेयर और मैंटीनैंस की दशा भी अच्छी नहीं है। ये मैंने अपनी बात कही है। नाहन विधान सभा क्षेत्र के पुलों, सड़कों के निर्माण के प्रति

गंभीरता बरतने की आवश्यकता है। एक और घोषणा मुख्य मंत्री जी पिछले दिनों नाहन के मालरोड के लिए करके आए थे और बहुत बड़ी खबर लगी थी लेकिन डेढ़ साल हो गया है, कुछ नहीं आया। वह सारा गड्डों में तब्दील हुआ है। अध्यक्ष जी, लोक निर्माण विभाग को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इतनी बात कहते हुए आपने मुझे मांग संख्या-10 पर बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

28/03/2016/1810/MS/DC/2

अध्यक्षः अभी दो माननीय सदस्य और बोलने को हैं। अभी समय तो काफी है लेकिन यदि दोनों ही माननीय सदस्य कम समय लेंगे तो माननीय मुख्य मंत्री जी भी आज ही इसका जवाब दे देंगे।

डॉ0 राजीव सैजलः अध्यक्ष जी, मैं मांग संख्या-10, लोक निर्माण, सड़क, पुल एवं भवन, पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।
जब से इस मांग पर चर्चा शुरू हुई है, मैं अपने सभी विधायक मित्रों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं भी डॉ0 राजीव बिन्दल जी की तरह पेशे से चिकित्सक हूं। अभी तक तो मुझे लगता था कि जो जीवधारी हैं, वही रोगग्रस्त होते हैं लेकिन अब देखने में आ रहा है कि सड़कें भी अब रोगग्रस्त हो रही हैं। अभी सभी विभागों में अगर हम देखें तो जो सबसे लचर कार्यशैली है!

अध्यक्षः डॉक्टरों को सब मरीज ही लगते हैं।

डॉ0 राजीव सैजलः लेकिन डॉक्टरों के डॉक्टर हमारे सामने मुख्य मंत्री जी बैठे हैं इन्हीं को समाधान करना है और इन्हीं को इन सड़कों की चिकित्सा करनी है। सम्माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर सड़कें हमारे जैसे पहाड़ी प्रदेश के लिए भाग्य की रेखाएं हैं लेकिन जो सड़कों की आज स्थिति है इसको देखकर इनको भाग्य की रेखाएं कहना कहां तक उचित होगा, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। मैं ज्यादा विस्तार में न जाता हुआ आपके माध्यम से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो सड़कों की स्थिति खराब है, उसकी ओर सरकार और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मेरे

निर्वाचन क्षेत्र का सबसे पुराना रोड, सबसे पहले अगर कोई रोड मेरे चुनाव क्षेत्र में बना है तो वह भोजनगर से मल्ला रोड है। अभी सम्माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ0 धनी राम शांडिल जी भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आए थे और मैंने इस रोड की दुर्दशा को लेकर इनका ध्यान भी आकर्षित किया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण कार्य चला हुआ है। अध्यक्ष जी, 28 नवम्बर, 2008 में एक ठेकेदार को यह सड़क का काम अवार्ड हुआ था। अब वर्ष 2016 आ गया है यानी तकरीबन 8 वर्ष इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किए हुए हो गया है। इस रोड की कुल लम्बाई 14.50 किलोमीटर है। इन 8 वर्षों

28/03/2016/1810/MS/DC/3

के अंतराल में केवल-मात्र 10.50 किलोमीटर के ऊपर काम हुआ है। अध्यक्ष जी, यह जो 10.50 किलोमीटर काम हुआ है इसमें से भी तकरीबन 5 किलोमीटर सड़क डडियारघाट से लोगोपुल तक उखड़ चुकी है और जो इस सड़क की वर्तमान स्थिति है उसको देखकर यकीन ही नहीं होता है कि यहां पर कभी सड़क रही होगी या यह सड़क पक्की हुई होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सड़क के अंदर बहुत ही घटिया कार्य हुआ है और हमारे क्षेत्र की तकरीबन 4-5 पंचायतों को यह सड़क जोड़ती है। हजारों लोग इस सड़क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उस सड़क के लिए 383.50 लाख रुपया स्वीकृत था।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

28.03.2016/1815/जेएस/डीसी/1

डॉ0 राजीव सैजलः-----जारी------

यह जो घटिया काम इस सड़क के अन्दर हुआ है मेरा निवेदन रहेगा कि इसकी जांच करवाई जाए। अभी सड़क बनने के तुरन्त बाद, उसके निर्माण के बाद सड़क उखड़ जाएगी जो कि चिन्ता का विषय है। इसी तरह से हमारे निर्वाचन क्षेत्र की जो अन्य सड़कें हैं उसमें परवाणू से बरोटीवाला वाया हरिपुर, ये हमारे निर्वाचन क्षेत्र को दून निर्वाचन क्षेत्र से जोड़ती है। इस सड़क को देख कर भी यकीन नहीं होता है कि यहां पर भी कभी

पक्की सड़क रही होगी, इतनी बुरी हालत इस सड़क की है। जब से यह सरकार बनी है मैं सुन रहा था कुछ हमारे विधायक मित्र कह रहे थे कि मिट्टी से विभाग गड्ढे भर देता है। इस तरह से सड़कों को दुरूस्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस सड़क के अन्दर तो गड्ढों में भी मिट्टी तक नहीं बिछाई गई है। काफी दुर्घटनाएं इस सड़क की दुर्दशा के कारण हो चुकी है। उसके बाद धर्मपुर से कुनिहार वाया सुबाथू, इस सड़क की हालत भी बहुत खराब है। धर्मपुर से सुबाथू वाया कंडा इस सड़क की हालत भी बहुत नाजुक है। भोजनगर से परवाणू वाया चक्की का मोड़ और सोलन से कुनिहार वाया सुबाथू, ये जितनी भी सड़कें मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर है अगर उनकी हालत हम जा करके देखें और वह देखने पर ही मालूम होगा। अभी हमारे विधायक मित्र चर्चा कर रहे थे कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी आते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत कम आते हैं। मुझे याद है वे एक ही बार मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आए हैं। एक ही जगह से उन्होंने कुछ भवनों का एलान किया। एक बार को छोड़ करके उसके बाद उनका मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आना नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, यह भी बड़ी चिन्ता का विषय है कि वर्ष 2012 के बाद हमने विधायक प्राथमिकता में सड़कें ली हैं। मेरी एक भी प्राथमिकता के ऊपर काम नहीं हुआ। उनके डी0पी0आर0 व एस्टिमेट्स तैयार नहीं हुए। आज हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर सिर्फ उन्हीं सड़कों के काम चले हुए हैं जो हमारे पूर्व मुख्य मंत्री हैं और जिनको हम सड़कों वाला मुख्य मंत्री भी कहते हैं, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी के समय में जो हमारे क्षेत्रों में सड़कें स्वीकृत हुई और वह जो कार्यकाल था उस बारे में मैं तो कहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए तो वह स्वर्णिम

28.03.2016/1815/जेएस/डीसी/2

कार्यकाल था। वहां पर अनेकों सड़कों का निर्माण हुआ। जिन सड़कों का निर्माण कार्य धूमल जी के समय में शुरू हुआ था आज हम उन सड़कों की स्थिति देखें तो बड़ा ढीला काम उन सड़कों का चला हुआ है। इसके ऊपर सरकार को जरूर विचार करने की आवश्यकता है। सम्माननीय भारद्वाज जी कह रहे थे कि केबल्ज बिछाने के लिए कभी थ्री जी, कभी फोर जी और कभी फाईव जी आएगा। केबल्ज बिछेंगी तो उससे सड़कें डैमेज होती हैं। मैं भी जब अपने निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण कर रहा था तो मैं देख रहा था कि ज्यादातर हमारे रोड़ज की स्थिति केबल्ज बिछाने से खराब हो रही है। जब हम उस

तरफ बैठते थे तब भी इसके ऊपर चर्चा होती थी लेकिन इसमें कुछ ठोस आज तक हो नहीं पाया है। क्या ऐसा कोई फैसला नहीं हो सकता है कि कोई परमानैंट ट्रैंच, पक्की एक ड्रेन उसके साथ-साथ एक सीमैंटिड ट्रैंच बना दें जिसके कुछ-कुछ स्थान के बाद ओपनिंग हो। उसके अन्दर ही केबल्ज बिछाई जाएं। जहां यात्रियों को असुविधा होती है वहीं दुर्घटनाओं के चांसिज भी बार-बार इन सड़कों की खुदाई से बढ़ जाते हैं और सड़कों की स्थिति खराब हो जाती है। बी0एस0एन0एल0 या दूसरे जो भी केबल्ज बिछाते हैं और वे जब विभाग को पैसा देते हैं वह पैसा वहां पर नहीं लगता है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ एक बार मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर जिस प्रकार से सड़कों की स्थिति खराब है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

28.03.2016/1815/जेएस/डीसी/3

अध्यक्षः अब अन्तिम वक्ता श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी मांग नम्बर-10 पर चर्चा करेंगे।

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मांग नम्बर-10 लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन पर कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व जो हमारे वरिष्ठ विधायक हैं इस पर सभी ने विस्तार से चर्चा की कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों की दशा क्या है और उनके निर्वाचन क्षेत्र में क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो मेरी अपनी असैसमैंट पिछले तीन सालों की है कि हिमाचल प्रदेश में जो सड़कों की स्थिति हैं वह इंडिया में किसी भी स्टेट से बद्तर हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

28.03.2016/1820/SS-AG/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर क्रमागतः

मेरे लिए इससे ज्यादा दुख की कोई बात नहीं हो सकती। जैसे बोला गया कि सड़कें

भाग्य रेखाएं होती हैं और मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट की डिवैल्पमैंट को देखने का मेज़र पैरामीटर यह है कि सड़कों की स्थिति क्या है, कितनी नई सड़कें बन रही हैं, जो पहले की सड़कें बनी हैं वे कैसे मैंटेन हैं। अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हिमाचल पूरे देश में सबसे पीछे आयेगा। सबसे बड़ी दुख की बात यह है जो मैं बार-बार कहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप भी पिछली बार नालागढ़ गये थे, लेकिन आपने एन0एच0-21 - नालागढ़ लेकर स्वारघाट तक का कोई ज़िक्र नहीं किया। लोग उसके बारे में आपसे मिले थे और आपने कहा था कि देखेंगे। बड़े दुख की बात है कि सैंटर गवर्नमैंट से पूरे फंडस आ गए हैं लेकिन उसका काम नहीं हुआ। लैंड एक्विजिशन हालांकि as per DPR स्टेट गवर्नमैंट की जिम्मेदारी थी कि वह उसने पे करना था। फिर भी as a special case डी0पी0आर0 चीफ इंजीनियर ने बनाई थी और दिल्ली भेजी। मैंने दो-तीन बार मंत्रालय में जाकर मैटर परश्यु किया तो इसकी डी0पी0आर0 में लैंड एक्विजिशन के लिए जितना पैसा मांगा था, वह पूरा 14.93 करोड़ सैंक्शन करवा दिया। उसको सैंक्शन हुए लगभग एक साल से ऊपर हो गया है। जनवरी महीने में करवाया था। लेकिन इसके बावजूद न तो लैंड एक्वायर की गई और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी स्पीड न के बराबर है तथा जितना काम हो रहा है उसकी क्वालिटी में वही बात है जैसा कि बाकी लिंक रोड में होता है। सड़कें बनती हैं और साथ-साथ महीने या बीस दिन में टूट जाती हैं। हमें लोगों को फेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पूरा पैसा आने के बावजूद काम नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने सारे डैमोक्रेटिक स्टैप्स उठाकर देख लिये। हमने धरने प्रदर्शन किये, पूरे फंडस भी सैंटर से ले आए, विधान सभा में बार-बार बोला। Even self-immolation के लिए मैंने इसी सदन से बोला था परन्तु उसके लिए लोगों ने मना कर दिया। क्योंकि यह काम उन लोगों को करना चाहिए जो पूरा पैसा होने के बावजूद भी इस काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने वह विदड्रा किया। अब हम लास्ट में पी0आई0एल0 करने जा रहे हैं। उसमें हम एक और डिमांड करने जा रहे हैं, उसकी एक कॉपी सैंटर गवर्नमैंट को कर रहे हैं कि लगभग पिछले तीन साल से जो मेजर काम होना था, जो अफसर लगातार वहां पर पिछले तीन साल से पोस्टिड हैं उनकी दो मुद्दों पर

28.03.2016/1820/SS-AG/2

सी0बी0आई0 इंक्वायरी होनी चाहिए। नम्बर एक, एब्नॉर्मल डिले क्यों हुई। नम्बर-दो,

बिलो स्पैसिफिक वर्क क्यों करवाया जा रहा है। इन दो मुद्दों पर यह मामला बहुत सीरियस है। मैंने आज नोटिस भेज दिया है। डिपार्टमैंट को एक-डेढ़ महीने का टाइम दिया है अगर हमें लगा कि डिपार्टमैंट इस इश्यु के बारे में सीरियस नहीं है तो पी0आई0एल0 ऑनरेबल हाई कोर्ट में कर दी जायेगी और बड़े दुख से करनी पड़ेगी क्योंकि हम हर स्टैप में फेल हो चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन है कि इसमें पसर्नल इंट्रस्ट लेकर काम करवाया जाए। नालागढ़ के लोग इतने दुखी हो चुके हैं कि उनका सरकार से विश्वास उठ चुका है। उस विश्वास को बहाल करने के लिए काम किया जाए। उसका आपको भी फायदा होगा और हमें भी होगा। आपका डेढ़ साल जो बचा है उसमें अगर सड़क बन जाए तो ठीक रहेगा ताकि हम भी जनता के बीच में जा सकें। अन्यथा न तो लोग आपको नालागढ़ में घुसने देंगे और न ही हमें, इसके लिए मैं आपको इस सदन के माध्यम से आज चेतावनी देना चाहता हूं। लैंड एक्विजिशन का एक नया ही काम शुरू कर दिया है। अब क्या किया जा रहा है? कहते हैं कि उतनी लैंड एक्वायर करनी है जितनी ब्लैक टॉप विडथ होगी। आज तक इंडिया में कहीं भी नेशनल हाईवे के लिए ऐसा नहीं किया गया। वे कहते हैं कि पैसे कम हैं। मैंने सैंट्रल मिनिस्ट्री में भी बात की है वे कहते हैं कि अगर पैसे कम हैं तो और डी0पी0आर0 भेज दें। डी0पी0आर0 पहले ही पूरी भेजनी चाहिए थी। पीसमील में क्यों भेजी? फिर भी वे एग्री कर रहे हैं कि अगर पैसा कम है तो और पैसे के लिए केस भेज दें। परन्तु जो नेशनल हाईवेज़ के नॉर्म्ज़ हैं in plain terrain that is between 24 to 28 mtrs उससे कम नहीं करनी चाहिए अदरवाइज़ अगर हम कम एक्वायर करेंगे तो लोग उसके बियोंड कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। परमानैंट नेचर की कंस्ट्रक्शन रेज़ कर लेंगे। कल को हमने उसको और एक्सपैंड करना है, फोरलेन करना है अगर पक्की कंस्ट्रक्शन होगी तो उसके लिए हमें हैवी पेमैंट करनी होगी। अब कम-से-कम लोगों के साथ इतना तो अन्याय मत कीजिए कि उसकी जो लैंड एक्वायर करनी है वह भी सिर्फ ब्लैक टॉप करनी है। ऐसा किया जा रहा है। मैंने प्रिंसीपल सैक्रेटरी से भी बात की थी लेकिन पता नहीं उसके बाद इन्होंने क्या किया। परन्तु स्टैंडर्ड को बिल्कुल डाउन करके यानी नॉर्म्ज़ को बाईपास करके उस सड़क में काम हुआ है। ऐसा लगता है कि बड़ा कैचुअल वे से ट्रीट किया गया है। न वहां पर प्रॉपर ब्लैक टॉप विडथ है, न ड्रेन है। जहां जितनी लैंड उपलब्ध थी, उसी के

28.03.2016/1820/SS-AG/3

मुताबिक एक लिंक रोड की तरह उसे बना दिया गया। मेरा कहना है कि बहुत कम काम हुआ है। उसमें दोबारा से काम करें। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले पूरी लैंड एक्वायर करें। लैंड एक्वायर पूरी as per specification है ब्लैक टॉप की विडथ कितनी होनी चाहिए, उसके बाद ड्रेन है, ड्रेन के बाद worm है, उसके आगे भी लैंड चाहिए होती है। उस ढंग से सारा काम करें।

जारी श्रीमती के0एस0

28.03.2016/1825/KS-AG/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर जारी-----

अगर ऐसा नहीं हुआ तो पी.आई.एल. हम दायर करने जा रहे हैं और वह हमें अच्छा नहीं लगेगा। पी.आई.एल. दायर करने के बाद मुझे लगता है कि और डिले होगा तो इसकी नौबत न आए । इसके अलावा एक और मेजर बात है जो नालागढ़ कंसीच्युएंसी है, पिछले तीन साल से न तो सी.आर.एफ. की कोई डी.पी.आर. सेंक्शन हुई है न इंटर स्टेट कनैक्टिविटी की हुई है जबकि पंजाब बॉर्डर से हमारी बहुत सी सड़कें टच करती है। मेरा आग्रह है कि हमारे नालागढ़ चुनाव क्षेत्र की नौ-दस सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उनको चाहे इंटर स्टेट कनैक्टिविटी से जो बॉर्डर से टच करती है, और दूसरी जो सड़कें हैं वह सी.आर.एफ. के माध्यम से या वर्ल्ड बैंक फेज़ सैकिण्ड सेंक्शन होता है उसके माध्यम से मैक्सिम सड़कों की सैंक्शन की जाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारी सड़क है, धीरोवाल-नालागढ़- रामशहर- दिग्गल-शिमला- जुब्बड़हट्टी- शिमला इसको या तो नैशनल हाईवे डिक्लेयर करवाया जाए या सैंटर गवर्नमैंट से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो इसका मूवमैंट चला हुआ है उसके तहत जल्दी से इसकी नोटिफिकेशन करवाई जाए। इससे न केवल नालागढ़ को फायदा होगा बल्कि जो पंजाब के दो-तीन जिले है और ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर के लोग हैं, उनको भी शिमला आने के लिए कालका जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नालागढ़ से शिमला के लिए लगभग डेढ़ घण्टे का समय लगेगा इससे एक तो समय की बचत होगी दूसरे, कालका-शिमला नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का लोड कम होगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है

कि जल्दी से जल्दी इसको सेंक्शन करवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं हमारी सात-आठ सड़कों के बारे में बताना चाहता हूं जिनके बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था जैसे

1. Dherowal-Nalagarh;
2. Soban Majra-Baruna-Bagheri-Khatiwala;
3. Panoh-Barian-Alyan-Danoghat including bridge on Alyan khad;
4. Ramshehar-Doli-Nerli Road;

28.03.2016/1825/KS-AG/2

5 Tambrodu-Vaid Ka Johad-Chanoberi - Ambwala road;

5. Bhini Johri-Papler road;
6. Gujjarhatti-Purla-Kantrooghat.
7. C/o Bridge between Village Kotla and Palahi on Kundlu Khad; and
8. C/o Link Road between Ambwala-Retar-Rajwain-Jagli-Bara-Khuhi.

ये जो सड़कें हैं इनको या तो सी.आर.एफ . के माध्यम से, क्योंकि नाबार्ड की फंडिंग की कंसीच्युएंसी के लिए लिमिट होती है। हमारे यहां क्योंकि सी.आर.एफ. का पैसा इंटर स्टेट कनैक्टिविटी का और वर्ल्ड बैंक का आज तक कोई पैसा नहीं लगा तो मेरा आग्रह है कि इन तीनों में से किसी भी हैड के अगेंस्ट इसकी फंडिंग करवाई जाए। अभी भी हमने दिल्ली से पता किया, अभी भी जो सड़कें हैं, हमारी कंसीच्युएंसी की एक भी नहीं हुई है। इंटर स्टेट कनैक्टिविटी में दो -तीन हुई है उसमें हमारी एक भी नहीं है तो बड़े दुख की बात है कि नालागढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

इसके अलावा मशीनरी के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्यों ने सही

कहा कि मशीनरी के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ भेदभाव होता है। कांग्रेस के विधायकों के चुनाव क्षेत्रों में ज्यादा मशीनरी जाती है। इसके अलावा नई सड़कों का कोई काम शुरू नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के समय में धूमल जी के नेतृत्व में जो सड़कों का काम था, उन्हीं सड़कों पर काम चला हुआ है और नई जो सड़क सेंक्शन हुई भी है, उसमें अभी काम शुरू नहीं हुआ है। तो जल्दी से जल्दी यह काम शुरू करवाया जाए। इसके अलावा सभी विधायकों ने चर्चा के माध्यम से यहां पर मुद्दा उठाया था कि जो गांव में पंचायतें सड़कें बनाती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। They are quite more in numbers. होता क्या है कि हर बरसात के बाद उनको जब रीस्टोर करना होता है तो काफी समय उसमें लग जाता है। लोगों की सब्जियां होती है उनको मार्किट ले जाना होता है इसके अलावा लोग बीमार होते हैं तो हमें फंडिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। हम सभी का सुझाव था कि उसके लिए

28.03.2016/1825/KS-AG/3

एक लम्प-सम फंडिंग ब्लॉक को पी.डब्ल्यू.डी. हैड से दे दी जाए । शायद मुख्य मंत्री जी मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि गांव की जो सड़कें है, other than P.W.D. roads लिंक रोड़ जो पंचायतें बनाती हैं, वे हर बरसात में टूट जाती हैं, तो उनके लिए मेंटीनैंस फंडज़ अवेलेबल नहीं होते हैं। हम कभी एक्सिअन से रिक्वैस्ट करते हैं और हम सारे विधायक उनकी दया पर निर्भर होते हैं। तो इसके लिए मेंटीनैंस फंड्ज़ ब्लॉक को दिए जाएं ताकि ब्लॉक उन रोड्ज़ को समय पर मेंटेंन करें और टाईमली उनको खोल दें। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और शायद बजट में इसका प्रोविज़न नहीं है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है अभी जो एनुअल रीसर्फिंग कोट होगी, जो रीकार्पेटिंग होती है, पांच साल बाद उसमें क्या है कि हर बार हम करते हैं वह अभी भी शुरू हो जाएगी और

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.3.2016/1830/av/ए0एस/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर------ जारी

वह एक महीने बाद टूट जाती है जबकि यहां पर एक प्रश्न के उत्तर में उसकी लाइफ पांच साल बताई है। इसके लिए मेरा आग्रह है कि इसको 20 एम0एम0 की बजाय 40 एम0एम0 कर दिया जाए और 40 एम0एम0 नहीं तो कम-से-कम 32 एम0एम0 तो कर दिया जाए। इससे नम्बर ऑफ किलोमीटर तो कम हो जायेगी मगर जो रोड बनेगी 3-4 साल चलेगी और लोगों में एक अच्छा मेसेज जायेगा कि रोड की एनुअल रिकार्पेटिंग की है तथा चली हुई है। आजकल ट्रेफिक बहुत हो गया है इसलिए 20 एम0एम0 एक पुरानी बात हो गई है। इसको टेक्निकली रिव्यू करने की जरुरत है। वैसे तो 40 एम0एम0 डिजायरेबल है लेकिन यदि 40 एम0एम0 नहीं है तो इसको 32 एम0एम0 यानि सवा ईंच किया जाए। मगर इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पहले जो लोक निर्माण विभाग में स्टेट हैड एम0एन0पी0 होता था उसमें हर साल लगभग 40 लाख रुपये प्रति निर्वाचन क्षेत्र बजट रखा जाता है। मैंने इस बारे में पिछली बार भी बात की थी कि अगर कोई सड़क चाहे पी0एम0जी0एस0वाई0, सी0आर0एफ0 या नाबार्ड में बनानी है तो बड़ी-बड़ी डी0पी0आर0 के लिए टाइम लगता है। अगर एम0एन0पी0 में हम थोड़ा बजट बढ़ा दें तो एक-दो किलोमीटर की छोटी-छोटी सड़कें उससे बनकर तैयार हो सकती है तथा उसका लोगों को बड़ी-बड़ी सड़कों से ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि स्टेट सैक्टर में एम0एन0पी0 बजट को दो करोड़ रुपये प्रति निर्वाचन क्षेत्र किया जाये। कोई इमरजैंसी की छोटी रोड को उसके माध्यम से जल्दी बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एस0सी0पी0 में जो सड़कें आती है विभाग उसका सारा साल ऐस्टिमेट नहीं बनाता है। बार-बार कहने पर लास्ट में ऐस्टिमेट बनता है। विभाग मार्च माह के अंत में अपने हिसाब से किसी और ही स्कीम में बुकिंग कर देता है और लोगों को एस0सी0पी0 का लाभ ठीक ढंग से नहीं मिलता है। एस0सी0पी0 में जितने भी प्रोजैक्ट है उसके लिए विभाग को शुरू में ही निर्देश जाने चाहिए, चाहे वह लोक निर्माण विभाग है या सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग है। उनको शुरू में ही निर्देश जाने चाहिए कि दो-तीन महीने में ऐस्टिमेट बन जाए और उसको ऐडमिनिस्ट्रेटिव

अप्रूवल मिल जाए। साल का जितना बजट है वह लग जाए नहीं तो लास्ट में उसको किसी एक वर्क में डाल दिया जाता है। ऐसा करने से न तो फीजिकल प्रोग्रैस आती है और न ही जिसके लिए वह पैसा दिया जाता है उसमें ढंग से लगता है।

28.3.2016/1830/av/ए0एस/2

यह मेरा प्रैक्टिकल ऐक्सपीरियंस है और इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। डी0पी0आरज0 जो लेट बन रही है उसके लिए भी मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। विभाग में इंजीनियरिंग स्टाफ कम है। इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि डी0पी0आर0 का कार्य आउट सोर्सिंग से किया जाए ताकि डी0पी0आर0 समय पर बन जाए। जब डी0पी0आर0 बनती है उसकी अप्रूवल का प्रोसैस उसके बाद ही शुरू होता है। मगर हम डी0पी0आर0 स्टेज पर ही बहुत लेट हो जाते हैं। अतः मैं कहना चाहूंगा कि डी0पी0आर0 का सारा कार्य आउट सोर्सिंग के माध्यम से किया जाए। इस बारे में सभी विधायकों की शिकायत रहती है और इससे बड़ा फायदा मिलेगा। जो लोक निर्माण विभाग में मैंटीनैंस फंड आता है वह ठीक ढंग से नहीं लगाया जाता। उसको केजुअल वे में लगाया जाता है, उसके लिए कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं की जाती कि पैसा कहां लगाया गया। मैंटीनैंस फंड का व्यय रोड की कंडिशन्ज को सुधारने के लिए करना चाहिए। यहां पर शिलाई के विधायक ने भी कुछ नाम दिए हैं जिनमें कठवार, कोडगा, सखोली, पोका, बडवास, मुईनल बाग, कोटी उतरऊ, पंदयार, बाली कोटी इत्यादि हैं। इन सड़कों के बहुत बुरे हाल है। इनका कहना है कि ये सड़कें बन चुकी हैं। अगर इनकी पासिंग हो जाए तो इस पर ट्रैफिक चल सकता है। इसके अतिरिक्त एन0एच0 72 की हालत बहुत खराब है। पूरे प्रदेश में ही सड़कों की हालत खराब है इसमें चाहे शिलाई हो या नालागढ़ हो। नालागढ़ का जो प्लेन टैरेन है वहां रोड बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 60 प्रतिशत प्लेन टैरेन पड़ता है और 40 प्रतिशत पहाड़ पड़ता है। प्लेन में भी हमारी सड़कों का बहुत बुरा हाल है। खासकर एन0एच021-ए0 आजकल इसका नया नाम 105 है। मेरी सूचना के मुताबिक ठेकेदार कोर्ट में चला गया है और उसने स्टे ले ली। अब दो-चार दिन पहले स्टे वेकेट हो गई है मगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए एक तो वहां पर जो तीन साल से ऑफिसर बैठे हुए हैं, मैंने इसके बारे में पी0आई0एल0 में भी लिखा है। उनमें दम नहीं है और न ही वे काम करवा सकते हैं। उनको वहां से एकदम स्थानांतरित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए कि काम में देरी क्यों हुई।

फंडिंग होने के बावजूद देरी क्यों हुई और बिलो स्पैसिफिकेशन वर्क क्यों करवाया गया? ये सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहता था बाकी इसमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है।अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

मुख्य मंत्री का जवाब टीसी द्वारा जारी

28.03.2016/1835/TCV/AS/1

अध्यक्षः मांग संख्याः 10 पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भाग लिया और विस्तृत रूप से उन्होंने अपनी बात रखी है। अब माननीय मुख्य मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्ता है कि मांग संख्याः 10 जो लोक निर्माण विभाग से संबंधित है इसके बारे में काफी माननीय सदस्यों ने कटमोशन्ज दिए और अपने विचार रखे हैं। निःसंदेह हिमाचल प्रदेश के अन्दर सड़कों का जाल बिछा है। एक समय था जबकि सारे प्रदेश के अन्दर कुछ मुट्ठी भर सड़कें थी, आज लगभग 34 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कें प्रदेश के अन्दर बनी हैं। सड़कों का विस्तार हुआ है और यह भी सही है कि सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं जैसे डॉ0 यशवंत सिंह परमार अकसर कहा करते थे। सड़कों के माध्यम से ही न केवल यातायात सुविधा होती है बल्कि विकास भी सड़कों के माध्यम से ही होता है। आज इस कटमौशन में जिन माननीय विधायकों ने भाग लिया, उनका एक ही कहना था कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर सड़कों के बहुत बुरे हाल हैं। अगर आपकी मानी जाये तो सारी सड़कें गड्ढों से भरी हुई है और आने-जाने के काबिल नहीं है जिसके कारण जनता को बहुत असुविधा हो रही है। मैं भी सड़कों से काफी जाता हूं। जब मैं डिस्ट्रिक्ट का टूअर करता हूं तो मैं सड़कों से ही करता हूं । मैं यह कहना चाहूंगा कि हिमाचल में जो मुख्य सड़कें हैं बल्कि हर जिले के अन्दर जो मुख्य सड़कें हैं वह अच्छी है। इतनी खराब नहीं है जो आप दर्शाना चाहते हैं। माननीय विधायक कह रहे हैं कि हमीरपुर जिले की सड़कें खराब है। मैं कहना चाहता हूं कि हमीरपुर की सड़कें हिमाचल प्रदेश के अन्दर सबसे अच्छी सड़कें हैं। ऊना जिला के अन्दर देखिए Network of roads is the finest in the Himachal Pradesh. बीच में कोई एक-आध सड़क हो सकती है वह भी सुधर रही है। कांगड़ा जिले के अन्दर अगर हम देखें जो मैन रोड हैं they are in a very good condition और सड़कें काफी चौड़ी

है और ज्यादा चौड़ी की जा रही है। नये पुल बन रहे हैं जब सड़क चौड़ी होगी तो पुल भी डबल लेन-3 लेन और 4 लेन के बनेंगे। हो सकता है जो कुछ गांव/इंटिरियर एरिया की सड़कें हैं, उनमें मरम्मत की जरूरत हों मगर by and large they are in good condition. We should not run down the Department like that. और ये एक प्रोपागण्डा/

28.03.2016/1835/TCV/AS/2

माहौल पैदा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है। यह ठीक है कि आजकल मण्डी-नेरचौक से कुल्लू तक हमारी सड़कों की फोरलेनिंग हो रही है और कुल्लू से मनाली टू लेन बन रही हैं। मगर उसके कारण कुछ खलबल मची है क्योंकि जो पुरानी सड़क हैं वह मैंटेंन नहीं हो रही है और जो नई फोरलेन है वह बड़ी तेजी के साथ बन रही है।

श्री आर0आर0के0एस0 ----- द्वारा जारी।

28.03.2016/1840/RKS/DC/1

मुख्य मंत्री...जारी

It is one of the best roads. जब बनकर तैयार होगी one of the best roads. कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से कुछ अड़चनें पैदा हुई हैं। इसी तरह से हाईवेज को स्टेट गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है। कालका से लेकर शिमला तक फोर लेनिंग हो रही है। बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है। मैं सिरमौर के बारे में कह रहा हूं। बिंदल साहिब सिरमौर के बारे में कुछ कह रहे थे। नाहन की सड़क बहुत अच्छी है। कुमारहट्टी से लेकर नाहन तक is one of the best roads. नाहन से पांवटा साहिब का रोड़ ठीक है। वहां से जो शिलाई बगैरा को सड़क जा रही है वह नेशलन हाईवे बन गया है और तेजी से उसका काम हो रहा है। वह सड़क चौड़ी हो रही है। कहीं-कहीं अस्थायी समस्या पैदा होती है। जहां पर कटाई हो रही है, सड़क चौड़ी हो रही है उसकी वजह से कुछ यातायात अवरूद्ध होता है। यह कहना कि सड़कों की टारिंग नहीं हो रही है, मरम्मत नहीं हो रही है, मिट्टी डालकर गड्ढे भरे जा रहे हैं। This can be exception, not as a Rule. मैं रूल

आउट नहीं करता। कोई ऐसी सड़कें होंगी जो ठीक तरह से रूल्ज के मुताबिक मेंटेन नहीं हुई होंगी। मगर the exception cannot be quoted as a defect यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आज पुरानी सड़कों को मेंटेन करना है, आज नई-नई सड़कें बन रही हैं, नये इलाकों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जहां आज तक सड़कें नहीं पहुंची वहां आज सड़कें पहुंचाई जा रही है। कच्ची सड़कों को पक्का किया जा रहा है, यह सब काम हो रहा है। मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि कई जगह है जहां पर लैप्सिज होते हैं। लोक निर्माण विभाग बहुत बड़ा विभाग है। कई जगह बहुत अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। कई जगह जो ऑफिसर्ज लगते हैं, मुलाज़म लगते हैं उनमें कोई कमी रहती हैं तो सड़क के रख-रखाव में भी कमी रहती है। I accept it. इसके बारे में विभाग को और चुस्त-दरुस्त करने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी स्ट्रीक्ट मोनिटरिंग हैं और इससे ज्यादा भी स्ट्रीक्ट मोनिटरिंग की जाएगी कि सड़कें ठीक से बनें। स्पेस्फिकेशन के बाद जो नई सड़कें बन रही हैं वह स्पेस्फिकेशन के मुताबिक बनें। इसी तरह से जहां पर रिपेयर हो रही है या रिटारिंग

28.03.2016/1840/RKS/DC/2

हो रही है वह ठीक तरह से हो। बिचुमन ठीक तरह से पडें, अच्छी क्वालिटी का बिचुमन पड़ें। उसकी जो लेयर की थीकनैस है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। ताकि जो बड़े-बड़े लोड वेयरिंग ट्रक्स जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा माल को ढोते हैं ऐसी सड़कों के लिए सड़क को और ज्यादा मजबूत करना आवश्यक है। अभी स्पेस्फिकली यहां पर कुछ बातें रखी गई। श्री रिखी राम कौंडल जी क्या यहां पर बैठे हुए हैं? अभी थोड़ी देर पहले आप स्पीकर साहिब के कमरे में टी.वी. में यहां की प्रोसिडिंग देख रहे थे। आपने बागछाल पुल के बारे में जिक्र किया। आप जानते हैं कि उस क्षेत्र के लोगों की बहुत मांग रही है कि वहां पर पुल बनें। क्योंकि वहां पर अगर पुल हो तो वे एकदम से स्वारघाट पहुंच जाएंगे

श्री एस.एल.एस द्वारा ....जारी

28.03.2016/1845/SLS-DC-1

माननीय मुख्य मंत्री ...जारी

वरन् उनको बिलासपुर होकर वहां तक जाना पड़ता है। उसको ध्यान में रखते हुए काफी समय पहले हमारी सरकार ने वहां पर पुल मंजूर किया और उसके लिए अप्रोच रोड बनाया। उसका काम करने वाली भी कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं थी। गैमन्ज, जो कि बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी मानी जाती है, उसको उस पुल का ठेका दिया गया था। मगर उनकी तरफ से कोई टैक्निकल फलॉ रहा जिसकी वजह से पुल का एक पाया हार्ड रौक के ऊपर नहीं पहुंच पाया। उसकी वजह वह काम बंद हुआ। उस पुल के ऊपर काम बिल्कुल बंद कर दिया गया था और ऐसा लगता था as if the bridge has been abandoned. जब फिर से हमारी सरकार आई, हमने फिर से गैमन्ज से बात की और अब हमने वहां पर एक डॉ० रैणा, जो इंटरनेशनल कंसलटैंट फॉर गैमन्ज इंडिया हैं, उनसे राय ली है कि यह पुल कैसे बन सकता है। उसी स्थान पर बन सकता है या किसी और स्थान पर, इसकी कंसलटैंसी ली है और इस बात का पता जल्दी ही लग जाएगा। उम्मीद यह की जा रही है कि उसी जगह पर कुछ और काम करके पुल बन सकता है। वह बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बन सकेगा we will abandon this bridge. हम उसको छोड़ देंगे और उसके बगल में निकटतम स्थान पर नए पुल का निर्माण किया जाएगा। मगर इसमें देर बहुत लग चुकी है। आज से कई वर्ष पहले उसका काम शुरू हुआ था मगर बीच में, जैसे मैंने कहा है, उन कारणों से उसका काम रुक गया। मैं समझता हूं कि यह पुल बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि यह एक बहुत बड़ी पापुलेशन को सर्व करता है। इसके लिए जितने चिंतित हमारे श्री रिखी राम कौंडल जी हैं उतनी ही चिंतित सरकार भी है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी हूं। मैं चाहता हूं कि यह पुल जल्दी-से-जल्दी बन जाए।

इसी तरह से श्री महेन्द्र सिंह जी ने एक प्वायंट रेज किया regarding reduction in budget for Mandi Zone. If required for CRF works in Mandi Zone, budgetary

allocation will be made in supplementary grants. CRF works are in progress as under:-

28.03.2016/1845/SLS-DC-2

1. The amount of Rs. 33 crores is sanctioned against CRF work of Baroti, Rakhera and Maddi-Kamla Road, out of which Rs.15.08 crores has already been spent.

2. And on Joginder Nagar-Sarkaghat Road 81% of the CRF work has been completed. The amount of Rs. 11.45 crores is spent.

3. Awadevi, Tihra, Gaddidhar and Sandhol roads the amount of Rs. 13 crores is sanctioned, out of which 80% of the amount is spent.

मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी जोन से बजट काटने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। Because total expenditure on the PWD for roads and maintenance etc. is increasing not decreasing और हर जोन को, हर क्षेत्र को, जो भी वहां की स्कीमें हैं, उनके अनुसार बजटरी एलोकेशन होती है। हम चाहते हैं कि हिमाचल में जहां कहीं भी काम हो रहा है; वह चाहे सड़क का हो, पुल का हो या इरिगेशन का हो या और हो, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध हो ताकि जल्दी-से-जल्दी उसको पूरा किया जा सके। इसलिए आपका यह कहना कि आपके जोन को पैसा कम दिया गया है, वह सही नहीं है।

इसी तरह से डॉ० बिन्दल जी ने

जारी ...गर्ग जी

28/03/2016/1850/RG/AG/1

मुख्य मंत्री----क्रमागत

कोलार-बिलासपुर सड़क के बारे में जिक्र किया। मैं कहना चाहूंगा कि यह सड़क मंजूर कर दी गई है by Government of India under inter-State connectivity for Rs. 13.82 crores. Three number bridges और इसमें सैंक्शन हुए हैं और उनकी डी.पी.आर्ज. पी.एम.जी.एस.वाई. को भेजी गई हैं और जिनके लिए 6.50 करोड़ रुपये भी बजट में हमको इसके लिए प्राप्त होंगे। तो यह काम चालू है और मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी ही बनकर तैयार होगा। एक यह भी सजेस्ट किया गया था कि लोक निर्माण विभाग में एक क्वालिटी विंग होना चाहिए। I fully agree with it. There had to be a Quality Wing which will see कि कंस्ट्रक्शन के काम में क्वालिटी है और मेन्टीनेंस में भी क्वालिटी है। इसको मेन्टेन करना बहुत आवश्यक है।

We have a ENC (Q&C). Three tier wing of quality checking. Seven private labs also empanelled to augment the departmental labs and assist contractors. Even NABARD and PMGSY works are being inspected by State Quality Monitors. I assure to strengthen even the monitoring of maintenance works.

So far, PMGSY is concerned, till 2015 it was 100 per cent centrally funded. Now, we provide 10 per cent allocation from the year 2015-2016 onwards. पहले सौ प्रतिशत सेन्टर का होता था, लेकिन अब इसमें प्रदेश सरकार को भी 10% कॉन्ट्रीब्युट करना पड़ता है।

Several old PMGSY sanctioned works in Chamba, Kullu, Mandi, Shimla and Kangra were not being tendered and the contractors were not coming forward. Government of India under PMGSY gave no escalation over the approved cost. Therefore, Himachal Pradesh Government provided Rs. 50 crores for the year 2015-2016 so that the works can be awarded to meet the additional cost. हम चाहते हैं कि केन्द्र से यदि कम भी फण्डिग आ रही हो, तो हम अपनी स्टेट की तरफ से पैसा डालकर उन स्कीम्ज को चालू करें और उनको बनाने

के लिए प्रयास करें।

28/03/2016/1850/RG/AG/2

श्री महेन्द्र सिंह जी ने सी.आर.एफ. वर्क्ज के बारे में बात की। मैं यह कहना चाहूंगा कि sanction for the year 2016-2017, totalling Rs. 197 crores has been received.

Sanction for 2016-2017 and 2015-2016 covers all parts of the State, no majority constituencies. It covers the entire State. CRF money is reimbursed by the Government of India. Only budgetary provisioning is done by the State and after expenditure by the State the Government of India reimburses the amount spent by the State Government.

Continued by AG in English . . .

28/03/2016/1855/MS/AG/1

Chief Minister Continues . . .

For the year 2015-2016, Rs. 93 crores were reimbursed.

Shri Bikram Thakur raised issue of CRF works. In fact, the Dhaliara-Dadasiba Road, Phase -1 has been approved for Rs. 5.42 crores.

Several Members raised the issue of vacancies of posts. Sir, to strengthen the department, following posts have been filled up:

<u>Assistant Engineer - 40 have been recruited and process is still on.</u> Junior Engineer - 195 have been recruited. Junior Draughtsman - 108 have been recruited. Surveyors - 50 and Clerks - 109 have been recruited. Steno Typist - 55 have been recruited. So we are trying to see that the vacancies are filled. But vacancies keep on coming because so many people retire

every year. Our policy is that right in the beginning of the year, whatever vacancies are to occur during that year and even in first half of the next year will be recruited because it takes time for recruitment. Recruitment is done mostly by the H.P. Subordinate Services Selection Board. So, ample time must be given to select these people in time so that there is no vacuum.

Shri Ravinder Singh talked about PMGSY works. Sir, with a road length of 33000 km and over 21000 km being metalled, the periodical renewal is being done in the State of only 2000 km per year, whereas, it should be over 7000 km per year. However, in order to increase the target of renewal works, financing is a constraint.

The PMGSY roads contribute over 12000 km out of the 33000 km length. The proposal for PMGSY for Rs. 690/- crores for year 2015-2016 is likely to be approved during the year. The shelf under consideration of Government of India has proposed new roads, up gradation roads and missing bridges. That is the priority we are giving to. These are some of the points which have been raised.

28/03/2016/1855/MS/AG/2

मैं इस बात को मानता हूं कि सड़कों का रख-रखाव बहुत ही मुश्किल काम है। मगर इसको विभाग को करना अनिवार्य है और क्वालिटी वर्क होना चाहिए। अगर आज हम यह कह दें कि हम सड़क पर पड़े गड्ढों को पत्थर या मिट्टी डालकर भरेंगे तो it is not acceptable. The roads have to be maintained. We cannot tar. जो 33 हजार किलोमीटर सड़कें हैं अगर उनमें से हम 7-8 हजार किलोमीटर सड़कें हर साल टार्ड करेंगे तब जाकर 100 प्रतिशत मैंटीनैंस हो सकती है और ड्यूरेशन भी ठीक होगा। मगर हमारे पास इतने साधन नहीं हैं। सड़कें ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं और उनकी टारिंग/मैटलिंग भी हो रही है मगर उनको जल्दी-जल्दी जो रि-टारिंग करने का प्रोग्राम होना चाहिए we are not able to do that due to financial constraints. फिर भी जहां पर हो रहा है वह ठीक ढंग से होना चाहिए। I remember a time, Sir. It is not

that it happens in Congress time also. During BJP Government, I happened to be coming from Hamirpur to Shimla

Continued by AS in English . . .

28.03.2016/1900/जेएस/एएस/1
मुख्य मंत्रीः-----जारी---------

and when I reached at Ghagas and cross the bridge the road was being metalled to Namhol. The contractor was doing the job और मैंने देखा कि इतनी चमकती हुई काली सड़क मैंने आते हुए देखी। मज़े की बात यह थी कि वह आगे नम्होल तक नहीं पहुंचे थे, वे नम्होल से पीछे थे और वे आगे बढ़ रहे थे और पीछे से पी0डब्ल्यू0डी0 के ट्रक्स उसमें गड्ढे भर रहे थे। It is a fact. I don't want to mention the name of the contractor, I know that also.

अध्यक्षः 7.00 बज गए हैं। I want to extend the time with the permission of the House.

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, आप 10 मिनट तक और बढाईए। मैं उसके अन्दर-अन्दर ही खत्म कर दूंगा।

Speaker: I extend the House for 15 minutes.

मुख्य मंत्रीः होता यह है कि ठेकेदार के लिए कोई भी सरकार हो I was not alone; two vehicles with me and so many people were me बिल्कुल ब्लैक और जैसे कोई ब्लैक की हुई सड़क है। मैंने कहा कि यह सड़क काली कैसे हो गई? मुझे बताया गया कि उसमें ऑयल काला करने के लिए पड़ता है। डीज़ल या कोई दूसरा ऑयल उसमें पड़ता है। उससे सड़क काली हो जाती है। काली हो या कोई और रंग हो मगर बात यह है कि सड़क अभी तक बनी नहीं और पी0डब्ल्यू0डी0 के ट्रक्स है, रोलर्ज़ हैं वे पीछे से गड्ढे भर कर जा रहे थे। such things happened. No government wants itकभी-

कभी ऐसे कांट्रेक्टर्ज़ पैदा हो जाते हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। that is not exception, it is not the rule. मैं यह कहना चाहता हूं and our system is unable to check this thing. We must change the system which should be able to check such matters मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे नालागढ़ के माननीय विधायक, श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी ने Acquisition of land for Baddi-Nalagarh Four Lane के बारे में बात की है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि उस सड़क की फोर लेन बनाने के लिए ज़मीन एक्वायर की जा रही है। No contract of National Highway-21-A, from Nalagarh to 49 KM has been

28.03.2016/1900/जेएस/एएस/2

terminated due to non-performance by the contractor and re-tendering is being processed. Roads from 49 KM to Swarghat is progressing well and will be completed by 30.6.2016. Sanction of road from Nalagarh to Swarghat is of double lane standard, I will direct the Department to examine acquisition of land up to 20-24 meter. This is the factual postion. अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में माननीय विधायकों द्वारा अपनी कटौती प्रस्तावों के द्वारा अपने विचार रखें और सरकार का ध्यान कई महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर दिलाया। मैं उनको धन्यवाद करता हूं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

28.03.2016/1905/SS-AS/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

And the Public Works Department is under strain and we cannot expand the department too much. They are doing everything possible but yet there is rule for improvement. Every system has good and bad people or indifferent people. PWD have some very good engineers and workers, some are not so good and some may be just burden to the Department. In Government we

don't have system of 'hire and fire'. We have to carryon somehow जो अच्छा काम करते हैं वे भी और जो अच्छा काम नहीं करते हैं उनको भी तथा जो बिल्कुल नहीं करते हैं they can't be dismissed in the system. उनको भी चलाना पड़ता है। मगर इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा the monitoring system will be strengthened I will see that every work which is done is frequently examined and inspected. यहां पर एक बात कही गई थी कि कई जो इंस्पैक्टर रखे हुए हैं जोकि मोनिटर करते हैं या जो रिटायर्ड इंजीनियर्ज़ हैं वे अपना काम ठीक से नहीं करते हैं क्योंकि उनके मातहत ही आज काम कर रहे हैं It is that they are lenient to them. That is also a point, it is a point of view. Therefore, हम चाहेंगे कि पीपल चाहे रिटायर्ड हों या चाहे दूसरे हों man of integrity, who have been known for their honesty, dedication only such people are appointed as monitors to inspect these roads and I want to finish with one word Sir, which has drawn lot of attention in the past that is Theog and Rohru Road. It was a World Bank Project and originally it was when tendered it was in two parts one was Theog to Kharapthar and another from Kharapthar to Rohru. This is the second time first time the Chinese company did one work from Theog to Rohru.. Chinese Company got the work. It was World Bank funding project and that company was a subsidiary of the Government of China. They had their own problems. But I can say whatever work they did was very good and up to the mark. But it could not do more. So, it was retendered again and this time it was divided into two parts. One from Theog to

28.03.2016/1905/SS-AS/2

Kharapathar and other from Kharapathar to Rohru. I don't how different people bid for two different parts. But somehow, I don't know what their constitution was, it was ultimately given to only one company i.e. C&C

Chaddha and Chaddha. Chaddha and Chaddha used to be very reputed company once upon a time. But now they are facing serious internal administrative problems and also financial problems and they are not able to do the work with the speed which is expected. Actually this year there is hardly snowfall and mostly the traffic was opened. Even than I am not satisfied with the work done. But I can't change administratively. Much has been done and reaming has to be done by them कैसे न कैसे उनसे काम लेना है। They are facing financial problem जिसको वे एम्प्लॉय करते हैं, ठेका देते हैं, किसी काम को सब-लैट करते हैं उनको देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। and we give that money to them out of their contract money. तो यह एक प्रॉब्लम पैदा हुई है। उसको भी कुछ लोगों ने राजनीतिक तौर से भुनाने की कोशिश की है। पांच साल तक सड़क नहीं बनी यानी जब भाजपा गवर्नमैंट बड़े फैन-फेयर के साथ बनी तो उसका उद्घाटन हुआ।

जारी श्रीमती के0एस0

28.03.2016/1910/केएस/डीसी/1

मुख्य मंत्री जारी----

जब दूसरा काँट्रैक्ट हुआ है उसके बाद ही उसमें मूवमैंट आई मगर जिस तेज़ी से होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई that is due to the finical problems of that company to whom the contract was awarded. मुझे उम्मीद है कि अब काम पिकअप हो रहा है. **<u>We are monitoring it very hard and I am sure by the summer of the next year we will be able to complete the work. That is the target now.</u>** Though it should have been done much earlier क्योंकि यह इस एरिया में एक बर्निंग इश्यू रहा है इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। Mr. Speaker Sir, I am very thankful to you for giving me time. There were many other points which were raised which I have not been able to take up in my reply. **<u>I can ensure you those</u>**

issues which were raised and I have not replied to them here, I shall be writing to those Hon'ble Members about it. Thank you so much.

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य अपने-अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहेंगें?

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी घिरा-फिरा कर उत्तर देने का प्रयास किया है। पहली बात जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही कि मण्डी जोन को हमने कम राशि नहीं दी है, बजट की किताबें आपके पास है। आप 2015-16 और 2016-17 दोनों किताबों को पढ़कर देख लेना कि कम हुआ है या नहीं हुआ है। 20 करोड़ रु0 कम हुए हैं। दूसरा आपने सी.आर.एफ. की बात कही है। हमारे सम्माननीय सदस्य विक्रम जी ने चाहा था कि जब सी.आर.एफ. में कोई सड़क डालनी है तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ की उसकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा होता माननीय मुख्य मंत्री जी अपने जवाब में कह देते कि जिन-जिन सड़कों को, वे चाहे इंटर स्टेट कनैक्टिविटी में है, या प्रदेश के अंदर दूसरी सड़कें हैं, जिनको सी.आर.एफ. के लिए डी.पी.आर. बनानी है,

28.03.2016/1910/केएस/डीसी/2

उनको पहले मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्ज़ की नोटिफिकेशन की जाएगी। तीसरे, आपने एक बात पर जिसके बारे में हम सब कह रहे थे कि आपने बहुत जगह एक मुश्त राशि रखी है। जो एक मुश्त राशि है, चाहे वह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत है, चाहे विश्व बैंक के अंतर्गत है, चाहे नाबार्ड में है, इसमें एक शक की सूई घूमती है कि जब कोई भी डी.पी.आर. अप्रूव होती है, सेंक्शन होती है तो राशि उस वर्क के लिए आती है।

जब राशि उस वर्क के लिए आती है, हम चाहते थे आप पारदर्शिता बरतते और इसके साथ-साथ वर्क वाईज़ अगर आप बजट बुक में लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहना था, हमारा यह आरोप था लेकिन जो हमने इश्यूज़ उठाए हैं, उसमें से उल्टा आप हमारे ऊपर कुछ बातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने अपना कटौती प्रस्ताव दिया है, हम उसको वापिस नहीं ले रहे हैं।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री महेन्द्र सिंह, रिखी राम कौंडल, इन्द्र सिंह, विजय अग्निहोत्री, बिक्रम सिंह, जय राम ठाकुर, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह, डॉ0 राजीव बिन्दल और डॉ0 राजीव सैजल के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं।

(प्रस्ताव गिर गया)
कटौती प्रस्ताव अस्वीकार।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.3.2016/1915/av/डीसी/1

अध्यक्ष------ जारी

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या 10-लोक निर्माण : सड़क, पुल एवं भवन के अंतर्गत मु0 27,94,29,62,000/- रुपये (राजस्व) व मु0 8,75,86,56,000/- रुपये (पूंजी) की धनराशियां सम्बंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार

मांग संख्या 10 -लोक निर्माण -सड़क, पुल एवं भवन पूर्ण रूप से पारित हुई।

अगली मांगें कल शुरू करेंगे।

अब इस मान्य सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांक : 28.3.2016 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
शिमला-171004 **सचिव।**